चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित
20 नवंबर- 26 नवंबर 2017
नई दिल्ली
हर शुक्रवार को प्रकाशित
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अपने ही 'रॉ' एजेंटों को धोखा क्यों देती है सरकार ?

रॉ एजेंटों के परिवारों की चीख़ और सिसकियां

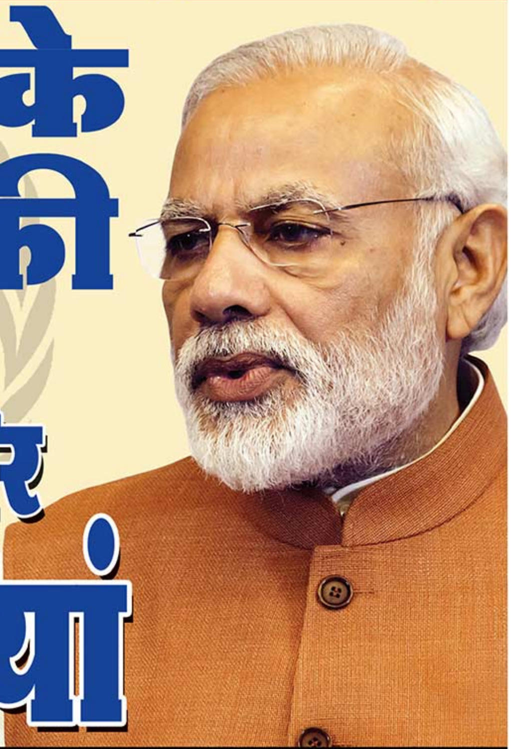

देश के युवकों को पाकिस्तान के नरक में झोंक कर भूल जाती है भारत सरकार

- ○ बची हुई जिंदगी को घसीट रहे दीक्षित जैसे अनगिनत 'रॉ' एजेंट
- ● कीमोथिरेपी से विक्षिप्त हुई पत्नी का कैसे करें इलाज!
- ○ देश पर मर-मिटने वाले जासूसों की हो रही आपराधिक उपेक्षा
- ○ 'रॉ' एजेंट्स को भारत की सरकार न नाम देती है न इनाम
- ● गुलछर्रे उड़ा रहे 'रॉ' के आला अफसर, एजेंट खींच रहे रिक्शा
- ○ पाकिस्तान की जेलों में बेमतलब की कुर्बानी दे रहे नौजवान

प्रभात रंजन दीन

छोटे से सीलन भरे कमरे से आने वाली चीख और सिसकियों की आवाजें किसकी हैं? दर्द से मुक्ति पाने की छटपटाहट के बेचैन स्वर किसके हैं? देर रात लोगों को परेशान करने वाले बेमानी शब्द-शोर से भरी पागल आवाजें किसकी हैं? किसकी सुनाई पड़ती हैं किसी बच्चे को फुसलाने जैसी कातर ध्वनियां? आप यह न समझें कि यह किसी खूंखार जेल के बंद सेल से आने वाली दुखी-प्रताड़ित कैदियों की आवाजें हैं. यह उन देशभक्तों का यथार्थ आर्तनाद है, जिन्होंने अपने देश के लिए पाकिस्तान में जासूसी करते हुए जीवन खपा दिया, लेकिन आज अपने देश में दिहाड़ी मजदूर या उससे भी गलीज हालत में हैं. उन्हें कोई 'राष्ट्रभक्त' पूछता नहीं. 'राष्ट्रभक्त' सरकार को देशभक्त जासूस की कोई चिंता नहीं. अब संकेत में नहीं, सीधी बात पर आते हैं. लखनऊ में एक शख्स मिले, जो भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड अनालिसिस विंग' ('रॉ') के जासूस थे. उन्होंने अपने बेशकीमती 21 वर्ष पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर खोमचा घसीटते हुए, मुल्ला बन कर मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए, संवेदनशील सरकारी महकमों पर महीनों नजरें रखते हुए, पाकिस्तानी सेना द्वारा पोषित आतंकियों से दोस्ती गांठते हुए, जान की परवाह न कर वहां की सूचनाएं भारत भेजते हुए और आखिर में बर्बर यातनाओं के साथ जेल काटते हुए बिताए. बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जेल से छूट कर भारत पहुंचे 'रॉ' एजेंट मनोज रंजन दीक्षित का जीवन अपने देश आकर और दुश्वार हो गया. उनकी पत्नी शोभा दीक्षित को कैंसर हो गया. कीमोथिरेपी और दुष्कर इलाज के क्रम में शोभा मां नहीं बन सकीं. वे मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गईं. रात-रात को उस छोटे से कमरे से आने वाली चीखें और सिसकियां उन्हीं की हैं. दर्द से छटपटाने की आवाजें उन्हीं की हैं. विक्षिप्तता में होने वाली हरकतें और पति को नोचने-खसोटने-मारने की आवाजें शोभा की ही हैं. पत्नी को बच्चे की तरह मनाने की कातर कोशिश करने वाले वही शख्स हैं... 'रॉ' एजेंट मनोज रंजन दीक्षित उर्फ मोहम्मद इमरान.

दीक्षित की तरह ऐसे अनगिनत देशभक्त हैं, जिनका जीवन देश के लिए जासूसी करते हुए और जान को जोखिम में डालते हुए बीत गया. जब वे अपने वतन वापस लौटे, तो अपना ही देश उन्हें भूल चुका था. सरकार को भी यह याद नहीं रहा कि भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते ही वह पाकिस्तान में प्रताड़नाएं झेल रहा था. कुलभूषण जाधव तो सुर्खियों में इसलिए हैं कि उनसे सरकार का राजनीतिक-स्वार्थ सध रहा है. यह सियासत क्या कुलभूषण के जिंदा रहने की गारंटी है? अगर गारंटी होती तो रवींद्र कौशिक, सरबजीत सिंह जैसे तमाम देशभक्त पाकिस्तान की जेलों में क्या सड़ कर मरते? फिर सरकार का उनसे क्या लेना-देना, जो देशभक्ति में खप चुके, पर आज भी जिंदा हैं! ऐसे खपे हुए देशभक्तों की लंबी फेहरिस्त है, जो अपनी बची हुई जिंदगी घसीट रहे हैं. इन्होंने देश की सेवा में खुद को मिटा दिया, पर सरकार ने उन्हें न नाम दिया न इनाम. पूर्व 'रॉ' एजेंट मनोज रंजन दीक्षित का प्रकरण सुनकर केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार बदलाव की बातें तो करती है, लेकिन विदेशों में काम कर रहे 'रॉ' एजेंट्स को स्थायी गुमनामी के अंधेरे सुरंग में धकेल देती है. विदेशों में हर पल जान जोखिम में डाले काम कर रहे अपने ही जासूसों की हिफाजत और देश में रह रहे उनके परिवार के लिए आर्थिक संरक्षण का सरकार कोई उपाय नहीं करती. जबकि देश के अंदर काम करने वाले खुफिया अधिकारियों की बाकायदा सरकारी नौकरी होती है. वेतन और पेंशन उन्हें और उनके परिवार वालों को ठोस आर्थिक संरक्षण देता है. इसके ठीक विपरीत 'रॉ' के लिए जो एजेंट्स चुने जाते हैं, सरकार उनकी मूल पहचान ही मिटा देती है. उनका मूल शिक्षा प्रमाणपत्र रख लेती है और किसी भी सरकारी या कानूनी दस्तावेज से उसका नाम हटा देती है. मनोज रंजन दीक्षित इसकी पुष्टि करते हैं. दीक्षित कहते हैं कि नजीबाबाद स्थित एमडीएस इंटर कॉलेज से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के साहू-जैन कॉलेज से उन्होंने ग्रैजुएशन किया था. 'रॉ' के लिए चुने जाने के बाद उनसे स्कूल और कॉलेज के मूल प्रमाणपत्र ले लिए गए. जब वे 21 साल बाद अपने घर लौटे, तो उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी. उन्हें बताया गया कि सरकारी मुलाजिमों का एक दस्ता वर्षों पहले उनके घर से उनकी सारी तस्वीरें ले जा चुका था. राशनकार्ड से मनोज का नाम हट चुका था. सरकारी दस्तावेजों से मनोज का नाम 'डिलीट' किया जा चुका था. भारत सरकार ऐसी घिसी-पिटी लीक पर क्यों चलती है?

(शेष पृष्ठ 2 पर)

रॉ एजेंट मनोज रंजन दीक्षित (इनसेट) की कैंसर से पीड़ित पत्नी

> “बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की जेल से छूट कर भारत पहुंचे 'रॉ' एजेंट मनोज रंजन दीक्षित का जीवन अपने देश आकर और दुश्वार हो गया. उनकी पत्नी शोभा दीक्षित को कैंसर हो गया. कीमोथिरेपी और दुष्कर इलाज के क्रम में शोभा मां नहीं बन सकीं. वे मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गईं. रात-रात को उस छोटे से कमरे से आने वाली चीख़ें और सिसकियां उन्हीं की हैं. दर्द से छटपटाने की आवाजें उन्हीं की हैं. विक्षिप्तता में होने वाली हरकतें और पति को नोचने-खसोटने-मारने की आवाजें शोभा की ही हैं...”

4 कश्मीर, वार्ताकार और दिशाहीन बातचीत

5 वंचितों को हक़ न मिला तो जल उठेगा देश : श्याम रजक

6 नोटबंदी से बेरोज़गारी बढ़ी है

7 भाजपा के लिए कठिन है 2019 की डगर

रॉ एजेंटों के परिवारों की चीख़ और सिसकियां

पृष्ठ 1 का शेष

भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी ही यह सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका, चीन, इजराइल, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कई देश अपने जासूसों की हद से आगे बढ़ कर हिफाजत करते हैं और उनके परिवारों का ख्याल रखते हैं. यहां तक कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक अपने एजेंटों को सुरक्षा कवच और आर्थिक संरक्षण देती है, लेकिन भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि सत्ता-सियासतदानों को इसमें वोट का फायदा नहीं दिखता.

वर्ष 1984 में 'रॉ' के टैलेंट हंट के जरिए चुने गए मनोज रंजन दीक्षित की अकेली आपबीती देश के युवकों को यह संदेश देने के लिए काफी है कि वे 'रॉ' जैसी खुफिया एजेंसी के लिए कभी काम नहीं करें. मेजर रवींद्र कौशिक से लेकर ऐसे तमाम 'रॉ' एजेंटों की बेमानी गुमनाम-शहादतों के उदाहरण भरे पड़े हैं. खुफिया एजेंसियों के अफसर ही यह कहते हैं कि पाकिस्तान या अन्य देशों में तैनात 'रॉ' एजेंट के प्रति आंखें मूंदने वाली सरकार भारत में रह रहे उनके परिवार वालों को लावारिस क्यों छोड़ देती है, यह बात समझ में नहीं आती. ऐसे में देश का कोई युवक 'रॉ' जैसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के बारे में क्यों सोचे? मनोज रंजन दीक्षित को 'रॉ' के टैलेंट फाइंडर जीतेंद्रनाथ सिंह परिहार ने चुना था. एक साल की ट्रेनिंग के बाद दीक्षित को जनवरी 1985 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर मोहनपुर पोस्ट से 'लॉन्च' किया गया. दीक्षित के साथ एक गाइड भी था, जो उन्हें पाकिस्तान के पल्लो गांव होते हुए बम्बावली-रावी-बेदियान नहर पार करा कर लाहौर ले गया और उन्हें वहां छोड़ कर चला गया. उसके बाद से दीक्षित का जासूसी करने का सारा रोमांच त्रासद-कथा में तब्दील होता चला गया. 23 जनवरी 1992 को सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से गिरफ्तार किए जाने तक दीक्षित ने जासूसी के तमाम पापड़ बेले. खोमचे घसीटे, लाहौर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर जैसे तमाम शहरों में आला सैन्य अफसरों से लेकर बड़े नेताओं की जासूसी की और दुबई, कुवैत, कतर, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर जैसी जगहों पर बैठे 'रॉ' अफसरों के जरिए भारत तक सूचना पहुंचाई. 'रॉ' ने हैदराबाद के आमिर आलम के जरिए दीक्षित को अफगानिस्तान भी भेजा, जहां जलालाबाद और कुनर में उन्हें अहले हदीस के चीफ शेख जमीलुर रहमान के साथ अटैच किया गया. वहां के सम्पर्कों के जरिए दीक्षित पेशावर में डेरा जमाए अरब मुजाहिदीन के सेंटर बैतुल अंसार पहुंच गए और जेहादी के रूप में ग्रुप में शामिल हो गए. दीक्षित बताते हैं कि बैतुल अंसार पर ओसामा बिन लादेन और शेख अब्दुर्रहमान जैसे आतंकी सरगना पहुंचते थे और सेंटर को काफी धन देते थे. 23 जनवरी 1992 को दीक्षित को सिंध प्रांत के हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद दीक्षित की यंत्रणा-यात्रा शुरू हुई. पहले उन्हें हैदराबाद में आईएसआई के लॉकअप में रखा गया फिर उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की 302वीं बटालियन में शिफ्ट कर दिया गया. हैदराबाद से उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की दूसरी कोर के कराची स्थित मुख्यालय भेजा गया. पूछताछ के दौरान दीक्षित को बर्बर यातनाएं दी जाती रहीं. पिटाई के अलावा उन्हें सीधा बांध कर नौ-नौ घंटे खड़ा रखा जाता था और कई-कई रात सोने नहीं दिया जाता था. करीब एक साल तक उन्हें इसी तरह अलग-अलग फौजी ठिकानों पर टॉर्चर किया जाता रहा और पूछताछ होती रही. इस दरम्यान दीक्षित के हबीब बैंक के हैदराबाद और मुल्तान ब्रांच के अकाउंट भी जब्त कर लिए गए और उसमें जमा होने वाले धन के स्रोतों की गहराई से छानबीन की गई. 21 दिसम्बर को उन्हें कराची जेल शिफ्ट कर दिया गया. पांच महीने बाद जून 1993 से दीक्षित पर पाकिस्तानी सेना की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और उन्हें कराची जेल से 85वीं एसएंडटी कोर (सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कोर) को हैंड-ओवर कर दिया गया. इस दरम्यान दीक्षित को पाक सेना की 44वीं फ्रंटियर फोर्स (एफएफ) के क्वार्टर-गार्ड में बंद रखा गया. वर्ष 1994 में दीक्षित 21वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के हवाले हुए और उन्हें 51-लांसर्स के क्वार्टर-गार्ड में शिफ्ट किया गया. इस बीच मेजर नसीम खान, मेजर सलीम खान, लेफ्टिनेंट कर्नल हमीदुल्ला खान और ब्रिगेडियर रुस्तम दारा की फौजी अदालतों में मुकदमा (कोर्ट मार्शल) चलता रहा. दीक्षित कहते हैं कि कोई कबूलदारी और सबूत न होने के कारण पाकिस्तान सेना ने उन्हें सिंध सरकार के सिविल प्रशासन के हवाले कर दिया. सिंध सरकार ने वर्ष 2001 में ही दीक्षित को भारत वापस (शेष पृष्ठ 3 पर)

> **पाकिस्तान में मिशन पूरा कर या जेल की सजा काट कर वापस लौटे कई 'रॉ' एजेंटों ने केंद्र सरकार से औपचारिक तौर पर आर्थिक संरक्षण देने की गुहार लगाई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई. यहां तक कि भारत सरकार ने उन्हें सरकारी कर्मचारी मानने से ही इन्कार कर दिया. सरकार ने अपने पूर्व 'रॉ' एजेंटों को पहचाना ही नहीं. ऐसे ही 'रॉ' एजेंटों में गुरदासपुर के खैरा कलां गांव के रहने वाले करामत राही शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 1980 में पाकिस्तान 'लॉन्च' किया गया था.**

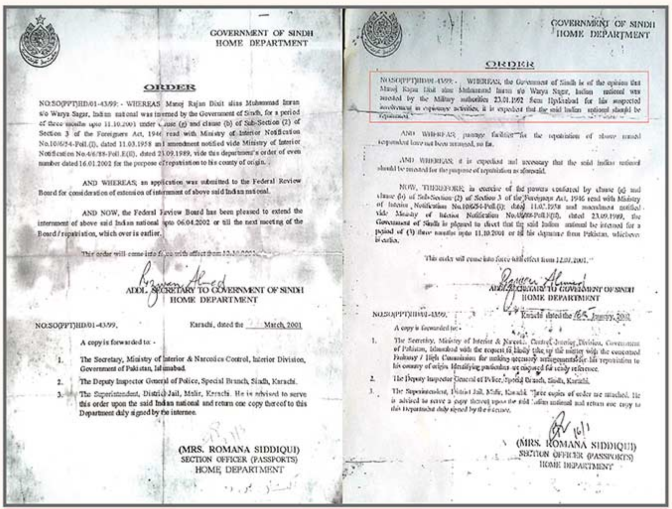

GOVERNMENT OF SINDH
HOME DEPARTMENT

ORDER

NO.SO(PPT)HD/01-43/99: - WHEREAS Manoj Rajan Dixit alias Muhammad Imran s/o Warya Sagar, Indian national was interned by the Government of Sindh, for a period of three months upto 11.10.2001 under clause (g) and clause (b) of Sub-Section (2) of Section 3 of the Foreigners Act, 1946 read with Ministry of Interior Notification No.10/6/54-Poll.(I), dated 11.03.1958 and amendment notified vide Ministry of Interior Notification No.4/6/88-Poll.E(II), dated 21.09.1989, vide this department's order of even number dated 16.01.2002 for the purpose of repatriation to his county of origin.

AND WHEREAS, an application was submitted to the Federal Review Board for consideration of extension of internment of above said Indian national.

AND NOW, the Federal Review Board has been pleased to extend the internment of above said Indian national upto 06.04.2002 or till the next meeting of the Board/repatriation, which ever is earlier.

This order will come into force with effect from [illegible]

Rizwan Ahmed
ADDL. SECRETARY TO GOVERNMENT OF SINDH
HOME DEPARTMENT

NO.SO(PPT)HD/01-43/99, Karachi, dated the ___ March, 2001

A copy is forwarded to: -

1. The Secretary, Ministry of Interior & Narcotics Control, Interior Division, Government of Pakistan, Islamabad.
2. The Deputy Inspector General of Police, Special Branch, Sindh, Karachi.
3. The Superintendent, District Jail, Malir, Karachi. He is advised to serve this order upon the said Indian national and return one copy thereof to this Department duly signed by the internee.

(MRS. ROMANA SIDDIQUI)
SECTION OFFICER (PASSPORTS)
HOME DEPARTMENT

GOVERNMENT OF SINDH
HOME DEPARTMENT

ORDER

NO.SO(PPT)HD/01-43/99: - WHEREAS, the Government of Sindh is of the opinion that Manoj Rajan Dixit alias Muhammad Imran s/o Warya Sagar, Indian national was arrested by the Military authorities 23.01.1992 from Hyderabad for his suspected involvement in espionage activities, it is expedient that the said Indian national should be repatriated.

AND WHEREAS, passage facilities for the repatriation of above named respondent have not been arranged, so far.

AND WHEREAS, it is expedient and necessary that the said Indian national should be interned for the purpose of repatriation as aforesaid.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (g) and clause (b) of Sub-Section (2) of Section 3 of the Foreigners Act, 1946 read with Ministry of Interior Notification No.10/6/54-Poll.(I); dated 11.03.1958 and amendment notified vide Ministry of Interior Notification No.4/6/88-Poll.E(II), dated 21.09.1989, the Government of Sindh is pleased to direct that the said Indian national be interned for a period of (3) three months upto 11.10.2001 or till his departure from Pakistan, whichever is earlier.

This order will come into force with effect from 12.01.2001.

ADDL. SECRETARY TO GOVERNMENT OF SINDH
HOME DEPARTMENT

NO.SO(PPT)HD/01-43/99, Karachi dated the 16th January, 2002

A copy is forwarded to: -

1. The Secretary, Ministry of Interior & Narcotics Control, Interior Division, Government of Pakistan, Islamabad with the request to kindly take up the matter with the concerned Embassy / High Commission for making necessary arrangements for his repatriation to his country of origin. Identifying particulars are enclosed for ready reference.
2. The Deputy Inspector General of Police, Special Branch, Sindh, Karachi.
3. The Superintendent, District Jail, Malir, Karachi. Three copies of order are attached. He is advised to serve a copy thereof upon the said Indian national and return one copy to this Department duly signed by the internee.

16/1
(MRS. ROMANA SIDDIQUI)
SECTION OFFICER (PASSPORTS)
HOME DEPARTMENT

पाकिस्तान की सिंध सरकार के ये दस्तावेज ही अब दीक्षित के 'रॉ' एजेंट होने और पाकिस्तान में पकड़े जाने के सबूत के रूप में बचे हैं

देश के लिए पाकिस्तान की काल कोठरी में यातनाएं सहने वाले दीक्षित को देश में भी अंधेरगर्दी ही नसीब हुई

भीषण अराजकता और बदइंतज़ामी का शिकार है 'रॉ'

केंद्रीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड अनालिसिस विंग' (रॉ) में भीषण अराजकता व्याप्त है. 'रॉ' की जिम्मेदारियां (अकाउंटिबिलिटी) कानूनी प्रक्रिया के तहत तय नहीं हैं. एकमात्र प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होने के कारण 'रॉ' के अधिकारी इस विशेषाधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हैं और विदेशी एजेंसियों से मनमाने तरीके से सम्पर्क साध कर फायदा उठाते रहते हैं. 'रॉ' के अधिकारियों कर्मचारियों के काम-काज के तौर तरीकों और धन खर्च करने पर अलग से कोई निगरानी नहीं रहती, न उसकी कोई ऑडिट ही होती है. 'रॉ' के अधिकारियों की बार-बार होने वाली विदेश यात्राओं का भी कोई हिसाब नहीं लिया जाता. कौन ले इसका हिसाब? प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार छोड़ कर कोई अन्य अधिकारी 'रॉ' से कुछ पूछने या जवाब-तलब करने की हिमाकत नहीं कर सकता. 'रॉ' के अधिकारी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में बेतहाशा आते-जाते रहते हैं. लेकिन दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीकी देशों में उनकी आमद-रफ्त काफी कम होती है. जबकि इन देशों में 'रॉ' के अधिकारियों का काम ज्यादा है. 'रॉ' के अधिकारी युवकों को फंसा कर पाकिस्तान जैसे देशों में भेजते हैं और उन्हें मरने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं. प्रधानमंत्री भी 'रॉ' से यह नहीं पूछते कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे आलीशान देशों में 'रॉ' अधिकारियों की पोस्टिंग अधिक क्यों की जाती है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या अन्य दक्षिण एशियाई देशों या मध्य पूर्व के देशों में जरूरत से भी कम तैनाती क्यों है? इन देशों में 'रॉ' का कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता. लेकिन इस अराजकता के बारे में कोई पूछताछ नहीं होती. 'रॉ' में सामान्य स्तर के कर्मचारियों की होने वाली नियुक्तियों की कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है. कोई निगरानी नहीं है. 'रॉ' के कर्मचारियों का सर्वेक्षण करें, तो अधिकारियों के नाते-रिश्तेदारों की वहां भीड़ जमा है. सब अधिकारी अपने-अपने रिश्तेदारों के संरक्षण में लगे रहते हैं. तबादलों और तैनातियों पर अफसरों के हित हावी हैं. यही वजह है कि जिस खुफिया एजेंसी को सबसे अधिक पेशेवर (प्रोफेशनल) होना चाहिए था, वह सबसे अधिक लचर साबित हो रही है.

'रॉ' में सीआईए वह कुछ अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों की घुसपैठ भी गंभीर चिंता का विषय है. 'रॉ' के डायरेक्टर तक सीआईए के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं. इसी तरह एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिसे आईबी का निदेशक बनाया जा रहा था, उसके बारे में पता चला कि वह दिल्ली में तैनात महिला सीआईए अधिकारी हेदी अगस्ट के लिए काम कर रहा था. तब उसे नौकरी से जबरन रिटायर किया गया. भेद खुला कि सीआईए ही उस आईपीएस अधिकारी को आईबी का निदेशक बनाने के लिए परोक्ष रूप से लॉबिंग कर रही थी. 'रॉ' में गद्दारों की लंबी कतार लगी है. 'रॉ' के दक्षिण-पूर्वी एशिया मसलों के प्रभारी व संयुक्त सचिव स्तर के आला अफसर मेजर रविंदर सिंह का सीआईए के लिए काम करना और सीआईए की साजिश से फरार हो जाना भारत सरकार को पहले ही काफी शर्मिंदा कर चुका है. रविंदर सिंह जिस समय 'रॉ' के कवर में सीआईए के लिए क्रॉस-एजेंट के बतौर काम कर रहा था, उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. वर्ष 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद रविंदर सिंह भारत छोड़ कर भाग गया. अराजकता का चरम यह है कि उसकी फरारी के दो साल बाद नवम्बर 2006 में 'रॉ' ने एफआईआर दर्ज करने की जहमत उठाई. मेजर रविंदर सिंह की फरारी का रहस्य ढूंढ़ने में 'रॉ' को आधिकारिक तौर पर आजतक कोई सुराग नहीं मिल पाया. जबकि 'रॉ' के ही अफसर अमर भूषण ने बाद में यह रहस्य खोला कि मेजर रविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमिंदर कौर सात मई 2004 को राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमारी शर्मा के छद्म नामों से फरार हो गए थे. उनकी फरारी के लिए सीआईए ने सात अप्रैल 2004 को इन छद्म नामों से अमेरिकी पासपोर्ट जारी कराया था. इसमें रविंदर सिंह को राजपाल शर्मा के नाम से दिए गए अमेरिकी पासपोर्ट का नंबर 017384251 था. सीआईए की मदद से दोनों पहले नेपालगंज गए और वहां से काठमांडू पहुंचे. काठमांडू में अमेरिकी दूतावास में तैनात फर्स्ट सेक्रेटरी डेविड वास्ला ने उन्हें बाकायदा रिसीव किया. काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे से दोनों ने ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस की फ्लाइट (5032) पकड़ी और वाशिंगटन पहुंचे, जहां डल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईए एजेंट पैट्रिक बर्न्स ने दोनों की अगवानी की, उन्हें मैरीलैंड पहुंचाया. मैरीलैंड के एकांत आवास में रहते हुए ही फर्जी नामों से उन्हें अमेरिका के नागरिक होने के दस्तावेज दिए गए, उसके बाद से वे गायब हैं. पीएमओ ने रविंदर सिंह के बारे में पता लगाने के लिए 'रॉ' से बार-बार कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि 'रॉ' प्रधानमंत्री के तहत ही आता है. इस मसले में 'रॉ' ने कई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के निर्देशों को भी ठेंगे पर रखा. रविंदर सिंह प्रकरण खुलने पर 'रॉ' के कई अन्य अधिकारियों की भी पोल खुल जाएगी, इस वजह से 'रॉ' ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया.

विदेशी एजेंसियों के लिए क्रॉस एजेंसी करने और अपने देश से गद्दारी करने वाले ऐसे कई 'रॉ' अधिकारी हैं, जो पकड़े जाने के डर से या प्रलोभन से देश छोड़ कर भाग गए. मेजर रविंदर सिंह जैसे गद्दार अकेले नहीं हैं. 'रॉ' के संस्थापक रहे रामनाथ काव का खास सिकंदर लाल मलिक जब अमेरिका में तैनात था, तो वहीं से लापता हो गया. सिकंदर लाल मलिक का आज तक पता नहीं चला. मलिक को 'रॉ' के कई खुफिया प्लान की जानकारी थी. बांग्लादेश को मुक्त कराने की रणनीति की फाइल सिकंदर लाल मलिक के पास ही थी, जिसे उसने अमेरिका को लीक कर दिया था. मलिक की उस कार्रवाई को विदेश मामलों के विशेषज्ञ एक तरह की तख्ता पलट की कोशिश बताते हैं, जिसे इंदिरा गांधी ने अपनी बुद्धिमानी और कूटनीतिक सझ-बूझ से काबू कर लिया.

मंगोलिया के उलान बटोर और फिर इरान के खुर्रमशहर में तैनात रहे 'रॉ' अधिकारी अशोक साठे ने तो अपने देश के साथ निकृष्टता की इंतिहा ही कर दी. साठे ने खुर्रमशहर स्थित 'रॉ' के दफ्तर को ही फूंक डाला और सारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज आग के हवाले कर अमेरिका भाग गया. विदेश मंत्रालय को जानकारी है कि साठे कैलिफोर्निया में रहता है, लेकिन 'रॉ' उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया. 'रॉ' के सीनियर फील्ड अफसर एमएस सहगल का नाम भी 'रॉ' के भगोड़ुओं में अव्वल है. लंदन में तैनाती के समय ही सहगल वहां से फरार हो गया. टोकियो में भारतीय दूतावास में तैनात 'रॉ' अफसर एनवाई भास्कर सीआईए के लिए क्रॉस एजेंट का काम कर रहा था. वहीं से वह फरार हो गया. काठमांडू में सीनियर फील्ड अफसर के रूप में तैनात 'रॉ' अधिकारी बीआर बच्चर को एक खास ऑपरेशन के सिलसिले में लंदन भेजा गया, लेकिन वह वहीं से लापता हो गया. बच्चर भी क्रॉस एजेंट का काम कर रहा था. 'रॉ' मुख्यालय में पाकिस्तान डेस्क पर अंडर सेक्रेटरी के रूप में तैनात मेजर आरएस सोनी भी मेजर रविंदर सिंह की तरह पहले सेना में था, बाद में 'रॉ' में आ गया. मेजर सोनी कनाडा भाग गया. रॉ' में व्याप्त अराजकता का हाल यह है कि मेजर सोनी की फरारी के बाद भी कई महीनों तक लगातार उसके अकाउंट में उसका वेतन जाता रहा. इस्लामाबाद, बैंगकॉक, कनाडा में 'रॉ' के लिए तैनात आईपीएस अधिकारी शमशेर सिंह भी भाग कर कनाडा चला गया. इसी तरह 'रॉ' अफसर आर वाधवा भी लंदन से फरार हो गया. केवी उन्नीकृष्णन और माधुरी गुप्ता जैसे उंगलियों पर गिने जाने वाले 'रॉ' अधिकारी हैं, जिन्हें क्रॉस एजेंसी या कहें दूसरे देश के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सका. पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग में आईएफएस ग्रुप-बी अफसर के पद पर तैनात माधुरी गुप्ता पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी के साथ मिल कर भारत के ही खिलाफ जासूसी करती हुई पकड़ी गई थी. माधुरी गुप्ता को 23 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह अर्सा पहले 'रॉ' के अफसर केवी उन्नीकृष्णन को भी गिरफ्तार किया गया था. पकड़े जाने वाले 'रॉ' अफसरों की तादाद कम है, जबकि दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी की साठगांठ से देश छोड़ कर भाग जाने वाले 'रॉ' अफसरों की संख्या कहीं अधिक है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 37
20 नवंबर- 26 नवंबर 2017
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9717002199
फैक्स न. 0120-2544377

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

रॉ एजेंटों के परिवारों की चीख़ और सिसकियां

पृष्ठ 2 का शेष

भेजने (रिपैट्रिएट करने) का आदेश दे दिया था, लेकिन वह चार साल तक कानूनी चक्करों में फंसता-निकलता आखिरकार मार्च 2005 में तामील हो पाया. मनोज रंजन दीक्षित को 22 मार्च 2005 को बाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया गया. 'रॉ' के मिशन पर पाकिस्तान में 21 वर्ष बिताने वाले मनोज रंजन दीक्षित 13 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे. भारत लौटने पर भारत सरकार के एक नुमाइंदे ने उन्हें दो किश्तों में एक लाख 36 हजार रुपए दिए और उसके बाद फाइल क्लोज कर दी. पाकिस्तान की जेल से निकल कर दीक्षित भारत के अधर में फंस गए. जीने के लिए उन्हें ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी. फिलहाल वे लखनऊ की एक कंसट्रक्शन कंपनी में मामूली मुलाजिम हैं. पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कीमोथिरैपी और ऑपरेशन के बाद भी इलाज का क्रम जारी ही है. लखनऊ के ही नूर मंजिल मानसिक रोग चिकित्सालय में उनकी मानसिक विक्षिप्तता का इलाज चल रहा है. अल्पवेतन में बीमार पत्नी के साथ जिंदगी की गाड़ी खींचना दीक्षित को मुश्किलों भरा तो लगता है, लेकिन वे कहते हैं, 'पाकिस्तान की यंत्रणाएं झेल लीं, तो अपने देश की त्रासदी भी झेल ही लेंगे'. दीक्षित कभी प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री को. सारे पत्र वे अपने साथ संजो कर रखते हैं और उन्हें दिखा कर कहते हैं, 'जिस सुबह की खातिर जुग-जुग से हम सब मर-मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी..!'

'रॉ' एजेंट्स की लंबी जमातः पाकिस्तान में हुए कुर्बान, भारत ने मिटा दी पहचान

'रॉ' के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए नौसेना कमांडर कुलभूषण जाधव का पहला मामला है, जब केंद्र सरकार ने उनकी रिहाई के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक गुहार लगाई. लेकिन इसके पहले मेजर रवींद्र कौशिक से लेकर सरबजीत सिंह और सरबजीत से लेकर तमाम नाम, अनाम और गुमनाम जासूसों की हिफाजत के लिए भारत सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया. कुलभूषण जाधव का मसला ही अलग है. उन्हें तो तालिबानों ने ईरान सीमा से अगवा किया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों बेच डाला. जर्मन राजनयिक गुंटर मुलैक अंतरराष्ट्रीय फोरम पर इसे उजागर कर चुके हैं. पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद सरबजीत की रिहाई के मसले में भी सामाजिक-राजनीतिक शोर तो खूब मचा, लेकिन भारत सरकार ने कोई कारगर दबाव नहीं बनाया. आखिरकार, दूसरे पाकिस्तानी कैदियों को उकसा कर कोट लखपत जेल में ही सरबजीत सिंह की हत्या करा दी गई.

पाकिस्तान में मिशन पूरा कर या जेल की सजा काट कर वापस लौटे कई 'रॉ' एजेंटों ने केंद्र सरकार से औपचारिक तौर पर आर्थिक संरक्षण देने की गुहार लगाई है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई. यहां तक कि भारत सरकार ने उन्हें सरकारी कर्मचारी मानने से ही इन्कार कर दिया. सरकार ने अपने पूर्व 'रॉ' एजेंटों को पहचाना ही नहीं. ऐसे ही 'रॉ' एजेंटों में गुरदासपुर के खैरा कलां गांव के रहने वाले **करामत राही** शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 1980 में पाकिस्तान 'लॉन्च' किया गया था. पहली बार वे अपना मिशन पूरा कर वापस लौट आए, लेकिन 'रॉ' ने उन्हें 1983 में फिर पाकिस्तान भेज दिया. इस बार 1988 में वे मीनार-ए-पाकिस्तान के नजदीक गिरफ्तार कर लिए गए. करामत 18 साल जेल काटने के बाद वर्ष 2005 में वापस लौट पाए. करामत की रिहाई भी पंजाब के उस समय भी मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के हस्तक्षेप और अथक प्रयास से संभव हो पाई. देश वापस लौटने के बाद करामत ने 'रॉ' मुख्यालय से सम्पर्क साधा, लेकिन 'रॉ' मुख्यालय के आला अफसरों ने धमकी देकर करामत को खामोश कर दिया. भारत सरकार की इस आपराधिक अनदेखी के खिलाफ करामत ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, लेकिन अदालत भी कहां 'नीचा' सुनती है!

इन मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारें भी 'रॉ' एजेंटों के प्रति आपराधिक उपेक्षा का ही भाव रखती हैं. 'रॉ' एजेंट **कश्मीर सिंह** का मामला अपवाद की तरह सामने आया, जब 35 साल पाकिस्तानी जेल की सजा काट कर लौटने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें जमीन दी और मुआवजा दिया. वर्ष 1962 से लेकर 1966 तक कश्मीर सिंह सेना की नौकरी में थे. उसके बाद 'रॉ' ने उन्हें अपने काम के लिए चुना और पाकिस्तान 'लॉन्च' कर दिया. 1973 में वे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए. उन्हें पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में घुमाया जाता रहा और प्रताड़ित किया जाता रहा. 17 साल तक उन्हें एक एकांत सेल में बंद रखा गया. चार मार्च 2008 को वे रिहा होकर भारत आए, लेकिन इस लंबे अंतराल में कश्मीर सिंह जिंदगी से नहीं, पर उम्र से शहीद हो चुके थे.

गुरदास के डडवाईं गांव के रहने वाले **सुनील मसीह** दो फरवरी 1999 को पाकिस्तान के शकरगढ़ में गिरफ्तार किए गए थे. आठ साल के भीषण अत्याचार के बाद वर्ष 2006 में वे अत्यंत गंभीर हालत में भारत वापस लौटे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके बारे में कोई ख्याल नहीं किया. उन्हीं के गांव डडवाईं के **डैनियल उर्फ बहादुर** भी पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा 1993 में गिरफ्तार किए गए थे. चार साल की सजा काट कर वापस लौटे. पूर्व 'रॉ' एजेंट डैनियल अब रिक्शा चला कर अपना गुजारा करते हैं. पाकिस्तान की जेल में तकरीबन तीन दशक काटने के बाद छूट कर भारत आने वाले पूर्व 'रॉ' एजेंटों में **सुरजीत सिंह** का नाम भी शामिल है. 'रॉ' ने सुरजीत सिंह को वर्ष 1981 में पाकिस्तान 'लॉन्च' किया था. वे 1985 में गिरफ्तार किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई. 1989 में उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई. वर्ष 2012 में पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से सजा काटने के बाद सुरजीत रिहा हुए. सुरजीत ने भी 'रॉ' के अधिकारियों से सम्पर्क साधा, लेकिन नाकाम रहे. सुरजीत अपनी पत्नी को यह बोल कर पाकिस्तान गए थे कि वे जल्दी लौटेंगे लेकिन 1981 के गए हुए 2012 में वापस लौटे. जब लौटे तब वे 70 साल के हो चुके थे. भारत सरकार ने उनके वजूद को इन्कार कर दिया, जबकि वापस लौटने पर सुरजीत ने पूछा कि भारत सरकार ने उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा, तो वे अपनी मर्जी से पाकिस्तान कैसे और क्यों चले गए? सुरजीत मिशन के दरम्यान 85 बार पाकिस्तान गए और आए. पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाने के बाद भारतीय सेना की तरफ से उनके परिवार को हर महीने डेढ़ सौ रुपए दिए जाते थे. सुरजीत पूछते हैं कि अगर वे लावारिस ही थे, तो सेना उनके घर पैसे क्यों भेज रही थी? सुरजीत ने भी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में शरण ले रखी है.

गुरदासपुर जिले के डडवाईं गांव के ही रहने वाले **सतपाल** को वर्ष 1999 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था. तब भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध चल रहा था. पाकिस्तान में सतपाल को भीषण यातनाएं दी गईं. पाकिस्तान की जेल में ही वर्ष 2000 में उनकी मौत हो गई. विडंबना यह है कि पाकिस्तान सरकार ने सतपाल का पार्थिव शरीर भारत को सौंपने की पेशकश की, तो भारत सरकार ने शव लेने तक से मना कर दिया. सतपाल का शव लाहौर अस्पताल के शवगृह में पड़ा रहा. पंजाब में स्थानीय स्तर पर काफी बावेला मचने के बाद सतपाल का शव मंगवाया जा सका. शव पर प्रताड़ना के गहरे घाव और चोट के निशान मौजूद थे. तब भी भारत सरकार को उनकी शहादत की कीमत समझ में नहीं आई. सतपाल के बेटे सुरेंदर पाल आज भी अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. पंजाब सरकार ने सतपाल के बेटे सुरेंदर पाल को सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया, लेकिन यह आश्वासन भी ढाक के तीन पात ही साबित हुआ.

विनोद साहनी को 1977 में पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन वे जल्दी ही पाकिस्तानी तंत्र के हाथों दबोच लिए गए. उन्हें 11 साल की सजा मिली. सजा काटने के बाद विनोद 1988 में वापस लौटे. 'रॉ' ने विनोद को सरकारी नौकरी देने और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लौटने के बाद 'रॉ' ने उन्हें पहचानने से भी इन्कार कर दिया. विनोद अब जम्मू में 'पूर्व जासूस' नाम की एक संस्था चलाते हैं और तमाम पूर्व जासूसों को जोड़ने का जतन करते रहते हैं.

रामराज ने 18 साल तक भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' की सेवा की. 18 सितम्बर 2004 को उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया. करीब आठ साल जेल काटने के बाद रिहा हुए रामराज को भारत आने पर उसी खुफिया एजेंसी ने पहचानने से इन्कार कर दिया. ऐसा ही हाल **गुरबक्श राम** का भी हुआ. एक साल की ट्रेनिंग देकर उन्हें वर्ष 1988 को पाकिस्तान भेजा गया था. उनका मिशन पाकिस्तान की सैन्य युनिट के आयुध भंडार की जानकारियां हासिल करना था. मिशन पूरा कर वापस लौट रहे गुरबक्श को पाकिस्तानी सेना के गोपनीय दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें सियालकोट की गोरा जेल में रखा गया. 14 साल की सजा काट कर वर्ष 2006 में वापस अपने देश लौटे गुरबक्श को अब सरकार नहीं पहचानती. **रामप्रकाश** को प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में 'रॉ' ने वर्ष 1994 में पाकिस्तान में 'प्लांट' किया था. 13 जून 1997 को भारत वापस आते समय रामप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया. सियालकोट की जेल में नजरबंद रख कर उनसे एक साल तक पूछताछ की जाती रही. वर्ष 1998 में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई. सजा काटने के बाद सात जुलाई 2008 को उन्हें भारत भेज दिया गया. **सूरम सिंह** तो 1974 में सीमा पार करते समय ही धर लिए गए थे. उनसे भी सियालकोट की गोरा जेल में चार महीने तक पूछताछ होती रही और 13 साल सात महीने पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में प्रताड़ित होने के बाद आखिरकार वे 1988 में रिहा होकर भारत आए. **बलबीर सिंह** को 1971 में पकिस्तान भेजा गया था. 1974 में बलबीर गिरफ्तार कर लिए गए और 12 साल की जेल की सजा काटने के बाद 1986 में भारत वापस लौटे. भारत आने के बाद उन्हें जब 'रॉ' से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन 'रॉ' ने हाईकोर्ट के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं की.

'रॉ' एजेंट **देवुत** को पाकिस्तान की जेल में इतना प्रताड़ित किया गया कि वे लकवाग्रस्त हो गए. देवुत को 1990 में पाकिस्तान भेजा गया था. जेल की सजा काटने के बाद वे 23 दिसम्बर 2006 को लकवाग्रस्त हालत में रिहा हुए. लकवाग्रस्त केंद्र सरकार ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनकी पत्नी वीणा न्याय के लिए दरवाजे-दरवाजे सिर टकरा रही हैं और मत्था टेक रही हैं. 'रॉ' ने **तिलकराज** को भी पाकिस्तान 'लॉन्च' किया था, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चला. 'रॉ' ने भी पाकिस्तान में गुम हुए तिलकराज को खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. तिलकराज के वयोवृद्ध पिता रामचंद्र आज भी अपने बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं. 'रॉ' ने इसी तरह **ओमप्रकाश** को भी वर्ष 1988 में पाकिस्तान भेजा, लेकिन ओमप्रकाश का फिर कुछ पता नहीं चला. कुछ दस्तावेजों और कुछ कैदियों की खतो-किताबत से ओमप्रकाश के घर वालों को उनके पाकिस्तान की जेल में होने का सुराग मिला. इसे 'रॉ' को दिया भी गया, लेकिन 'रॉ' ने कोई रुचि नहीं ली. बाद में ओमप्रकाश ने अपने परिवार वालों को चिट्ठी भी लिखी. 14 जुलाई 2012 को लिखे गए ओमप्रकाश के पत्र के बारे में 'रॉ' को भी जानकारी दी गई, लेकिन सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया. 'रॉ' एजेंट **सुनील** भी पाकिस्तान से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा.

feedback@chauthiduniya.com

'रॉ' एजेंट सुरजीत सिंह

'रॉ एजेंट विनोद साहनी

'रॉ' एजेंट सुनील मसीह

'रॉ' एजेंट डैनियल

'रॉ' एजेंट सुरम सिंह

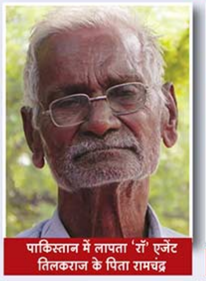
पाकिस्तान में लापता 'रॉ' एजेंट तिलकराज के पिता रामचंद्र

'रॉ' एजेंट गुरबक्श राम

'रॉ' एजेंट रामराज

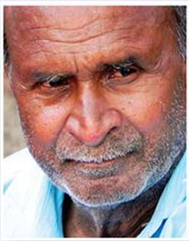
'रॉ' एजेंट रामप्रकाश

'रॉ' एजेंट करामत राही

'रॉ' एजेंट सुनील की पत्नी सीमा

'रॉ' एजेंट देवुत की पत्नी वीना

'रॉ' एजेंट सतपाल का बेटा सुरेंदर पाल

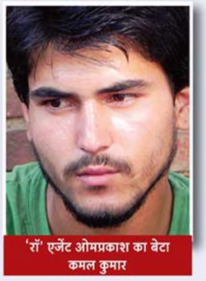
'रॉ' एजेंट ओमप्रकाश का बेटा कमल कुमार

अपने ही जासूसों के प्रति भारत सरकार की आपराधिक उपेक्षा के ये कुछ ऐसे उदाहरण और प्रमाण हैं, जो देशभक्तों के प्रति देश की सरकारों के निकृष्ट रवैये का पर्दाफाश करते हैं...

केंद्र की बेजा नीतियों और 'रॉ' की साज़िश से मारे गए कौशिक

पाकिस्तानी सेना में मेजर के ओहदे तक पहुंच गए मेजर नबी अहमद शाकिर उर्फ रवींद्र कौशिक भारत सरकार की बेजा नीतियों और खुफिया एजेंसी 'रॉ' की साजिश के कारण मारे गए. 'रॉ' के अधिकारियों ने सोचे-समझे इरादे से इनायत मसीह नाम के ऐसे 'बेवकूफ' एजेंट को पाकिस्तान भेजा, जिसने वहां जाते ही रवींद्र कौशिक का भंडाफोड़ कर दिया. कर्नल रैंक पर तरक्की पाने जा रहे रवींद्र कौशिक उर्फ मेजर नबी अहमद शाकिर गिरफ्तार कर लिए गए. 'रॉ' के सूत्र कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना में रवींद्र कौशिक को मिल रही तरक्की और भारत में मिल रही प्रशंसा (उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा गया था) से जले-भुने 'रॉ' अधिकारियों ने षडयंत्र करके कौशिक की हत्या करा दी. कौशिक को पाकिस्तान में भीषण यंत्रणाएं दी गईं. पाकिस्तान की जेल में ही उनकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई. भारत सरकार ने कौशिक के परिवार को यह पुरस्कार दिया कि रवींद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और चेतावनी दी कि रवींद्र के मामले में चुप्पी रखी जाए. रवींद्र ने जेल से अपने परिवार को कई चिट्ठियां लिखी थीं. उन चिट्ठियां में उन पर ढाए जा रहे अत्याचारों का दुखद विवरण होता था. रवींद्र ने अपने विवश पिता से पूछा था कि क्या भारत जैसे देश में कुर्बानी देने वालों को यही सिला मिलता है? राजस्थान के रहने वाले रवींद्र कौशिक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, जब 'रॉ' के तत्कालीन निदेशक ने खुद उन्हें चुना था. 1965 और 1971 के युद्ध में मार खाए पाकिस्तान के अगले षडयंत्र का पता लगाने के लिए 'रॉ' ने कौशिक को पाकिस्तान भेजा. कौशिक ने पाकिस्तान में पढ़ाई की, सेना का अफसर बना और तरक्की के पायदान चढ़ता गया. कौशिक की सूचनाएं भारतीय सुरक्षा बलों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती रहीं और पाकिस्तान के सारे षडयंत्र नाकाम होते रहे. पहलगाम में भारतीय जवानों द्वारा 50 से अधिक पाक सैनिकों का मारा जाना रवींद्र की सूचना के कारण ही संभव हो पाया. कौशिक की सेवाओं को सम्मान देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 'ब्लैक टाइगर' की उपाधि दी थी. लेकिन ऐसे सपूत को 'रॉ' ने ही साजिश करके पकड़वा दिया और अंततः उनकी दुखद मौत हो गई.

कश्मीर, वार्ताकार और दिशाहीन बातचीत

शुजात बुख़ारी

ऐसा लगता है कि कश्मीर में बातचीत की नई पहल शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई है. यदि इस पहल का मकसद उनलोगों तक पहुंचना था, जो कश्मीर में भारत की सत्ता को चुनौती देते हैं, तो यह पहल अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है. सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक और यासीन मालिक की संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार पूर्व आईबी निदेशक दिनेश्वर शर्मा से बातचीत ख़ारिज कर दी है.

शर्मा की नियुक्ति पर कई लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार कश्मीर समस्या के हल के लिए इस मार्ग की पक्षधर नहीं थी. पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सेना और अर्द्धसैनिक बलों को यहां स्थिति से निपटने की खुली छूट दे रखी है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तमाल को उचित ठहराया गया. गौरतलब है कि पैलेट गन के छर्रों की चोट से कई युवा लड़के और लड़कियों ने अपनी आंखें खो दी थीं. अब गुस्सा शांत हो गया है. अब समस्या के राजनीतिक समाधान की कोशिश होनी चाहिए.

भाजपा का खेल

जब कश्मीर के सभी पक्षों और हितधारकों से बातचीत के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिनेश्वर शर्मा के नाम की घोषणा हुई, तब इस पर घाटी में बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाई दिया. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों ने ही सरकार के इस पहल की अहमियत कम कर दी. प्रधानमंत्री कार्यालय में जूनियर मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह कहकर इस पहल पर पानी फेरने की कोशिश की कि शर्मा एक वार्ताकार नहीं, बल्कि सरकार के एक प्रतिनिधि हैं और कश्मीर कोई समस्या नहीं है.

शर्मा खुद ऐसा माहौल बनाने में नाकाम रहे, जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करता. जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्तूबर को यह घोषणा की कि नई दिल्ली बातचीत की निरंतर प्रक्रिया शुरू करेगी, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शर्मा किसी के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि दिनेश शर्मा को यह अधिकार होगा कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी हितधारक से बातचीत कर सकें. जम्मू-कश्मीर के लोगों की जायज़ मांगों को समझने के लिए वे लोगों से निरंतर बातचीत करेंगे.

जल्द ही भाजपा के कई नेताओं ने धारा 370 जैसे विवादास्पद मुद्दों को उछालकर इस प्रक्रिया पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया. उनमें से कुछ ने यह भी कहा कि हुर्रियत के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है. हालांकि उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने स्वीकार किया था कि हुर्रियत एक हितधारक है. बहरहाल, अलग-अलग हलकों से आने वाली प्रतिक्रियाओं से यह धारणा बनती है कि शर्मा की नियुक्ति सिर्फ एक नियुक्ति थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं थी. शर्मा के श्रीनगर पहुंचने से बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में आ डटे. उन्होंने पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के उस बयान का जोरदार खंडन किया, जिसमें चिदंबरम ने आजादी की तुलना स्वायत्तता से की थी. उन्होंने चिदंबरम के बयान को शर्मनाक और असंवेदनशील करार दिया था. हालांकि उनके इस बयान से उनकी मंशा ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन उससे यह धारणा ज़रूर बनती है कि नई दिल्ली उन लोगों से बातचीत करने के मूड में नहीं है, जो विरोध और असहमति के स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि समस्या के राजनीतिक समाधान का दायरा बहुत संकुचित है.

शर्मा के बयान से यह समझना मुश्किल हो गया कि जो प्रक्रिया वो शुरू करने वाले हैं, वो समस्या का राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए है भी या नहीं. उन्होंने हिंसा का रास्ता त्यागने वाले युवाओं के लिए रोज़गार की बात की और उन्हें ऐसे रास्ते से दूर हटाने की बात की, जो कश्मीर को एक और सीरिया में बदल देंगे. उनके इस बयान से ज़ाहिर होता है वे गैरज़रूरी बात कर रहे थे. तो सवाल उठता है कि क्या नए अवतार में उन्हें उनकी पिछली भूमिका के साथ भेजा गया है? श्रीनगर आने से पहले, शर्मा ने कुछ बयान दिए, जो सुलह-सफाई के लिए नियुक्त वार्ताकार के लिए बेमानी थे.

यदि कश्मीर के राजनैतिक मुद्दे पर वह एक दृढ़ और प्रो-पीपुल रुख नहीं अपनाएगी, तो वह खुद का नुकसान करेगी. चिदंबरम पर अपनी प्रतिक्रिया के मद्देनजर, कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर पॉलिसी ग्रुप के गठन के तर्क को भी समझा जाना चाहिए.

कांग्रेस की मजबूरी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने स्वायत्तता की बात की तो पार्टी ने खुद को उस बयान से अलग कर लिया. पूर्व में भी कांग्रेस इसी असमंजस की हालत में दिखी है. जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस एक सियासी ताकत है और 2021 में सत्ता में लौटने की आकांक्षा रखती है. लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह हिचकोले खाती राष्ट्रवाद के नाव में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

जब प्रधानमंत्री ने चिदंबरम के बयान की निंदा की, तब कांग्रेस प्रवक्ता ने उस बयान से पार्टी को अलग कर लिया. विडंबना यह है कि यह वही कांग्रेस है, जिसने 2010 में अपनी सरकार द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकारों की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. फ़िलहाल कांग्रेस राष्ट्रवादी होने के मामले में भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, लेकिन चिदंबरम के बयान को ख़ारिज करने का अर्थ यह है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे अपने ही नेताओं को ख़ारिज करना, जिन्होंने क्रमश: 1952, 1975 और 1986 में कश्मीर मसले पर समझौते किए थे.

कांग्रेस का आचरण भाजपा की तरह हो गया है. कांग्रेस ने भी एक ऐसा स्टैंड लिया है, जो बातचीत और समाधान के खिलाफ है. भाजपा की हां में हां मिलाने के बजाय कांग्रेस को उदार और प्रगतिशील ताकतों के साथ जुड़ने की जरूरत है. कांग्रेस 2004 में भाजपा को चुनौती देकर सत्ता में नहीं आई थी. जम्मू-कश्मीर के मामले में कांग्रेस की विरासत दागदार रही है. यदि कश्मीर के राजनैतिक मुद्दे पर वह एक दृढ़ और प्रो-पीपुल रुख नहीं अपनाएगी, तो वह खुद का नुकसान करेगी. चिदंबरम पर अपनी प्रतिक्रिया के मद्देनजर, कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली जम्मू-कश्मीर पॉलिसी ग्रुप के गठन के तर्क को भी समझा जाना चाहिए.

हुर्रियत का असमंजस

गिलानी, मीरवाइज और मलिक के संयुक्त प्रतिरोधी नेतृत्व द्वारा जारी बयान से यह संकेत मिलता है कि यदि भाजपा के लोगों के विरोधाभासी बयान को देखा जाए तो इस पहल में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे नया कहा जाए.

इस प्रक्रिया को निरर्थक बताते हुए संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व ने कहा कि जिस तरह भारत सरकार द्वारा श्री दिनेश्वर शर्मा को जम्मू-कश्मीर का वार्ताकार नियुक्त किए जाने को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया, वो कुछ और नहीं, बल्कि सरकार की समय बिताने की रणनीति है. यह रणनीति अंतरराष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय मजबूरी और कश्मीर के लोगों पर सैन्य दमन की राज्य की नीति की असफलता के कारण अपनाई गई है.

हालांकि नेतृत्व की प्रतिक्रिया कुछ वास्तविकताओं पर आधारित है, लेकिन नेताओं को अन्य वर्गों के साथ भी विचार-विमर्श करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने 2016 में हुए हड़तालों के दौरान किया था. नेतृत्व ने प्रतिक्रिया देने के लिए एक सप्ताह का समय लिया और फिर जब प्रतिक्रिया आई तो इससे बहुतों को हैरानी हुई. उन्हें बातचीत के लिए औपचारिक आमंत्रण मिलने तक इंतज़ार करना चाहिए था.

जिस तरह से शर्मा और भाजपा ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, उससे इस पहल में कोई स्पष्टता दिखाई नहीं देती. इस पृष्ठभूमि में संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व को अपने लोगों का एक समूह गठित करना चाहिए था और अपनी मांगों का एक चार्टर पेश कर गेंद को शर्मा के पाले में डाल देना चाहिए था. यदि भारत सरकार सचमुच समय बिताना चाहती है और ज़मीनी हकीकत से ध्यान भटकाना चाहती है, तो ऐसा करने से यह स्पष्ट हो जाता. शायद नेतृत्व की प्रतिक्रिया उनकी सामान्य प्रतिक्रिया की तरह थी. चूंकि शर्मा केवल मुख्यधारा की पार्टियों के साथ ही मुलाक़ात कर पाएंगे, लिहाज़ा इससे स्थिति में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है. बातचीत के दरवाज़े बन्द करना समय के विरुद्ध है. इस स्थिति के लिए कौन दोषी है, यह देखना अभी बाकी है.■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

लैंगिक भेदभाव मिटाने से खुलेगा विकास का रास्ता

राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर राजनीति में भी जगह देनी होगी. ग्राम पंचायत स्तर पर भी जहां महिलाएं मुखिया या सरपंच हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना होगा. ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में सशक्त महिला नेतृत्व का डंका बजाने वाला देश आज महिला नेतृत्व के मामले में भी पिछड़ता जा रहा है. हालांकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की स्थिति में सुधार हुआ है, जो भारत के लिए बेहतर स्थिति कही जा सकती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

लैंगिक भेदभाव के मामले में भारत का स्थान चीन और बांग्लादेश से भी पीछे है. विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 108वां स्थान दिया है. इस सूची में 144 देशों को शामिल किया गया था. पिछले साल भारत को इस सूची में 87वां स्थान मिला था. यानी हम पिछले साल से 21 पायदान नीचे आ गए हैं. अब भी देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उचित भागीदारी नहीं है. उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है.

हालांकि भारत सरकार के लिए यह बात संतोषजनक है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने यहां लैंगिक भेदभाव को 67 प्रतिशत तक दूर करने में सफल रहा है. इसके बावजूद वह अपने पड़ोसियों चीन और बांग्लादेश से काफी पीछे है. इस सूची में बांग्लादेश को 47 वां स्थान मिला है, जबकि चीन 100 वें स्थान पर है. महिलाओं की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीति में योगदान के आधार पर लैंगिक असमानता रिपोर्ट तैयार की गई थी. अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान और वेतन की बदहाल स्थिति के कारण भारत इस क्षेत्र में 139 वें स्थान पर है. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत में 66 फीसदी महिलाओं को बिना वेतन के ही काम करना पड़ता है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी असमानताएं हैं. इस क्षेत्र में भारत का स्थान 144 देशों में से 141वें पर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2234 तक हम कार्यस्थलों पर महिलाओं और पुरुषों में पूरी समानता के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. हालांकि एक साल पहले अनुमान था कि महिला पुरुषों के बीच असमानता को दूर करने में 83 साल लग जाएंगे.

राजनीति में महिला नेतृत्व के मामले में भी भारत की स्थिति बेहतर नहीं है. हालांकि पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन भारत को अभी इस क्षेत्र में और ध्यान देने की जरूरत है. राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर राजनीति में भी जगह देनी होगी. ग्राम पंचायत स्तर पर भी जहां महिलाएं मुखिया या सरपंच हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देना होगा. ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में सशक्त महिला नेतृत्व का डंका बजाने वाला देश आज महिला नेतृत्व के मामले में भी पिछड़ता जा रहा है. हालांकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की स्थिति में सुधार हुआ है, जो भारत के लिए बेहतर स्थिति कही जा सकती है.

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2017 में महिला-पुरुष असमानता को दूर करने के प्रयास ठहर गए हैं. 2006 के बाद से यह पहला मौका है, जबकि महिला-पुरुष में यह अंतर बढ़ा है. इसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर महिला-पुरुष असमानता 68 प्रतिशत घटी है, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 68.3 प्रतिशत था. डब्लूईएफ ने सबसे पहले 2006 में इस तरह की सूची प्रकाशित की थी.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी यह कहा है कि अगर भारत श्रम बल में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करता है, तो यह भारत के लिए बेहतर स्थिति होगी. मुद्राकोष ने इसके लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और सामाजिक खर्च बढ़ाने की बात भी की है. इतना ही नहीं, आईएमएफ ने ये भी कहा था कि अगर भारत रोजगार के मामले में महिलाओं को पुरुषों की संख्या के समान कर लेता है, तो इससे भारत की जीडीपी दो फीसदी तक बढ़ जाएगी. वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी देशों में लिंग समानता हासिल कर लेना है. इसके तहत सभी देशों में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने 2005 में इसे स्थान दिया था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. बजट में इसकी व्यवस्था करने के साथ-साथ योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर भी नजर रखनी होगी. श्रम बल की भागीदारी और यौन हिंसा पर रोकथाम जैसे मसलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

राष्ट्रीय आंकड़ों से पता चलता है कि देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर समुचित प्रयास किए गए हैं. ये आंकड़े स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2015-16 के हैं. एक दशक के दौरान बाल विवाह में 20 फीसदी की कमी आई है. ये आंकड़े 47 फीसदी से घटकर 27 फीसदी हो गए हैं. घरेलू हिंसा भी 37 फीसदी से घटकर 29 फीसदी तक हो गई है. इसके बावजूद भारत में, प्रति 1,000 लड़कों पर 919 लड़कियों का होना सरकार के तमाम प्रयासों पर सवाल खड़े करता है. श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी भी 2006 में 29 फीसदी से घटकर वर्ष 2016 में 25 फीसदी हो गई है.

सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से महिलाओं और लड़कियों की तुलना में अधिक पुरुष लाभान्वित हुए हैं. इसके बाद ही सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर 2005 में लिंग बजट का प्रावधान किया था. उम्मीद है कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर सरकार इस बजट को और बढ़ाने पर विचार करेगी.■

वंचितों को हक़ न मिला तो जल उठेगा देश : श्याम रजक

> आजादी के बाद देश व राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकार रही है, इसलिए किसी एक नेता और पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. मेरा बस यही कहना है कि जो वक्त गुजर गया और हमलोगों ने जो गलती कि उससे सबक सीखने की जरूरत है. न्यायिक सेवा में दलितों की हिस्सेदारी एक फीसदी भी नहीं है. यही हाल उच्च शिक्षा का भी है. यहां भी दो फीसदी हिस्सेदारी ही है. हम इन क्षेत्रों में आरक्षण के प्रावधानों को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं. यह देश तो सभी का है तो फिर दलितों की इतनी उपेक्षा क्यों?

सरोज सिंह

दलितों का सही उत्थान नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. आजादी के 70 साल बाद भी वंचित वर्ग को उसका पूरा हक नहीं मिला है. न्यायिक सेवा और उच्च शिक्षा में तो दलितों की भागीदारी न के ही बराबर है. किसी एक नेता या किसी दल को मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि मेरा मानना है कि सभी से इस मामले में चूक हुई है. अब समय आ गया है कि वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी दल और सभी नेता जुट जाएं, ताकि सदियों से दबे कुचले इस समाज का भला हो सके. अभी समय है चेतने का और अगर अभी भी नहीं चेते और वंचित समाज को उसका वाजिब हक नहीं दिला पाए तो इस देश को जलने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वंचितों की भलाई के लिए पूरा देश आगे आएगा. ये विचार हैं जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्याम रजक के. काल में वे अपने बगावती बयानों से काफी चर्चा में हैं. अपने आगे के प्लान के बारे में उन्होंने खुलकर बात की. प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ खास अंश...

सवाल : आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कुछ नेता पद की लालसा में दलित आरक्षण को लेकर बयान दे रहे हैं. उन्हें इससे परहेज करना चाहिए.

जवाब : दरअसल वशिष्ठ बाबू के बयान को मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. उन्होंने यह नहीं कहा कि पद की लालसा को लेकर बयान दिया गया है. जहां तक मेरा सवाल है तो मैं 14 साल तक मंत्री रहा और 25 साल विधायक रहा, अब भी पार्टी के वरिष्ठ पद पर हूं तो पद की लालसा का सवाल कहां उठता है? मेरा आग्रह केवल इतना ही है कि आजादी के 70 साल के बाद भी दलितों का भला क्यों नहीं हुआ, इस पर चुप्पी क्यों है? मैं भी दलित समाज से आता हूं और मैंने भी अपने जीवन में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को झेला है. मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बाद की पीढ़ी भी उसी प्रताड़ना से गुजरे जिससे मेरे जैसे लोग गुजर चुके हैं. आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि देश की संसद चुप है. शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है पर प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर एक अजीब सी खामोशी है. देश की संसद इस पर पहल क्यों नहीं कर रही है.

सवाल : दलितों के उत्थान में आप किसे बाधक मानते हैं और इसे लेकर आप किस तरह की कार्ययोजना के साथ जनता के बीच जाना चाहते हैं?

जवाब : आजादी के बाद देश व राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकार रही है, इसलिए किसी एक नेता और पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. मेरा बस यही कहना है कि जो वक्त गुजर गया और हमलोगों ने जो गलती कि उससे सबक सीखने की जरूरत है. न्यायिक सेवा में दलितों की हिस्सेदारी एक फीसदी भी नहीं है. यही हाल उच्च शिक्षा का भी है. यहां भी दो फीसदी हिस्सेदारी ही है. हम इन क्षेत्रों में आरक्षण के प्रावधानों को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं. यह देश तो सभी का है तो फिर दलितों की इतनी उपेक्षा क्यों? मेरा संकल्प है कि जब तक मैं जिंदा हूं, दलितों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा. जो भी इस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहे करे श्याम रजक कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगा. बस दलितों के उत्थान के मुद्दे को प्राथमिकता मिलती रहनी चाहिए. मैंने पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेकर जनता से मिलने का कार्यक्रम बनाया है और सभी दल और उनके नेताओं से अपील की है कि आप साथ आएं ताकि एक समरस समाज की स्थापना हो सके.

सवाल : लालू प्रसाद ने आपके बयान का स्वागत किया है और कहा है कि वह उनके साथ हैं, संघर्ष जारी रखना चाहिए.

जबाव : लालू प्रसाद को यह बताना चाहिए कि जब वे रेल मंत्री थे तो उन्होंने दलितों के आरक्षण को लेकर क्या किया? रेलवे की नौकरियों में दलितों को आरक्षण देने का विचार तब उनके मन में क्यों नहीं आया? रेलवे में सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए तो वे प्रयास कर सकते थे, लेकिन भाषण के अलावा उन्होंने क्या किया? अभी क्या बिगड़ा है? दिल्ली तक उनकी पहुंच है. संसद में प्रस्ताव लाकर दलितों के उत्थान से जुड़े मसलों पर बहस कराकर रास्ता निकलवा दें तब यह माना जाएगा कि वह सही मायनों में दलितों के हितैषी हैं.

सवाल : ऐसी चर्चा है कि आप पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और निकट भविष्य में जदयू को बाय-बाय भी कर सकते हैं.

जबाव : सवाल ही पैदा नहीं होता है. जदयू में हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा. नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने दलितों के दर्द को समझा और उस पर मरहम लगाने का प्रयास किया. नीतीश कुमार ने हर पल दलितों की भलाई के लिए सोचा, पर उनकी भी एक सीमा है. जो काम देश की संसद को करना है, उसमें वे क्या कर सकते हैं? लेकिन यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि देश भर में कोई एक नेता जो दलितों के हित के लिए गंभीर है तो उसका नाम नीतीश कुमार है.

सवाल : आप जब राजद में थे तो उस समय भी कहते थे कि अंतिम सांस तक लालू प्रसाद के साथ हूं और पार्टी नहीं छोड़ूंगा.

जबाव : हां यह सही है कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने हमेशा यह बात भी कही है कि मिट्टी में मिल जाऊं, पर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा. जब मुझे लगने लगा कि राजद में मेरे स्वाभिमान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ देने का फैसला किया. लेकिन जिसके साथ रहता हूं, पूरी ईमानदारी से रहता हूं.

सवाल : एक चर्चा यह भी है कि लोकसभा टिकट के लिए आप दलितों के मद्दे को आधार बनाकर नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं.

जबाव : ऐसी चर्चा लोग कर रहे हैं, पर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ने वाला हूं. मेरी दिल से इच्छा है कि अपना बचा जीवन मैं पूरी तरह दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दूं. इस काम में अगर कुछ सहयोग कर पाया तो लगेगा कि जीवन में मैंने कुछ किया. समाज के सभी वर्गों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है और मैं सभी वर्गों से यह अपील करता हूं कि सब मिलकर आगे आएं और विकास की दौड़ में पिछड़ चुके दलित समाज को आगे बढ़ाने का जतन करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

पद की लालसा नहीं संघर्ष मुद्दों पर है : उदय

> जो लोग मुझपर पद पाने का आरोप मढ़ रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे साधु हैं? ऐसे लोगों को यह भी जान लेना चाहिए, चूंकि मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होने के चलते सरकार का खर्च बढ़ रहा था. इसी वजह से मैंने मंत्री पद छोड़ा था. मैं पद की राजनीति नहीं करता.

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक दौर था जब उदय नारायण चौधरी बिहार में नीतीश कुमार के सबसे भरोसे के साथी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन समय बदला तो संबंधों की गर्माहट भी ठंडी पड़ने लगी. विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार चौधरी की ताजपोशी ने उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार से कुछ दूर कर दिया. इसके बाद जब मंत्रिमंडल गठन की बारी आई तो उसमें भी श्री चौधरी पीछे छूट गए तो यह संदेश साफ चला गया कि रिश्तों में अब पहले जैसी बात नहीं है. उदय नारायण चौधरी ने इसके बाद भी इंतजार किया, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने दलित आरक्षण के सवाल पर संघर्ष का रास्ता चुनने का मन बना लिया. हालांकि वे आज भी कहते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जानकारी उन्होंने नीतीश कुमार को दे दी है. श्री चौधरी का कहना है कि जदयू उनकी पार्टी है और वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फायदा पार्टी को ही मिलना है.

सवाल : क्या आउटसोर्सिंग में आरक्षण का फैसला सरकार ने आपके बयानों के दबाव में लिया है.

जवाब : मैंने वंचित वर्ग मोर्चा के तहत जो आवाज उठाई थी, उसे बिहार सरकार ने कैबिनेट में पारित कर सकारात्मक पहल की है. लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं राष्ट्रीय स्तर पर ये नीति लागू हो इसके लिए मैं लड़ाई जारी रखूंगा. मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मेरी मांग मान ली गई.

सवाल : बिहार में महादलित और दलित छात्रों के समक्ष नई चुनौतियां हैं. उनकी छात्रवृत्ति अधर में है और नामांकन को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

जवाब : छात्रवृत्ति को बंद करना पूरे तौर पर गलत फैसला है. छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलती तो आज उदय नारायण चौधरी भी यहां तक नहीं पहुंच पाता. सरकार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को फौरन बंद कर छात्रवृत्ति को चालू करना चाहिए और साथ ही साथ नामांकन में आरक्षण को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए. शिक्षा में समानता लागू करने की भी जरूरत है.

सवाल: भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण की मुखालफत की है.

जवाब : मैं सीपी ठाकुर को धन्यवाद देता हूं, वे विद्वान आदमी हैं और मैं चाहूंगा कि वे ऐसा करते रहें.

सवाल : भाजपा के कई नेता आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू करने की वकालत कर रहे हैं.

जवाब : आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू करने की बात जो कह रहे हैं, पहले उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या देश के अंदर सही रूप में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई है. 70 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है. आज तक न तो न्यायपालिका में, न निजी क्षेत्र में, न उच्च शिक्षा में आरक्षण व्यवस्था लागू हो पाई है और न बैकलॉग को सरकार लागू कर पाई है. प्रमोशन में आरक्षण को बंद करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है.

सवाल : आप अपने एजेंडे पर कैसे काम करेंगे? क्या पार्टी लाइन के खिलाफ भी आप जा सकते हैं?

जवाब : मैं दलितों के हक के लिए वंचित वर्ग मोर्चा के बैनर तले लड़ाई जारी रखूंगा. पार्टी अगर इसे ग्रहण करती है तो धन्यवाद है और उसे नहीं भी स्वीकार करती है तो मैं पार्टी लाइन की चिंता किए बगैर प्रखंड पंचायत और जिला स्तर पर आंदोलन चला लूंगा.

सवाल : आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप पद पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं?

जवाब : जो लोग मेरे पर पद पाने का आरोप मढ़ रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे साधु हैं? ऐसे लोगों को यह भी जान लेना चाहिए, चूंकि मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होने के चलते सरकार का खर्च बढ़ रहा था. इसी वजह से मैंने मंत्री पद छोड़ा था. मैं पद की राजनीति नहीं करता.

सवाल : शरद यादव और लालू प्रसाद अगर आपको समर्थन देते हैं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे?

जवाब : शरद यादव से मेरे 25 साल पुराने संबंध हैं. शरद यादव और लालू प्रसाद अगर मुझे समर्थन देते हैं तो उन्हें धन्यवाद है. शरद यादव के साथ मेरे किसी तरह के राजनैतिक संबंध नहीं हैं. मै जदयू में हूं और जदयू में रहूंगा.

सवाल: क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आप के विरोध की वजह से नीतीश कुमार का एक निश्चय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अधर में पड़ सकता है.

जवाब : मैं नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मेरा नीतिगत विरोध जारी रहेगा. वंचित वर्ग मोर्चा के तहत मैंने 15 सूत्री मांगों को सामने रखा है और जब तक उसे सही स्वरूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हमारा मुद्दा मरेगा नहीं. मेरा आंदोलन भी जारी रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा सांसद श्यामाचरण गुप्ता का बयान

नोटबंदी से बेरोज़गारी बढ़ी है

ए.यू. आसिफ़

नोटबंदी के एक वर्ष पूरे होने पर केन्द्र में सत्ताधारी भाजपा और केन्द्रीय मंत्री कालाधन से निपटने के लिए नोटबंदी की खूबियां बयान करते हुए नहीं थक रहे हैं, इलाहाबाद से भाजपा सांसद और बीड़ी के प्रतिष्ठित कारोबारी श्यामाचरण गुप्ता ने ये खुलासा कर वास्तविक तथ्य को सामने ला दिया है कि नोटबंदी से आत्महत्या और बेरोजगारी बढ़ी है और असंगठित क्षेत्र पंगु हो गया है. भाजपा एमपी की ये टिप्पणी दरअसल नौ नवंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त से संबंधित पार्लियामेंट्री पैनल द्वारा नोटबंदी के प्रभाव की समीक्षा लेने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के दौरान आई. इस अवसर पर केन्द्र सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के चेयरमैन सुशील चंद्र समेत कई दिग्गज सदस्य पैनल में मौजूद थे.

ध्यान रहे कि श्यामाचरण गुप्ता खुद बीड़ी के एक बड़े व्यापारी हैं और 250 करोड़ रुपए की मिलकियत वाले बिजनेस श्याम बीड़ी के मालिक हैं. उन्होंने अपने बिजनेस हाउस समेत तमाम असंगठित क्षेत्रों पर नोटबंदी के पिछले एक साल में पड़े भयंकर प्रभाव का विवरण देते हुए कहा कि सरकार का कैश फ्लो रोक देने या कम कर देने से नौकरियों में बड़ी कमी हुई है. बीड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होने से यह सेक्टर डिमांड में बड़ी कमी का शिकार हुआ है. उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब श्यामाचरण गुप्ता ने पार्लियामेंट्री पैनल की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में संबंधित अधिकारियों से नोटबंदी के कारण असंगठित क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में आत्महत्या से हुई मौतों के आंकड़े पूछे. उन्होंने जानना चाहा कि क्या वो जानते हैं कि इन असंगठित क्षेत्रों में कितनी खराब स्थिति है, जहां लोग भूखमरी के शिकार हैं. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से उनका सवाल था कि क्या उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा की गई आत्महत्याओं पर कोई आंकड़े जमा किए हैं?

दिलचस्प बात तो ये थी कि उक्त बैठक में पैनल के बाकी भाजपा के सदस्य बिल्कुल खामोश रहे और केन्द्र सरकार के समर्थन में मैदान में नहीं कूदे. हैरत की बात ये थी कि इस मौके पर किसी भाजपा नेता ने नहीं, बल्कि राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने केन्द्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के हक में बोला. उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर बेंगलुरू से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये एशिया पेंट के मालिक हैं.

BANNED
ASSASSINATION of DEMOCRACY by GOVERNMENT
MUMBAI CONGRESS
SHAME
PROTEST

पार्लियामेंट्री पैनल के इस बैठक में विपक्षी सदस्य ने कहा कि नोटबंदी से चीन को काफी फायदा हुआ है. तृणमूल कांग्रेस एमपी सुगाता राय ने कहा कि नोटबंदी के बाद पिछले एक वर्ष में चीन से 23 फीसदी आयात बढ़ा है. उनका कहना था कि पेटीएम, जो असल में डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्मों में से एक है, को चीनी ई कॉमर्स जाएंट अली बाबा द्वारा वित्तीय सहयोग मिलता है. उक्त पार्लियामेंट्री पैनल पूर्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से बात कर चुका है. पैनल के चेयरमैन मोइली ने कहा कि आगामी हफ्ते हमलोग टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल होंगे, से मिलकर ये जानना चाहेंगे कि क्या हमलोग कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हैं? आखिर में हमारी बैठक का कॉरपोरेट, छोटे और मंझोले इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर सेक्टर और रिएलिटी सेक्टर से उनपर हुए नोटबंदी के प्रभाव को जानने के लिए होगी.

जहां तक दूसरी तरफ नोटबंदी से बेरोजगारी का सवाल है, ये तो अब स्पष्ट है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 15 लाख से ज्यादा लोग नोटबंदी से प्रभावित होकर 2017 के शुरुआती चार महीनों में अपनी नौकरियां खो चुके हैं. उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'फाइनेंशियल टाइम्स' में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आलेख छपा, जिसमें उन्होंने नोटबंदी के एक वर्ष पूरे होने पर अपना विचार व्यक्त किया है कि 'नोटबंदी से भारत की दो फीसदी जीडीपी कम हुई है. इनफॉर्मर लेबर सेक्टर बर्बाद हुआ है और कई छोटे और मंझोले बिजनेस खत्म हो गए और नोटबंदी ने लाखों भारतीय श्रमिकों का जीवन तबाह कर दिया.'

अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की स्थिति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुनकर नोटबंदी के पूरी तरह शिकार हुए हैं. आज तक चैनल की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी के सरिया में अमरपुर बटलोहिया बुनकरों की एक छोटी सी बस्ती है. यहां मोहम्मद जलील का परिवार पिछली कई पुश्तों से बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ है. 63 वर्षीय अब्दुल जलील और उनके बेटे बुनकर हैं. लेकिन एक वर्ष पहले मुल्क में लागू हुई नोटबंदी की मार ये परिवार अब तक झेल रहा है. अब्दुल अजीज ने बताया कि सात वर्ष पूर्व उन्होंने अपने घर पर चार हैंडलूम मशीनों को हटाकर पावर लूम लगाया था, जिससे सात-आठ हजार की मासिक कमाई हो जाती थी. लेकिन नोटबंदी के बाद उनकी कमाई अब आधी रह गई है. उनका कहना है कि वाराणसी और उसके आसपास के कई जिलों में बनारसी साड़ी के बुनकरों के कारोबार नोटबंदी के बाद लगभग ठप हो गए. वो ये भी कहते हैं कि यह स्थिति चल ही रही थी कि जीएसटी की मार पड़ी, जिसके लागू होने के बाद उन्हें बनारसी साड़ी बनाने के लिए तानाबाना यानी वो धागा जिससे साड़ी बनती है, खरीदने के भी लाले पड़ गए. जीएसटी के बाद उसकी कीमत बढ़ गई और वो उसे खरीदने के लायक नहीं रहे. यहां यही हालत सरिया के और बुनकर निसार अहमद और उनके चार भाइयों की है. कुछ वर्ष पूर्व इन लोगों ने पांच हैंडलूम मशीनें हटाकर पावरलूम मशीनें लगाई थी. पांच कारीगर इसमें काम करते थे, लेकिन नोटबंदी के लागू होने के बाद उनके भाई उन कारीगरों को पैसे देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में दूसरे बुनकरों की खराब स्थिति है.

अनऑर्गनाइज सेक्टर में आम तौर पर बुरी हालत है. दूसरा उदाहरण मुरादाबाद का लें, जहां कि अर्थव्यवस्था भी नोटबंदी से पूरी तरह प्रभावित है. वहां की दयनीय स्थिति का नक्शा खींचते हुए सैयद खुर्रम रजा ने चौथी दुनिया को बताया कि एक व्यक्ति आरिफ है. उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसका कभी ऐसा कारखाना रहा होगा, जिसमें हमेशा छह-सात लोग काम करते होंगे और 40-50 हजार रुपए महीने कमाते होंगे. नोटबंदी के एक वर्ष पूरा होने के बाद उसकी हालत यह है कि उसके पास अपने हाथ पर प्लास्टर कराने के लिए पंद्रह सौ रुपए तक नहीं हैं और वो एक सस्ते जर्राह से अपने हाथ की हड्डी पर लगी चोट की पट्टी करा रहा है. नोटबंदी का फैसला उसके लिए ऐसी परेशानियां लेकर आया कि वो देखते-देखते लोगों को तनख्वाह देने वाले से तनख्वाह लेने वाले बन गए.

आइए देखते हैं कि आरिफ खुद अपनी दर्दनाक कहानी क्या बताते हैं? आरिफ ने कहा कि मैं 40-50 हजार रुपए महीने कमाता था. मेरे पास छह-सात लोग काम करते थे और 15 हजार रुपए कमा लेते थे. मगर आज हालत ये है कि मैं खुद आज 10 हजार रुपए महीने की नौकरी कहीं और कर रहा हूं. मेरी बेटी जो एमबीए कर रही थी, उसी दरम्यान नोटबंदी की मार के कारण उसकी शिक्षा रोक देनी पड़ी. बेटा इंटर में पढ़ रहा था, वो भी घर पर पढ़ाई छोड़ कर बैठा है. जब नोटबंदी हुई थी, तब उन दिनों दिन में बैंकों में लाइन में लगकर पैसा निकालता था और अपने कारीगरों के तनख्वाह के लिए बंदोबस्त करता था. कारीगरों के बैंक में एकाउंट नहीं थे. कोई चेक लेने के लिए तैयार नहीं था. कच्चा माल भी नकद मिल रहा था. जिन लोगों से पैसे लेने थे, उनकी पोजिशन नगद देने की नहीं थी. सबके सब चेक दे रहे थे. इस सबका असर ये पड़ा कि धीरे-धीरे काम बंद हो गया. कुछ दिनों तक जमा रकम से खाया, फिर जब वो खत्म होने लगे तब कारखाना बंद करके बच्चों को पालने के लिए छोटी सी नौकरी कर ली. इस वक्त स्थिति यह है कि आरिफ के कारखाने में पावर का कॉमर्शियल कनेक्शन लगा हुआ है और उसे उम्मीद है कि अच्छे दिन जल्दी आएंगे और वो फिर कारखाना शुरू कर पाएगा. इसलिए उसने बिजली का कनेक्शन नहीं कटवाया.

इन तमाम उदाहरणों से अंदाजा होता है कि विभिन्न अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरों में कुल मिलाकर यही स्थिति पाई जाती है. श्यामाचरण गुप्ता की बातें कड़वी जरूर हैं, मगर सच हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार पर इन सबका अब भी कोई असर पड़ेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

अदालतों को याचिकाकर्ता की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए

न्याय तक पहुंच सिर्फ अदालतों की स्थापना की जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे न्याय तंत्र से संबंधित है. भले ही अदालतें लोगों की पहुंच में हों, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और खर्चीली है कि न्याय व्यवस्था बहुसंख्यक लोगों की पहुंच से दूर है. इस अदालती फैसले के बाद इन पक्षों पर बात करने की जरूरत है.

गोवा में चाहे जो भी सरकार हो, उसे वहां पर्यावरण पर काम करने वाले समूह हमेशा खटकते रहे हैं. सरकार को लगता है कि पर्यावरण के मसले पर ये विकास को बाधित कर रहे हैं. इसलिए यह अचरज की बात नहीं है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर राष्ट्रीय हरित अभिकरण यानी एनजीटी की पुणे पीठ में चल रहे गोवा के सभी मामलों को एनजीटी दिल्ली में स्थानांतरित कराने की कोशिश की. सरकार ने तर्क दिया कि गोवा से पुणे आना-जाना मुश्किल है और कई गुना अधिक दूर होने के बावजूद दिल्ली आना-जाना आसान है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उनके इस अनुरोध पर तेजी दिखाते हुए दो महीने से भी कम वक्त में स्वीकार कर लिया. इस निर्णय में इन मामलों से संबंधित दूसरे पक्षों की राय तक नहीं ली गई. लेकिन बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय के इस निर्णय को खारिज कर दिया.

इस मामले में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नूतन सरदेसाई ने 47 पन्ने का निर्णय दिया है कि उसमें देश की न्याय व्यवस्था के प्रति मूल सवाल उठाया गया है. इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और आजादी का मूल अधिकार देता है और न्याय तक पहुंच का अधिकार इसके तहत आता है. इसमें आने वाली कोई भी बाधा इस मौलिक अधिकार के खिलाफ है. आदेश में लिखा है, 'एक ऐसे समय में जब अदालतें अपना शाखा विस्तार करना चाहती हैं, ताकि याचिकाकर्ताओं को कम परेशानी हो, तब किसी सरकार की यह कोशिश बड़ी अजीब लगती है कि वह अपनी सुविधा के लिए मामलों की सुनवाई हजारों किलोमीटर दूर करवाना चाहती है और वह भी जनहित के नाम पर. यह जनहित नहीं है.'

वैसे गोवा सरकार की यह कोशिश एनजीटी की मूल भावना के भी खिलाफ है, क्योंकि 2011 में एनजीटी के पांच स्थानीय पीठ इसलिए स्थापित किए गए ताकि लोगों को सुनवाई के लिए बहुत दूरी नहीं तय करनी पड़े. खुद एनजीटी की स्थापना सामान्य अदालतों में पर्यावरण संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हुई थी. सच्चाई तो यह है कि स्थानीय पीठ के अलावा गोवा जैसे जगहों पर सर्कुलर पीठ स्थापित करने की बात उठी थी, क्योंकि गोवा से सबसे अधिक मामले आते हैं. पुणे पीठ के पास पूरे महाराष्ट्र और गुजरात के 340 मामले हैं और गोवा के 146. लेकिन राज्य सरकार ने इस काम को और आसान बनाने के बजाए जटिल बनाने की कोशिश की. पर्रिकर सरकार को यह लग रहा था कि वह ऐसा करने में कामयाब होगी, लेकिन गोवा में कुछ ऐसे सजग समूह हैं जो पर्यावरण को लेकर बेहद जागरूक हैं.

इस फैसले में कहा गया कि गोवा की सबसे बड़ी धरोहर पर्यावरण और पारिस्थितिकी है. 14 लाख की आबादी वाला गोवा पर्यावरण जागरूकता के मामले में सबसे सजग राज्य है. पर्यावरण सुरक्षा की लड़ाई यहां गांव-गांव में दैनिक तौर पर लड़ी जाती है. पंचायतें अक्सर विकास योजनाओं का आकलन पर्यावरण के लिहाज से करती हैं. तब भी अगर सरकार इन चिंताओं को नहीं दूर कर पाती तब ये मामले अदालत में पहुंचते हैं. इस काम में एनजीटी की स्थानीय पीठ लोगों के लिए बेहद उपयोगी है.

न्याय तक पहुंच सिर्फ अदालतों की स्थापना की जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे न्याय तंत्र से संबंधित है. भले ही अदालतें लोगों की पहुंच में हों, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और खर्चीली है कि न्याय व्यवस्था बहुसंख्यक लोगों की पहुंच से दूर है. इस अदालती फैसले के बाद इन पक्षों पर बात करने की जरूरत है. इस फैसले में जजों ने जेम्स बाल्डवीन की पुस्तक दि प्राइस ऑफ दि टिकट के एक अंश का हवाला दिया, 'अगर कोई यह जानना चाहता है कि देश में न्याय दिया जा रहा है या नहीं तो उसे पुलिस, वकील और जजों के पास नहीं, बल्कि आम लोगों के पास जाना चाहिए, जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है और उन्हें सुनना चाहिए.' यह बात भारत पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां कानून आम लोगों की रक्षा करने में अक्सर नाकाम रहता है. ■

(साभार : इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

भाजपा के लिए कठिन है 2019 की डगर

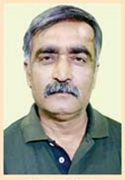
प्रशान्त शरण

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भाजपा को फिर से सत्ता पर काबिज कराने के लिए एंड़ी-चोट एक कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर रांची आए और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की. प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें भी हुईं, जिनमें लोकसभा की सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपने आलाकमान को इसके लिए आश्वस्त किया कि राज्य में भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ा है और जनता सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से खुश है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी झारखंड में सभी लोकसभा सीटों पर तो भगवा लहराएगी ही, विधानसभा की 81 में से 60 सीटों पर भी कमल खिलेगा. मुख्यमंत्री के इस दावे को कुछ राजदरबारी समाचार पत्रों का भी साथ मिला. एक सर्वेक्षण के जरिए यह बताया गया कि अगर अभी चुनाव हुए, तो भाजपा को 81 में से 65 सीटें मिलेंगी. भाजपा के कई आला नेताओं को इस सर्वेक्षण वाले समाचार पत्र की कॉपियां भेजी गईं. लेकिन भाजपा नेता इससे आश्वस्त नहीं हो सके और अपने स्तर पर उन्होंने आंतरिक सर्वेक्षण कराया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे.

विपक्षी एकजुटता भाजपा के लिए चुनौती

इस बार भाजपा को शिकस्त देने के लिए झारखंड में महागठबंधन की पृष्ठभूमि लगभग तैयार हो चुकी है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में सभी दलों को लाने की कोशिश कर रहे हैं. चारा घोटाले के मामले में ट्रायल फेस कर रहे लालू प्रसाद यादव का इन दिनों रांची आना-जाना लगा रहता है. वे इस कोशिश में हैं कि झारखंड में भी बिहार विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम दोहराया जाय. इसके लिए वे भाजपा विरोधी सभी दलों को एक मंच पर लाने के प्रयास में जुटे हैं. उनका कहना है कि इस बार पूरे देश की जनता भगवा पार्टी को सबक सिखाएगी. झारखंड और बिहार में तो भाजपा का सफाया तय है. धर्मनिरपेक्ष दल इस बार भगवा पार्टी को खदेड़ कर ही दम लेंगे. हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाबूलाल मरांडी की पार्टी का मतभेद लालू की इस कोशिश के आड़े आ रहा है. दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ मतभेद है. लेकिन अगर बाबूलाल इस गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, तो भी कांग्रेस, झामुमो और राजद का एक साथ चुनाव मैदान में उतरना भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो भाजपा के लिए विधानसभा में 20 सीटें जीत पाना भी ईश्वरीय कृपा मानी जाएगी. अकेले झामुमो ही भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के मामले में भाजपा सरकार के बैकफुट पर आने के बाद झामुमो का जनाधार तेजी से बढ़ा है. लिट्टीपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोक दी थी. पूरे सरकारी अमले के साथ भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तीन माह तक कैंप किया, लेकिन इन सबके बाद भी झामुमो ने भाजपा को भारी मतों से शिकस्त दी. झामुमो के बढ़ते जनाधार का सहज अंदाजा इसी से लगाया जा सकता जा सकता है कि पूरे देश में मोदी लहर के बाद भी झामुमो ने एक सीट का इजाफा कर 81 में से 19 सीटों पर कब्जा जमाया था.

आंतरिक सर्वेक्षण ने उड़ाई भाजपा-संघ की नींद

सूत्रों की मानें तो संघपरिवार एवं भाजपा ने जब अपने स्तर पर झारखंड में खुफिया सर्वेक्षण कराया तो सबको सांप सूंघ गया. इस सर्वेक्षण में भाजपा की दयनीय स्थिति सामने आई. पता चला कि जनता के साथ-साथ भाजपा के अधिकांश नेता एवं कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री रघुवर दास के तानाशाही वाले रवैये से नाराज हैं. लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा. सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन एवं धर्मान्तरण निषेध विधेयक के कारण आदिवासी, महतो एवं इसाई मतदाताओं का भाजपा से मोह भंग हो चुका है. अल्पसंख्यक तो वैसे ही भाजपा से नाराज चल रहे हैं. राज्य की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत मतदाता इन्हीं वर्ग से है. ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में भाजपा के मिशन-2019 का सफल होना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है.

अपनों से जूझ रही भाजपा

झारखंड गठन के बाद भाजपा पहली बार बहुमत में आई, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकी, जिससे लोग भाजपा को याद कर सकें. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन और धर्मान्तरण निषेध विधेयक लाकर तो सरकार खुद विवादों में घिर गई. इससे सत्ताधारी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई. अपने तानाशाही भरे फैसलों के कारण मुख्यमंत्री रघवर दास को भारी फजीहत झेलनी पड़ी. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के मामले में तो रघुवर दास ने भाजपा के आला नेताओं की भी नहीं सुनी. इसके बाद अर्जुन मुंडा और करिया मुंडा सरीखे नेता रघुवर दास से नाराज हो गए. अर्जुन मुंडा की नाराजगी रघुवर और भाजपा पर भारी पड़ी. अधिकांश आदिवासी विधायक एवं भाजपा नेता मुंडा के पक्ष में गोलबंद हो गए. झारखंड में पार्टी का संगठन कमजोर है और दो गुटों में साफ तौर पर विभाजित है. संगठन में 44 लाख नए सदस्य तो बने पर 22 लाख सदस्यों का सत्यापन नहीं हो सका है. इस मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई थी. अमित शाह ने जीत के कई टिप्स दिए, लेकिन शाह के टास्क पर पार्टी संगठन सुस्त है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिशन-2019 को लेकर सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी की सभी ईकाइयों को कई टास्क सौंपे थे, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम होता नहीं दिख रहा है.

इधर संथाल परगना में भाजपा अपना किला मजबूत करने की कोशिश में है. केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां मिशन-2019 की बुनियाद भी रखी. उन्होंने यहां कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया. इसके जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ही आदिवासी बहुल इस प्रमंडल का कायाकल्प कर सकती है. संथाल परगना में लोकसभा की तीन और विधानसभा की 18 सीटें है. यह क्षेत्र झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है. अब भाजपा यहां सेंधमारी का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में झामुमो के 6 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं. हालांकि वे दल-बदल कानून की जद में आ गए और उनका मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है. इधर रघुवर दास को अपनी ही पार्टी के विधायकों एवं नेताओं से भी भय बना रहता है. भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद भी वे हमेशा एक अनजान भय से डरे रहते हैं. यही कारण है कि वे कभी कांग्रेसी विधायकों को अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं, तो कभी झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरने का अर्शीवाद लेते हैं. सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी को तोड़ कर विधायकों को भाजपा में मिला लिया.

रघुवर दास के दावे पर विपक्ष का सवाल

अपने कामों को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास आत्मविश्वास से लबरेज हैं. उनका मानना है कि भ्रष्टाचार एवं अन्य कारणों से आम जनता का विश्वास राजनेताओं से उठ गया था जिसे वे वापस लाने में सफल रहे हैं. उनका कहना है कि मैं दास बनकर जनता की सेवा कर रहा हूं और 2019 के अंत में जनता को अपने काम का हिसाब दूंगा. जनता उन नेताओं को सबक सिखाएगी, जिन्होंने केवल राज्य को बेचने का काम किया है. मिशन-2019 के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो टास्क और जिम्मेदारी दी है, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा. भाजपा का जनाधार राज्य में तेजी से बढ़ा है. लोकसभा की सभी 14 सीटों एवं विधानसभा की 81 में से 60 सीटों पर जीत का पार्टी ने लक्ष्य रखा है, जो हर हाल में पूरा होगा, क्योंकि जनता विकास चाहती है और हमारी सरकार ने विकास में एक मिसाल कायम किया है. हमने योजनाओं को जमीन पर उतारा है. पहली बार स्थानीय नीति एवं धर्मान्तरण निषेध विधेयक लाया गया है. स्थानीय नीति के नाम पर पिछले 14 वर्षों से राजनीति हो रही थी. काफी विरोध के बाद भी मैं इस नीति को लाने में सफल रहा. मैने कई राज्यों की स्थानीय नीति का अध्ययन किया और सभी से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम परिणाम पर पहुंचा. इसका लाभ भी अब दिखने लगा है, सरकारी नौकरियों में एक लाख से भी अधिक लोगों को नियुक्त किया गया. जिसमें से 90 प्रतिशत स्थानीय हैं. मोमेंटम झारखंड की परिकल्पना भी इसलिए की गई थी कि हमारे राज्य के बेरोजगारों को घर में ही काम मिले. उद्योगों के आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और पलायन जो कि एक बड़ी समस्या है, उसपर रोक लगेगी. रघुवर दास का कहना है कि मैं अब भी उस वादे पर अटल हूं कि अगर 2018 तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचा सका, तो वोट मांगने नहीं आऊंगा.

इधर झामुमो नेता हेमंत सोरेन रघुवर दास के दावों पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है. झारखंड की सरकार दिल्ली से चल रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास केवल यहां की जमीनें बेचने के लिए सत्ता में बैठे हैं. आला नेताओं के आदेश पर बड़े उधोगपतियों को जमीन दिया जा रहा है. लोग यहां भूख से मर रहे हैं और मुख्यमंत्री विदेश दौरा कर रहे हैं. मोमेंटम झारखंड और माइनिंग शो के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है. इससे राज्य को कोई लाभ नहीं मिल पाया. जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री के कुनबे में ही भ्रष्टाचारियों की जमात है. विकास के नाम पर सरकारी राशि का खुलकर बंटरबांट हो रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, आला अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. झाखंड में विकास जमीन पर नहीं, विज्ञापनों में नजर आ रहा है. राज्य में विवि-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है. आए दिन दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं. नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अधिकारी मुकदर्शक बने हुए हैं. रघुवर सरकार हर मोर्चे पर विफल है. यह सरकार सर्कस की तरह केवल शो दिखाने में विश्वास करती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी
पूरे हफ्ते ख़बरों का ख़ज़ाना
जुड़िए...
Editor's Take
में देश के सबसे निर्भीक पत्रकार संतोष भारतीय से
Fourth Dimension में
छप क्या रहा चौथी दुनिया के नए अंक में
Crime Time में हर दिन अपराध की पड़ताल
हम ख़बरें बनाते ही नहीं दिखाते भी हैं

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है

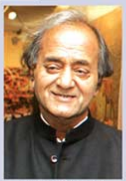

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. आयोग का यह फर्ज है कि वो इसकी विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखे. चुनाव आयोग को हर चुनाव से पहले यह घोषणा करनी चाहिए कि वह किस प्रणाली से चुनाव करवा रहा है. इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और आम नागरिक को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है. हर पांच साल में चुनाव होते हैं. इसमें कोई जीतता है, कोई हारता है. उससे मेरा कोई मतलब नहीं है. मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कांग्रेस में नहीं हूं. मैं नहीं चाहता कि मोदी जाएं और राहुल गांधी आ जाएं. यह जनता तय करती है, लेकिन सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, जैसे आज अमेरिका में है.

हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को चुनाव सम्पन्न हो गए. चुनाव के नतीजों की घोषणा 18 दिसंबर को गुजरात के नतीजों के साथ की जाएगी. ऐसा क्यों, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होने हैं. दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्वाचन आयोग अपने मानकों पर खरा नहीं उतरा है. जब चुनाव आयोग हिमाचल चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर रहा था, तब हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा भी होनी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा की? ऐसा उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गुजरात में सरकार को नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करनी थी, यानी निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लग गया. टीएन शेषन एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग का एक नया मानक स्थापित किया था. उसके पहले भी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था, लेकिन शेषन ने दिखाया था कि वास्तव में निर्वाचन आयोग के क्या-क्या अधिकार हैं? यह ज़माना 1990-91 का था. अब 27 साल बाद एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए हैं, जिन्होंने उस मानक को नीचे गिराया है. देश के भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है.

बहरहाल, यह बात अब बीत गई है. अब जो चुनाव हो रहे हैं, वो वीवीपैट सिस्टम से हो रहे हैं. इसमें वोटिंग मशीन से वोटर वेरिफिकेशन का कागज निकलता है. अब देखना यह है कि इसकी विश्वसनीयता कितनी रहती है. नोटबंदी के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी. उस चुनाव पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है. उस पर आज भी सवाल है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था कि नहीं. कई प्रदेशों में ये शंका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव में धांधली हुई थी. भारत में इससे पहले इस तरह की चर्चा कभी नहीं हुई थी. एक अफ्रीकी देश है, जहां एक व्यक्ति 25 साल से सत्ता में है. हर पांच साल के बाद वहां चुनाव होते हैं. वह हर चुनाव हारता है और यह घोषणा कर देता है कि वह चुनाव जीत गया. सेना उसका समर्थन कर देती है. यदि भारत के चुनाव के तरीके भी संदेह के दायरे में आ गए हैं, तो यह खोखलापन है, लोकतंत्र है ही नहीं. दुर्भाग्यवश, यदि भारत इस काली गुफा में घुस गया, तो लोकतंत्र खत्म तो हो ही जाएगा, साथ ही पाकिस्तान की तरह यहां भी सेना का वर्चस्व हो जाएगा. इस दृष्टिकोण से हिमाचल का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहां से केवल चार सदस्य चुन कर लोकसभा पहुंचते हैं. देश की राजनीति में इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन इस चुनाव से चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता का एक संकेत मिलेगा. गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को चुनाव होने हैं, उसमें तो मालूम पड़ ही जाएगा. अब वो चुनाव वीवीपैट से हो रहा है या ईवीएम से, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है.

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. आयोग का यह फर्ज है कि वो इसकी विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखे. चुनाव आयोग को हर चुनाव से पहले यह घोषणा करनी चाहिए कि वह किस प्रणाली से चुनाव करवा रहा है. इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और आम नागरिक को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है. हर पांच साल में चुनाव होते हैं. इसमें कोई जीतता है, कोई हारता है. उससे मेरा कोई मतलब नहीं है. मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कांग्रेस में नहीं हूं. मैं नहीं चाहता कि मोदी जाएं और राहुल गांधी आ जाएं. यह जनता तय करती है, लेकिन सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, जैसे आज अमेरिका में है. अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग हैरान है कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, लेकिन किसी ने वहां की प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया. जो हुआ, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ. जनता जिसको चुनती है, वो चुन लिया गया. अंग्रेजी में कहावत है कि यू गेट द गवर्नमेंट, यू डिजर्व (आपको वैसी ही सरकार मिलती है, जिसके आप हकदार होते हैं). लोकतंत्र में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप किसी बेवकूफ को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, इसलिए वो आजादी भी होनी चाहिए. यदि अच्छे आदमी को निर्वाचित करने की आजादी है, तो खराब आदमी को भी निर्वाचित करने की आजादी होनी चाहिए. लेकिन वो निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए. लिहाज़ा चुनाव आयोग को चाहिए कि 2019 के आम चुनाव से पहले इस धब्बे को साफ कर दें. ये देशहित में होगा, चुनाव आयोग के हित में होगा और जो आने वाली सरकार है, उसके हित में होगा.

VVPAT
Election Commission of India

8 नवंबर को नोटबंदी के एक वर्ष पूरे हो गए. सरकार इसे एक क्रांतिकारी कदम के रूप में मना रही है. वहीं, विपक्ष के लोगों ने 8 नवंबर को नोटबंदी की बरसी मनाई. दरअसल, देश की आज़ादी के बाद के 70 वर्षों में उससे ज्यादा घातक, उससे ज्यादा बेवकूफी भरा और बिना सोचे-समझे इस देश ने कोई आर्थिक कदम नहीं उठाया था. अब इसके खतरे से लोगों को आगाह करना चाहता हूं. एक कहानी है मेढ़क और पानी की, जो यहां सटीक बैठती है. उबलते हुए पानी में मेढ़क को डाल दीजिए, वो कूद कर बाहर आ जाएगा और अपनी जान बचा लेगा. ठंडे पानी में एक मेढ़क को डाल दीजिए और उस पानी को धीरे-धीरे गरम कीजिए, तो वो पानी में ही मर जाएगा, क्योंकि वो गर्मी का आदि होता रहता है. एक स्टेज आता है जब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता और मर जाता है. हमारा देश भी उसी हालत में जा रहा है. जब इमर्जेंसी लगाई गई, तब वो उबले पानी की तरह थी. जनता ने झटक कर सरकार को बाहर फेंक दिया और अपनी आजादी बचा ली. अब साढ़े तीन साल से जो हो रहा है उसमें पानी का तापमान धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. नोटबंदी उसकी एक खास मिसाल है. नोटबंदी के एक साल बाद सरकार दूरदर्शन और अखबारों के ज़रिए यह बता रही है कि नोटबंदी का कितना फायदा हुआ है, यानी असलियत और संवाद में कोई संपर्क नहीं है. हर व्यक्ति इसकी असलियत जानता है. यदि कोई बहुत उदार टिप्पणी करेगा तो भी यह कहेगा कि यह एक निरर्थक कदम था. लेकिन यदि सरकार कहे कि यह बहुत बेहतर क़दम है और इससे अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है, तो फिर यह तो विडंबना ही कही जाएगी.

एक कहानी है मेढ़क और पानी की, जो यहां सटीक बैठती है. उबलते हुए पानी में मेढ़क को डाल दीजिए, वो कूद कर बाहर आ जाएगा और अपनी जान बचा लेगा. ठंडे पानी में एक मेढ़क को डाल दीजिए और उस पानी को धीरे-धीरे गरम कीजिए, तो वो पानी में ही मर जाएगा, क्योंकि वो गर्मी का आदि होता रहता है. एक स्टेज आता है जब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता और मर जाता है. हमारा देश भी उसी हालत में जा रहा है. जब इमर्जेंसी लगाई गई, तब वो उबले पानी की तरह थी. जनता ने झटक कर सरकार को बाहर फेंक दिया और अपनी आजादी बचा ली.

लोकतंत्र का मतलब संवाद होता है. संवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच तर्क और वितर्क हो. अब जो हो रहा है, वो तो तर्क की भी विडंबना है. हिटलर के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर गोएबल्स साहब थे. उनकी थ्योरी थी कि अगर एक झूठ को 100 बार बोलें, तो वह सत्य हो जाता है. यह सरकार उसी रास्ते पर चल रही है. अब नोटबंदी को बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित करने के लिए लोगों से लेख लिखवाएं, तो यह बड़ा हास्यास्पद होगा. कोई भी अर्थशास्त्री (जो इनके खिलाफ हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं) जो सरकार के समर्थन में हैं, वो हक़ीक़त जानते हैं, लेकिन सरकार को नुक़सान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो लिखते हैं कि इसके बेहतर दूरगामी परिणाम होंगे. नोटबंदी के दूरगामी परिणाम कुछ हैं ही नहीं. नोट बदलने थे, बदल दिए गए. वो 6 महीने का अल्पकालिक मामला था, वो खत्म हो गया. अब उसपर बहस करना निरर्थक है.

दरअसल नोटबंदी की झेंप मिटाने के लिए सरकार ने जल्दबाज़ी में जीएसटी लागू कर दिया. जीएसटी पर देश में बीस साल से संवाद चल रहा था. उसे जल्दबाज़ी में लागू करने की वजह से त्रुटियां रह गईं. 12 बजे रात को संसद के सेंट्रल हॉल में इस तरह से फंक्शन किया गया, जैसे नई आज़ादी आ गई. यह अपने आप में बहुत संकीर्ण सोच है. कर प्रणाली में बदलाव को आप क्रांति बता रहे हैं! आप तो देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई. जवान देश पर अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं. जीएसटी का परिणाम क्या हुआ? जो छोटे-छोटे धंधे करने वाले हैं, किराने वाले, सब्जी बेचने वाले, ढाबे चलाने वाले सबका धंधा ठप हो गया. मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी के सलाहकार कौन हैं, लेकिन जो भी हैं वो जमीन से बहुत दूर हैं. देश में संगठित क्षेत्र के कुल मजदूरों की संख्या तीन करोड़ है. इस तीन करोड़ में सरकारी कर्मचारी और पुलिस सब शामिल हैं. देश में संगठित क्षेत्र से कहीं ज्यादा संख्या असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की है. उनमें कोई ढाबे पर काम करता है, कोई दुकान में काम करता है. इनकी संख्या करोड़ों में है. सरकार के रुख से लगता है कि उसे केवल संगठित क्षेत्र के तीन करोड़ लोगों की ही चिंता है, उसे बाकियों की कोई चिंता नहीं है. यह समझ से बाहर है कि इनका कैलकुलेशन है क्या? यदि इसके बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं, तो वही मेढक वाली बात हो गई कि धीरे-धीरे हमारा देश ही खत्म हो जाएगा.

नोटबंदी का सबसे अधिक फायदा किसे हुआ? आंकड़े बताते हैं कि चीन को हुआ. भारत में चीन का आयात काफी बढ़ गया. सबसे पहले तो इस पर बहस होनी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश के लिए है या चीन, जापान और अमेरिका के लिए है. हर बात में अमेरिकीकरण, हर बात में चीन, हर बात में जापान, इस देश के हित में नहीं है. यहां सवा सौ करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी के एक छठवें हिस्सा हैं. भारत की कई और विशेषताएं भी हैं. पहली तो यह कि दुनिया में भारत जैसा कोई कोई दूसरा देश नहीं है, जहां इतनी विविधताओं के लोग शांति से एक साथ रहते हों. मैं केवल मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही. यहां हर कस्बे में, हर मोहल्ले में सभी तरह के लोग रहते हैं. अब ये जो हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई मुल्क एक मजहब को अलग करके चल ही नहीं सकता है. भारत जैसा देश तो कतई नहीं चल सकता है. यहां सवा सौ करोड़ की आबादी में 15 प्रतिशत मुसलमान हैं. सिख, पारसी, ईसाई हैं, वो अलग हैं. मैं तो कहता हूं कि इस तरह के भेदभाव से एक मोहल्ला, एक कस्बा तक नहीं चल सकता, आप भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए. लेकिन अब मुझे दूसरा डर सताने लगा है. गुजरात इलेक्शन भी हो जाएंगे.

मान लीजिए भाजपा जीत गई तो उनको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं. ये कहेंगे, देखो नोटबंदी को लोगों का समर्थन है. अब तो सरकार इलेक्शन मोड में चल रही है. हर सरकार चुनाव को नजर में रखते हुए लोकप्रिय फैसले लेती है. लेकिन जब आप जीत जाएं, तो देश के लिए कुछ तो काम कीजिए. एक चुनाव जीतते ही अगले चुनाव पर नजर है? उन्हें देश से कोई मतलब नहीं रहता है. हम बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं, जिसे कोई समझ नहीं रहा है. जैसे वो मेढक है, वैसे ही हम सब इंसान हैं. तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सब समझ नहीं रहे हैं. एक हालत ऐसी आ जाएगी, जब हम असहाय और हताश हो जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे. इसकी तरफ बुद्धिजीवियों को ध्यान देना चाहिए. उन्हें सरकार को सुझाव देना चाहिए कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए और कैसे देश को वापस प्रगति की राह पर लाया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

किसान और भूख की बात करना ग़द्दारी नहीं है

आपको 1975 की एक प्रमुख उक्ति याद दिलाना चाहता हूं. देश में आपातकाल लग चुका था. कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरूआ थे. देवकांत बरूआ ने एक दिन कहा, इंदिरा इज इंडिया. इंदिरा ही भारत है और पूरी कांग्रेस की टीम इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा महान हैं, इंदिरा के अलावा भारत की कल्पना नहीं की जा सकती आदि-आदि वाक्य बोलने लगे. सारे अखबार इंदिरा इज इंडिया से भर गए. इंदिरा इज इंडिया के नारे पर नाचने लगे. जनता ने इंदिरा जी को जमीन पर ला दिया. उस नारे की हवा निकल गई. ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि टेलीविजन पर अचानक हिन्दुत्व का ज्वार आ गया है. वे सारे लोग, जिन्हें हिन्दू धर्म का एबीसी भी नहीं पता, वो सब हिन्दू होकर नारे लगाने लगे. एक बार टेलीविजन के कुछ एंकरों ने या कुछ पार्टिसिपेंट्स ने इस नारे की हवा निकाल दी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से जो हिन्दू, हिन्दू चिल्लाते थे, उनसे पूछ लिया कि भाई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जो भी आप कहो, क्योंकि आप कुछ और कहते हो और देश कुछ और समझता है, लेकिन वंदे मातरम् गाकर सुना दो. सिर्फ टेलीविजन पर ही नहीं, देश के प्रमुख नेताओं से, छोटे और तृतीय दर्जे के नेताओं से भी राष्ट्रगान सुनने की पत्रकारों के बीच होड़ लग गई. अचानक पता चला कि एक व्यक्ति भी मलयज शीतलाम् शस्य श्यामलाम नहीं गा पाया. वंदे मातरम नहीं गा पाया. यहां तक कि संघ के सुप्रतिष्ठित महान विचारक, जो हर टेलीविजन पर संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी वंदे मातरम् नहीं गा पाए. मेरा ख्याल है इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस गीत को 100-200 बार कंठस्थ करने में लगे हैं.

अब एक नई चीज सोशल मीडिया पर शुरू हुई है, जिसे देखकर मैं चौंक गया. कहा जा रहा है कि वो हिन्दू, हिन्दू नहीं है, जो मोदी का साथ न दे, यानी अगर आप जय मोदी, जय मोदी नहीं करते हैं तो आप हिन्दू नहीं हैं. अब इन्हें कौन समझाए कि हिन्दू आप हैं या नहीं हैं, ये तो आप साबित कीजिए, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि हिन्दू नाम का कोई धर्म नहीं है. धर्म सनातन है और आपको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या होता है? आप अगर हिन्दू शब्द कहां से आया, ये जानना है तो श्री मोहन भागवत के विचार सुनिए. आप वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस देश में देशभक्ति को समाप्त करना चाहते हैं. आप देशभक्त हैं, आप गद्दार हैं. आप अगर देश के सवालों को उठाते हैं तो आप गद्दार हैं. लेकिन आप अगर किसानों की आत्महत्या को गाली देते हैं, गरीबों की भूख को गाली देते हैं, सिर्फ आप मोदी, मोदी कहते हैं तो आप देशभक्त हैं. ये नई चीज सोशल मीडिया पर शुरू हुई है. ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यह स्थिति बताती है कि धीरे धीरे जब तर्कशक्ति खत्म हो जाती है, जब बताने के लिए काम का ब्यौरा आपके पास नहीं होता है, जब आप इसका जवाब नहीं दे पाते कि हमने जो वादे किए थे, वो वादे कौन-कौन से थे और उनमें से कितने पूरे हुए, तब इस तरह के तर्क उभरते हैं कि अगर आप मोदी, मोदी नहीं कहते हैं, मोदी का साथ नहीं देते हैं, तो आप हिन्दू हैं ही नहीं, गद्दार हैं.

कल मैं एक कवि की कविता सुन रहा था. उसने कहा कि मैं अपने उन मित्रों से जिन्होंने किसी समय बहुत जोर-शोर से नारे लगाए थे, उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ वादों को भी याद करो, जो आपने देश के लोगों से किए थे, तो वो लोग झेंप कर हंस देते हैं. लेकिन टेलीविजन पर और जनता के बीच में झूठ का सिलसिला, झूठ का पुलिंदा जारी है. यह झूठ हमें क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि हमने मोदी जी की तरफ बड़ी आशा से देखा था. मोदी जी पर खुद करप्शन का कोई चार्ज नहीं है. मोदी जी ने गुजरात को जिस तरह से भी चलाया, राजनीति में जिनको भी ठिकाने लगाया, अलग चीज है, पर उन्होंने गुजरात को बदलने की कोशिश की. खासकर गुजरात में पानी की सिंचाई के बारे में जो उन्होंने कमाल किया, वो देश में भी करते, उनसे यह आशा थी. जब वे देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो आशा थोड़ी धूमिल हुई. शायद उनके साथियों, अधिकारियों, सचिवों या उस ब्यूरोक्रेसी के कारण धूमिल हुई, जिन्हें मोदी का दिमाग ही समझ में नहीं आया या शायद उन अति उत्साही सचिवों के कारण हुई, जिन्होंने मोदी जी को यह समझा दिया कि नोटबंदी और जीएसटी क्यों क्रांतिकारी कदम हैं? चूंकि मोदी जी ने भी उनके कहने पर लागू कर दिया, इसलिए उन्हें उसके समर्थन में तर्क देने ही थे. पर वो सारे तर्क जमीन पर उल्टे पड़ रहे हैं. उनके अपने प्रदेश गुजरात में सूरत 28 दिनों तक बंद रहा. गुजरात से ये खबरें आने लगीं कि इस चुनाव में लगभग बराबर-बराबर की लड़ाई है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था.

> गुजरात से ये हवा आने लगी है कि बिल्कुल बराबर की लड़ाई है. गुजरात में एकतरफा लड़ाई होनी चाहिए थी, पर सर्वे आने लगे कि पांच या दस सीटें इधर या उधर की होंगी. एक बड़ा चैनल, जो अब तक मोदी जी के गुणगान करता था और जिसने शुरुआती सर्वे में गुजरात में भाजपा को एकतरफा जीतता हुआ दिखाया था, अब कह रहा है कि कांग्रेस को 138 सीटें मिल सकती हैं. ये स्थिति क्यों आई? इसका विश्लेषण उनको करने की जरूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का साथ न दे वो हिन्दू, हिन्दू नहीं गद्दार है. उनको सियार की तरह हुआं-हुआं चिल्लाने दीजिए. जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल होते देखना चाहते हैं, उन्हें इस स्थिति का विश्लेषण कर इसके कारणों की तलाश करनी चाहिए. यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस देश के बहुत सारे लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास हिल जाएगा.

मोदी जी का गुजरात मॉडल सारे देश में बिका, लोगों ने गुजरात मॉडल के लिए वोट दिए, लेकिन गुजरात का मॉडल किसी भी प्रदेश में न शिवराज सिंह, न वसुंधरा राजे, न योगी और न ही रावत के प्रदेश में कहीं दिखाई दिया. इनमें से किसी ने पलट कर भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हम गुजरात मॉडल से अपने प्रदेश का विकास करेंगे. मुझे चिन्ता है कि मोदी जी की सारी अच्छाइयों और उनकी सारी कोशिशों को उनके साथियों ने तबाह कर दिया है. मैंने जितने नाम लिए और जितने बचे हुए नाम हैं, कोई गुजरात मॉडल का नाम क्यों नहीं लेता? जिसने भारतीय जनता पार्टी को केन्द्र में सत्तारूढ़ कराया, उस गुजरात मॉडल का नाम योगी जी, नीतीश कुमार, रावत जी, शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे क्यों नहीं लेती हैं? असम को छोड़ दीजिए. जितने भी नाम हैं, आप उसको इसमें जोड़ सकते हैं, पर ये प्रमुख नाम हैं. ये लोग गुजरात मॉडल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में हैं और तब मुझे लगता है कि ये सारे लोग नरेंद्र मोदी को बहकाकर या फुसलाकर असफल करना चाहते हैं. इसीलिए कृषि और संचार के क्षेत्र में यथास्थिति बनी हुई है.

आप जितने लोग हैं, जो ये कहते हैं कि मोदी-मोदी कहो, नहीं तो तुम गद्दार हो, वो खुद अपने मोबाइल पर तीन से चार बार कॉल ड्रॉप के शिकार होंगे. आप कॉल ड्रॉप कर रहे हैं, फोन नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है और आप मोबाइल के जरिए पूरा बैंकिंग सिस्टम चलाने की बात करते हैं. कम से कम उन लोगों से तो सवाल करो, जो इस कॉलड्रॉप के लिए जिम्मेदार हैं. जो इन मोबाइल कंपनियों को इतना ज्यादा पैसा दिलवाने के लिए जिम्मेदार हैं. आप एक कॉल करते हैं, तो तीन बार कॉल ड्रॉप होता है, जिसके कारण आपसे तीन कॉल के पैसे लिए जाते हैं. जाहिर है, वो तीन कॉल के पैसे मोबाइल कंपनियों को जा रहे हैं. एक कॉल के समय में आप तीन कॉल का पैसा दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है. अब अगर कोई ये कहे कि इसमें सरकार के कुछ बड़े लोगों के पास भी उसकी दक्षिणा जा रही होगी, अगर वो ये आशंका करता है, तो इसमें बुरा क्या है? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इतनी सारी बातचीत हुई, लेकिन हमारे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि हमारे देश में कितना निवेश आया और वो निवेश कहां लगा? क्या वो प्राइवेट सेक्टर में लगा या वो कंज्यूमर सेक्टर में लगा, जिसको हम कॉस्मेटिक सेक्टर कहते हैं. अच्छे-अच्छे फ्रिज, टेलीविजन और कारें सब आ रही हैं, लेकिन गरीब के खाने के लिए, रेलवे में गरीब के बैठने के लिए, रेलवे में साफ-सफाई के लिए, देश में साफ-सफाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर बनना चाहिए था, उसकी क्या हालत है? ये सब लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह कर रहे हैं. उनको ये समझा रहे हैं कि आपका विरोध करना कुछ लोगों की आदत है, इसलिए आप इसके बारे में मत सोचिए. अभी इंतजार कीजिए कि आपके ऊपर और क्या-क्या परेशानियां आने वाली हैं?

इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा देश ब्लैकमनी नहीं रखता है. हमारे देश की सारी ब्लैकमनी, जो विदेशों में थी, एक जुमला था, एक झूठ था, एक लफ्फाजी थी, जिसे आडवाणी जी, बाबा रामदेव और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने मिलकर 2014 में देश को बेचा था. हमने उस कालाधन पर, उस छिपे हुए धन पर कोई वार नहीं किया, जो विदेशों में था. हमने ये मान लिया कि ये सारा कालाधन इस देश के लोगों के पास है, इसलिए आपने नोटबंदी कर दी. अब रिजर्व बैंक या बैंकों के लोग ये समझ नहीं पाए कि हमको कितना रुपया लेना है, कितना नहीं लेना है? जितना रुपया दिया था, उससे ज्यादा रुपया आ गया. फिर आप कहने लगे कि नहीं, नहीं, उतना नहीं, जितना हमने दिया था, उससे ज्यादा नहीं आया, उतना ही आया है. तो फिर कहां गई फेक करेंसी, कहां गए नकली नोट, कहां गया कालाधन, इस सवाल को मत पूछिए. अब कह रहे हैं कि जो पैसा बैंकों में आया, हम उसकी पहचान कर रहे हैं.

एक मंत्री टेलीविजन पर कह रहे थे, आपको क्यों बुरा लगता है कि जो पैसा ब्लैकमनी था या जो कालाधन था या जो फेक करेंसी थी, वो पूरी की पूरी आ गई. अब उसे यह कहते हुए शर्म नहीं आई कि फेक करेंसी हमारे खजाने में आ गई और हमने उसे चलन में ला दिया, तब ये तो नोटबंदी मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन इस पर सवाल मत उठाइए. अगर आप सवाल उठाएंगे तो गद्दार हो जाएंगे, फिर फेसबुक पर कैम्पेन चलेगा कि जो मोदी का साथ न दे, वो गद्दार है. इंदिरा इज इंडिया. इसलिए मैंने शुरू में कहा था इंदिरा इज इंडिया, जो नारा उस समय कांग्रेस ने लगाया था, कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया था और जिसका परिणाम 1977 में देखने को मिला. मैं नहीं चाहता हूं कि वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिले. नरेंद्र मोदी से अब भी बहुत आशा है. नरेंद्र मोदी में क्षमता है, वो कर सकते हैं, पर ये जो आस-पास महान बुद्धिमानों की चौकड़ी जमा है, चाहे वो मंत्रिमंडल या अधिकारियों या उनकी पार्टी में हों, उनसे निजात पाने की जरूरत है. तभी वो इस देश के विकास के लिए कुछ सोच पाएंगे, अन्यथा जो स्थिति आज गुजरात में हो गई है, वो होनी ही नहीं चाहिए थी.

गुजरात से ये हवा आने लगी है कि बिल्कुल बराबर की लड़ाई है. गुजरात में एकतरफा लड़ाई होनी चाहिए थी, पर सर्वे आने लगे कि पांच या दस सीटें इधर या उधर की होंगी. एक बड़ा चैनल, जो अब तक मोदी जी के गुणगान करता था और जिसने शुरुआती सर्वे में गुजरात में भाजपा को एकतरफा जीतता हुआ दिखाया था, अब कह रहा है कि कांग्रेस को 138 सीटें मिल सकती हैं. ये स्थिति क्यों आई? इसका विश्लेषण उनको करने की जरूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का साथ न दे वो हिन्दू, हिन्दू नहीं गद्दार है. उनको सियार की तरह हुआं-हुआं चिल्लाने दीजिए. जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल होते देखना चाहते हैं, उन्हें इस स्थिति का विश्लेषण कर इसके कारणों की तलाश करनी चाहिए. यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा इस देश के बहुत सारे लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास हिल जाएगा. विपक्ष की तो मैं बात ही नहीं करता. विपक्ष तो इस समय कहीं है ही नहीं. अगर कहीं कोई है, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. वो खुद अपने लिए विपक्ष तैयार न करें, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं भी देनी चाहिए और ईश्वर से कहना चाहिए कि उनमें इतनी सन्मति आए कि वो इन अंतर्विरोधों को पहचान सकें और अपने लिए और देश के लिए करेक्टिव मेजर्स उठा सकें. अभी डेढ़ साल हैं, कम नहीं हैं. बहुत कुछ किया जा सकता है. इंदिरा इज इंडिया के तरीकों से बचिए. ■

editor@chauthiduniya.com

सहारनपुर के दलितों से भेदभाव कर रही यूपी सरकार

दोहरे अत्याचार का शिकार

एसआर दारापुरी

सहारनपुर के दलित दोहरे अत्याचार का शिकार हो रहे हैं. सभी भलीभांति अवगत हैं कि 5 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव के दलितों के घरों पर उस क्षेत्र के सामंतों ने हमला किया था. इसमें लगभग दो दर्जन दलित बुरी तरह से घायल हुए थे और 50 से अधिक घर बुरी तरह से जला दिए गए थे. उक्त हमले में रविदास मंदिर की मूर्ती तोड़ी गई थी और मंदिर को बुरी तरह से जलाया तथा क्षतिग्रस्त किया गया था. उस हमले में एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसने रविदास मंदिर के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर मंदिर को जलाया था तथा मूर्ती तोड़ी थी. दम घुटने के कारण मंदिर से बाहर निकलते ही वो बेहोश हो गया था. इसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने दलित बस्ती पर हमला किया था. हमले में दो दर्जन के करीब दलित बुरी तरह से घायल हुए थे. कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी भी हुई और ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर घरों को जलाया गया. पालतू पशुओं को भी नुकसान पहुंचा था.

जिस समय दलित बस्ती पर हमला किया गया, उस समय पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन उसने भी रोकने के बजाय हमलावरों को तांडव करने का खुला मौका दिया. जन मंच और स्वराज अभियान समिति की साझा जांच में यह बात सामने आई थी कि पुलिस ने दंगाइयों को मौका दिया था. पुलिस की भूमिका दलितों के प्रति दुर्भावनापूर्ण रवैये का सबूत है. इतना ही नहीं पुलिस ने दलितों के विरुद्ध पांच मुकदमे भी दर्ज कर दिए, जिनमें 9 दलितों को नामज़द किया गया. लेकिन दलितों की तरफ से केवल एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमे 9 लोगों को नामज़द तथा काफी अन्य को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद पुलिस के द्वारा आठ दलितों और हमलावर पक्ष के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद एक अन्य दलित को भी गिरफ्तार किया गया परन्तु दूसरे पक्ष से किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं की गई. जबकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम को बताया था कि उन्होंने लगभग 40 हमलावरों को चिन्हित कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी. लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई. इसके लगभग तीन हफ्ते बाद जब मायावती शब्बीरपुर गईं, तो उस दिन जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण शब्बीरपुर से लौट रहे एक दलित लड़के की हत्या कर दी गई. इस मामले में केवल दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई.

पुलिस के पक्षपाती रवैये का इससे बड़ा क्या सुबूत हो सकता है कि पुलिस ने पिटने वाले दलित और पीटने वाले सामंती दबंगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया. बराबर की गिरफ्तारियां की गईं. दो दलितों तथा दो हमलावरों पर एनएसए लगा दिया गया. सभी जेल में हैं. परिस्थितियों से पूरी तरह स्पष्ट है कि दलितों ने अपने बचाव में जो भी पथराव किया, वह आत्मरक्षा में किया था. परन्तु दलितों द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को भी हमले के ही रूप में लिया गया और उनकी गिरफ्तारियां की गईं, जबकि आईपीसी की धारा 100 में प्रत्येक नागरिक को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है. इस प्रकार एक तो दलितों पर अत्याचार किया गया और दूसरे पुलिस ने उन्हें आत्मरक्षा के अधिकार का लाभ न देकर गिरफ्तार किया. इस प्रकार दलित दोहरे अत्याचार का शिकार हुए हैं.

औरतों ने यह भी बताया था कि हमलावरों के पास गुब्बारे थे, जिसे फेंक कर आग लगाई गई थी. इससे स्पष्ट है कि दलितों पर हमला पूर्व नियोजित था. जांच समिति ने इसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में भी किया, परन्तु पुलिस ने इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया. प्रशासन द्वारा दलितों के घरों तथा सामान के नुकसान का आकलन कराया गया था, लेकिन अब तक जो मुआवजा दिया गया है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है. जो दलित नामज़द हैं और जेल में हैं उन्हें न तो सरकार की तरफ से नुकसान की भरपाई हेतु कोई मुआवजा मिला और न ही एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह-राशि ही मिली. इसके इलावा गिरफ्तार हुए दलितों को निजी वकील रखने पर भी खर्च करना पड़ रहा है.

पुलिस के पक्षपाती रवैये का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि पुलिस ने पिटने वाले दलित और पीटने वाले सामंती दबंगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया. दोनों पक्ष से गिरफ्तारियां की गईं. दो दलितों तथा दो हमलावरों पर एनएसए लगा दिया गया. सभी जेल में हैं. परिस्थितियों से पूरी तरह स्पष्ट है कि दलितों ने अपने बचाव में जो भी पथराव किया, वह आत्मरक्षा में किया था.

यह भी उल्लेखनीय है कि दलितों पर हुए हमले की घटना से एक दिन पहले ही आभास हो गया था कि महाराणा प्रताप जयंती पर दलितों पर हमला हो सकता है. ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों तथा एसडीएम को दे दी थी, परन्तु दलितों की सुरक्षा के लिए पुलिस का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया. इसके साथ ही जब 9 मई को भीम आर्मी ने प्रशासन द्वारा शब्बीरपुर में हुए हमले के सम्बन्ध में वांछित कार्रवाई न करने पर विरोध जताने की कोशिश की, तो पुलिस द्वारा बलप्रयोग किया गया. इस पर भीम आर्मी के सदस्यों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ होने पर भीम आर्मी के संयोजक चन्द्रशेखर तथा उसके साथियों के विरुद्ध 21 मुक़दमे दर्ज कर लिए गए. इसके बाद चन्द्रशेखर सहित 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. जिनमें से 2 लोग अभी तक जेल में हैं. चन्द्रशेखर और वालिया को छोड़ कर भीम आर्मी के अन्य गिरफ्तार सदस्यों की जमानत हो चुकी है. इन दोनों की जमानत जिला स्तर से रद्द हो चुकी है और अब यह इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है. जेल में चन्द्रशेखर की सेहत बराबर गिर रही है और 28 अक्टूबर को उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था.

भीम आर्मी के दमन का ताज़ा उदहारण यह है कि कुछ दिन पहले जब भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, तो उसके जेल से छूटने के पहले ही उस पर रासुका लगा दिया गया. दरअसल योगी सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर किसी भी हालत में जेल से बाहर आए, क्योंकि उसके बाहर आने पर दलितों के लामबंद होने का खतरा है. सरकार की यह कार्रवाई रासुका जैसे काले कानून का खुला दुरुपयोग है. इस कानून के अंतर्गत आरोपी को बिना किसी कारण के एक साल तक जेल में रखा जा सकता है. यह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है.

साफ है कि सहारनपुर में शब्बीरपुर के दलित आत्मरक्षा में कार्रवाई करने पर भी गिरफ्तार किए गए और उनकी गिरफ्तारियां हमला करने वाले लोगों के समतुल्य ही की गईं. रासुका के मामले में भी उन्हें हमलावरों के समतुल्य रखा गया है. पीड़ित दलितों को बहुत कम मुआवजा दिया गया और जो दलित मुकदमों में नामज़द हैं, उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला. इस प्रकार शब्बीरपुर के दलित एक तरफ सामंतों के हमले का शिकार हुए हैं तो दूसरी ओर वे प्रशासन के पक्षपाती रवैये का भी शिकार हो रहे हैं. इसके अलावा भीम आर्मी के दो सदस्य अभी भी जेल में हैं और तीन दर्जन से अधिक नवयुवक पुलिस से भिड़ंत के मुकदमे झेल रहे हैं. पुलिस ने भीम आर्मी के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी के लिए 12000 का इनाम घोषित कर रखा है. सरकार द्वारा हमलावरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई न करने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं और वे अभी भी दलितों को धमका रहे हैं. ■

-(लेखक जन मंच के संयोजक और स्वराज अभियान समिति के सदस्य हैं)

स्मारक की ज़मीन पर दे दिया दूसरे को पट्टा

सन्तोष देव गिरि

जमीन हथियाने की होड़ में शहीदों के परिजनों को भी नहीं बख्शा जा रहा है. हद तो यह है कि ऐसा करते हुए उन सरकारी मुलाजिमों को जरा भी शर्म नहीं आती, जो जमीन और कागजों की हेराफेरी में लिप्त हैं. मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का है, जहां देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीद के परिजनों को 8 साल बाद भी स्मारक की जमीन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. हालत यह है कि शहीद की स्मृति में स्मारक बनाने के लिए दी गई जमीन भी दूसरे को पट्टे में दे दी गई है. मिर्जापुर जनपद के मड़िहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरद निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान रहे गिरिजाशंकर मौर्या 25 मार्च 2009 को असम में उग्रवादियों से हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे. देश की रक्षा में शहीद होने वाले गिरजाशंकर का शव जब गांव ककरद पहुंचा, तब हजारों लोगों की भीड़ ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी. मौके पर मौजूद तत्कालीन उपजिलाधिकारी मड़िहान डॉ. विश्राम ने शहीद गिरजाशंकर का स्मारक बनाने के लिए चार बिस्वा जमीन देने की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद चार बिस्वा जमीन शहीद जवान के पुश्तैनी गांव ककरद में देने की बात कही गई थी. मजे की बात यह है कि शहीद गिरजाशंकर के परिजन घोषणा की गई जमीन पर पिछले 8 वर्षों से स्मारक बनाने का इंतजार करते चले आ रहे हैं, जिनकी उम्मीद अब निराशा में बदलने लगी है. मगर सरकारी लापरवाही के कारण उपजिलाधिकारी का यह आदेश जारी नहीं हो पाया है. पिछले 8 वर्षों से यह जमीन खाली पड़ी रही. शहीद के परिजन तब हैरान रह गए, जब ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा शहीद के लिए छोड़ी गई जमीन का पट्टा दूसरे को कर दिया गया. मजे की बात यह है कि शहीद स्मारक के नाम पर दी गई जमीन पर स्मारक का निर्माण न होकर पट्टाधारक ने जमीन पर ईंट गिरा कर मकान का निर्माण करना शुरू कर दिया. शहीद स्मारक के लिए छोड़ी गई जमीन पर निर्माण कार्य होते देख शहीद के परिजन भी हैरान हो गए. आनन-फानन में वे न्याय की गुहार लगाने के लिए अधिकारियों के पास पहुंच गए. शहीद की फोटो के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची शहीद गिरजाशंकर की बेवा पत्नी व परिजनों ने जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे से मिलकर स्मारक के लिए छोड़ी गई जमीन पर ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा किए गए पट्टे का विरोध करते हुए स्मारक के लिए जमीन को उनके चंगुल से मुक्त कराने की मांग की है. जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने शहीद के परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. वहीं अधिकारियों के अनुसार उस दौरान तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने मौके पर स्मारक बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन नियमों के मुताबिक उस जमीन का पट्टा शहीद के परिजनों को नहीं मिल पाया था. ऐसे में यह आदेश मौखिक ही रह गया था. जमीन के कागजात भी शहीद के परिजनों को नहीं मिल पाए थे. फिलहाल गलती किसकी है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा. लेकिन शहीद की स्मृति में स्मारक बनने का इंतजार कर रहे ग्रामीण और परिजन निराश हो चुके हैं. वे अब जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल की भूमिका को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब शहीद के नाम पर भी जमीन को बक्शा नहीं जा रहा है, तो आम आदमी की जमीनों का क्या हाल होता होगा. अब तो शहीद के परिजनों को यह डर सता रहा है कि देश की रक्षा में प्राण गवां चुके शहीद कुलदीप का स्मारक बनाने का उनका सपना अधूरा न रह जाए. ■

देश की रक्षा में शहीद होने वाले गिरजाशंकर का शव जब गांव ककरद पहुंचा, तब हजारों लोगों की भीड़ ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी थी. मौके पर मौजूद तत्कालीन उपजिलाधिकारी मड़िहान डॉ. विश्राम ने शहीद गिरजाशंकर का स्मारक बनाने के लिए चार बिस्वा जमीन देने की घोषणा की थी.

अब बांग्लादेशी डकैतों से यूपी आक्रांत, 'राष्ट्रवादी' सरकार नाकाम

इनके लिए भी देश नहीं, वोट ज़रूरी...

- असम से फ़र्ज़ी पहचान पत्र बनवा कर यूपी आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए
- असम नहीं भेजी जा सकी 12 सौ बांग्लादेशी घुसपैठियों की दूसरी सूची
- यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ कार्रवाई के लिए तैयार
- यूपी पुलिस ने 17 सौ की लिस्ट भेजी, असम पुलिस दबा कर बैठ गई
- यूपी, असम और केंद्र में भाजपा सरकार, राष्ट्रहित का मसला दरकिनार
- पर सरकार नहीं दे रही घुसपैठियों के निष्कासन का आदेश

प्रभात रंजन दीन

यूपी पुलिस निकाय चुनाव में व्यस्त बांग्लादेशी घुसपैठ में

उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश ही विचित्र राजनीतिक विरोधाभासों में फंसा हुआ है. राष्ट्रवादी भावनाएं भड़का कर वोट की राजनीति होती है, लेकिन राष्ट्रहित के लिए जरूरी प्राथमिकताओं पर कोई काम नहीं होता. बांग्लादेशी घुसपैठियों का छह साल का पूरा ब्यौरा हासिल करने के बावजूद उन्हें निकालने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही. सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हो रहा. कभी कहा जाता है कि सरकार समीक्षा में लगी है, तो अब कहा जा रहा है कि सरकार निकाय चुनावों में व्यस्त है. स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी निकाय चुनावों में ही व्यस्त है. इन्हीं टालू व्यस्तताओं में उत्तर प्रदेश बांग्लादेशी घुसपैठियों का स्वर्ग बनता जा रहा है. उधर असम की हालत यह है कि वहां बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को मुद्दा बना कर भाजपा चुनाव जीत लेती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे घुसपैठ का मसला याद नहीं रहता. यूपी पुलिस द्वारा किए गए भंडाफोड़ के बाद असम पुलिस से इस सिलसिले में जरूरी सहयोग मांगा गया था, लेकिन असम पुलिस को यूपी पुलिस के आधिकारिक पत्र का जवाब देने की भी फुर्सत नहीं है. यह है असम की भाजपा सरकार की राष्ट्रवादी असलियत. असम से यह पचड़ा फंसा दिया गया है और इधर निकाय चुनाव में सरकार और पुलिस की व्यस्तता का तर्क दिया जा रहा है. लखनऊ पुलिस के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि केवल लखनऊ में तकरीबन एक लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं. इसी क्रम में 1700 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहली सूची असम पुलिस को भेजी गई थी, जिन्होंने अपना नाम-पता असम का दे रखा है और उनका पहचान-पत्र भी असम के विभिन्न जिलों से हासिल किया हुआ है. यूपी पुलिस की सूची पर असम पुलिस से जवाब मिलने के बाद बांग्लादेशियों को शहर से बाहर खदेड़ने की कवायद शुरू होती, लेकिन बीच में ही इसमें अड़ंगा डाल दिया गया. यूपी पुलिस की ओर से सूची भेजे हुए कई महीने हो गए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया. असम पुलिस का जवाब मिलने के बाद यूपी पुलिस की तरफ से दूसरी सूची भेजी जाती, लेकिन सारी प्रक्रिया अधर में लटक गई है. लखनऊ पुलिस के एक आला अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की दूसरी सूची बन कर तैयार थी, लेकिन पहली सूची के सत्यापन की प्रतीक्षा में दूसरी सूची अभी नहीं भेजी जा रही. दूसरी सूची में भी 12 सौ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम है, जिनकी बाकायदा पहचान कर उन्हें सूची में शामिल किया गया है. दूसरी सूची में भी उन बांग्लादेशियों के नाम हैं, जिन्होंने अपना पहचान-पत्र असम से बनवा रखा है. इस प्रकरण का सबसे दुखद किंतु मजाकिया पहलू यह है कि यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की शिनाख्त कर उन्हें खदेड़ बाहर करने का राजनीतिक डायलॉग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही प्रसारित किया था. इसके बाद ही यूपी पुलिस हरकत में आई थी, लेकिन सत्ता अलमबरदार अपना संवाद जारी कर सो गए. नतीजतन पूरी प्रक्रिया सो गई. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ की चिनहट और गाजीपुर पुलिस ने सक्रिय होकर बांग्लादेशी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा. पकड़े गए लोगों ने यह कबूला कि बांग्लादेशी असम के बरपेटा जिले से फर्जी पहचान पत्र बनवाकर यूपी के विभिन्न जिलों में घुस रहे हैं. इस महत्वपूर्ण सूचना के बावजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों और आतंकियों को पकड़ने का काम नहीं हो रहा है. निकाय चुनाव सरकार की प्रथम प्राथमिकता है. पुलिस अधिकारियों से पूछिए तो जवाब मिलेगा, 'हम तो तैयार ही बैठे हैं, हमें तो बस शासन के आखिरी औपचारिक आदेश का इंतजार है'. ■

रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर चिल्लपों करने और राजनीति का रायता बिखेरनी वाली भाजपा सरकार अवैध बांग्लादेशियों की बढ़ती जा रही भीड़ को नियंत्रित करने या उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने में कोई रुचि नहीं ले रही है. केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और असम में भाजपा सरकार है, लेकिन तीनों सरकारें अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर लचर रवैया अख्तियार किए हुई हैं. यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी विभिनन अपराधों में लिप्त हैं. पकड़े भी जा रहे हैं और उनके असम से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के कनेक्शन आधिकारिक तौर पर उजागर हो रहे हैं, लेकिन न असम सरकार उनका ब्यौरा भेजने में कोई सक्रियता दिखा रही है और न केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय पुलिस और प्रशासन तंत्र को कोई सहयोग कर रहा है. यहां तक कि लखनऊ पुलिस ने जिन अवैध बांग्लादेशियों का छह साल का ब्यौरा जुटा रखा है, उन बांग्लादेशियों को भी वापस खदेड़ने को लेकर यूपी की भाजपा सरकार मौन ही साधे हुई है.

बांग्लादेशी घुसपैठिए असम से जाली पहचान पत्र बनवा कर आते हैं और उत्तर प्रदेश में अपराध करते हैं. लखनऊ के गोमतीनगर में एक साथ हुई कई भीषण डकैतियों के एक मामले की छानबीन में लखनऊ पुलिस को बांग्लादेशियों के जाली पहचान पत्र बनाने वाले अड्डे की जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक असम में इन्हें भारतीय पहचान पत्र बनाकर दिया जा रहा है. इसी पहचान पत्र के सहारे बांग्लादेशी अपराधी भारतीय नागरिक के आवरण में पुलिस की नजर से बच निकलते हैं. जाली पहचान पत्र बनाने के गोरखधंधे की छानबीन के लिए लखनऊ पुलिस की टीम असम भी गई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई. गोमतीनगर में ताबड़तोड़ हुई तीन डकैतियों में अवैध बांग्लादेशियों के उसी गैंग की भूमिका पाई गई, जिसने डेढ़ साल पहले एल्डिको ग्रीन कॉलोनी में भीषण डाका डाला था. उस घटना में शामिल चार बांग्लादेशी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरोह के पांच सदस्य गायब हो गए थे. पुलिस का कहना है कि उन्हीं गायब बांग्लादेशियों ने गोमतीनगर में एक साथ कई घरों में डाके डाले. इन बांग्लादेशी बदमाशों का सीधा सम्पर्क दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले बांग्लादेशियों से है. पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि बांग्लादेशियों को स्थानीय लोगों ने अपना रिश्तेदार या परिचित बता कर शरण दे रखा है. छानबीन में उनके पास से भारतीय पहचान पत्र मिले हैं, जबकि उनकी बोल-चाल और उनके रहन-सहन से उनके बांग्लादेशी होने की पुष्टि होती है. कई बस्तियां बसा कर उनमें मजदूरों के वेश में रह रहे इन बांग्लादेशियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है. इन अवैध बस्तियों को हटाने के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और नगर निगम को 20 से ज्यादा पत्र भेजे जा चुके हैं. लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. विचित्र बात यह है कि नगर निगम ने खुद बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशियों को ही नगर की सफाई के काम में लगा रखा है. निगम को मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार मजदूरों की पहचान लिए बगैर उन्हें सफाई के काम में लगा देते हैं. मामला उजागर होने के बाद अब उन मजदूरों की पहचान कराने के लिए ठेकेदारों से कहा जा रहा है. इस काम में भी ढिलाई का आलम यह है कि निगम अभी मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार कर रहा है. जब ठेकेदारों की सूची बन जाएगी तब उनसे मजदूरों की आईडी और उनकी पहचान से जुड़े दूसरे दस्तावेज मांगे जाएंगे. उसके बाद मजदूरों के परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा लिया जाएगा. तब जाकर बांग्लादेशियों की नागरिकता का असली साक्ष्य प्राप्त होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी. नगर निगम का रोना यह है कि इस प्रक्रिया से नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी. इस तरह मामले को जानबूझ कर लटका कर रखा जा रहा है.

आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में लगे बांग्लादेशियों की धड़-पकड़ में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और एंटी टेररिस्ट स्कवायड (एटेस) सक्रियता से लगी हुई है. अभी हाल ही लखनऊ एसटीएफ ने मेरठ के कस्बा फलावदा से एक बांग्लादेशी घुसपैठिया अबू हन्नान उर्फ अबू हना को दबोचा, जो न केवल अवैध रूप से भारत में रह रहा था बल्कि वह आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त था. वह बांग्लादेशी अपराधियों को नकली भारतीय पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र दिलाने का धंधा भी करता था. उसके पास से कई नकली भारतीय पासपोर्ट और पहचान पत्र बरामद हुए, साथ ही अन्य कानूनी कागजात भी मिले हैं. अबू हना कोलकाता, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, लुधियाना समेत कई जगहों पर रह कर अपना धंधा चला रहा था. उसने वर्ष 2006 में फलावदा की रहने वाली शबाना से शादी कर ली थी. शादी के बाद लड़की के पते का इस्तेमाल वह अपने धंधे के लिए कर रहा था. उस पते पर बने कई फर्जी कानूनी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. यह भी भेद खुला कि फर्जी पासपोर्ट पर उसने अपने बांग्लादेश में रहने वाले भाई मसूद राणा की आईडी से बांग्लादेश का वीज़ा हासिल किया और भारतीय नागरिक के बतौर बांग्लादेश आता-जाता रहा. पुलिस का कहना है कि अबू हना ने अपनी बीवी शबाना को सऊदी अरब शिफ्ट कर दिया है, जहां वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है. शबाना के मेरठ के पते पर पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र और वोटर कार्ड भी थे. गिरफ्तार अबू हन्नान के खिलाफ थाना फलावदा में मामला दर्ज कर एसटीएफ मामले की तहकीकात कर रही है.

उधर एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में लगे बांग्लादेशियों का पर्दाफाश किया. एटीएस ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन चला कर एक बांग्लादेशी आतंकी को गिरफ्तार किया. सहारनपुर स्थित देवबंद के एक मदरसे के तीन छात्रों को भी उनकी संदिग्ध हरकतों के कारण हिरासत में लिया गया. पकड़ा गया आतंकी भी देवबंद के एक मदरसे का पूर्व छात्र है और काफी समय से देवबंद में रहा था. एटीएस ने एसटीएफ की टीम के साथ मुजफ्फरनगर के चरथावल के कुटेसरा गांव में छापा मारकर बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला अल मामून, पुत्र रहीसुद्दीन अहमद, निवासी हुसनपुर, जिला मोमिनशाही बांग्लादेश को गिरफ्तार किया. वह देवबंद में रहकर बांग्लादेश के आतंकियों के लिए फर्जी आईडी से पासपोर्ट बनवाता था. इसमें बांग्लादेशी फैजान उसका सहयोग करता था. फैजान के भी आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है. उसकी तलाश हो रही है. यह भी खुलासा हुआ कि अदुल्ला बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्ला-बांग्ला से जुड़ा है. अब्दुल्ला देवबंद में आतंकियों को सुरक्षित आश्रय भी देता था. एटीएस की टीम ने देवबंद से जिन तीन संदिग्ध युवकों को पकड़ा, उनमें दो युवक कश्मीर के है और एक बिहार का है. पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, विभिनन ग्राम प्रधानों, ग्राम विकास अधिकारियों, तहसीलदारों और निर्वाचन कार्यालय की मुहरें भी बरामद की गईं. यह भी पता चला कि पकड़ा गया आतंकी छह साल से सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव अंबेहटा शेख में रह रहा था. कुछ दिनों पहले वह चरथावल के कुटेसरा गांव में रहने लगा था. एटीएस के एक आला अधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरनगर से मोहम्मद आदिल की गिरफ्तारी के बाद से ही अब्दुल्ला की तलाश की जा रही थी. आदिल संदीप शर्मा के नाम से रह रहा था. अभी हाल ही एटीएस ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन से तीन बांग्लादेशियों मोहम्मद इमरान पुत्र अब्दुल खालिक, रजीदुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिक, मो. फिरदौस पुत्र अब्दुल खालिक को गिरफ्तार किया है. ये तीनों सगे भाई हैं. इनकी गिरफ्तारी अब्दुल्ला मामून से मिले सुराग के आधार पर की गई. तीनों बांग्लादेश भागने की फिराक में थे और हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस पर सवार थे. इनके पास से नकली आधार कार्ड और कई फर्जी कानूनी दस्तावेज बरामद किए गए.

अब्दुल्ला एटीएस के सामने यह कबूल कर चुका है कि बांग्लादेश के कई युवक त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आ रहे हैं और दलालों की मदद से भारत का पहचान पत्र बनवा रहे हैं. अब्दुल्ला खुद 2011 में त्रिपुरा बॉर्डर से भारत में घुसा था और सहारनपुर में पासपोर्ट बनवाने के लिए 9 हजार रुपए दिए थे. उसने अपना पहचान पत्र असम के गांव नासत्रा, थाना अभयपुरी बोंगाईगांव जिले से बनवाया था. अब्दुल्ला के पास से उर्दू और बांग्ला में इस्लामिक जेहाद से जुड़े दस्तावेज और साहित्य के अलावा आईएसआईएस सरगना कुख्यात आतंकी अबू बकर बगदादी का घोषणा पत्र, बम बनाने की किताब और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं. बांग्लादेशी अपराधियों और आतंकियों की धर-पकड़ के सिलसिले में ही यूपी पुलिस को प्रतापगढ़ से छह बांग्लादेशियों को धर-दबोचने में कामयाबी मिली. सभी आधा दर्जन बांग्लादेशी प्रतापगढ़ जिले में डेरा जमाए हुए थे. बांग्लादेशियों ने नवाबगंज के लवाना इलाके में एक गेस्ट हाउस का कमरा किराए पर ले रखा था. बांग्लादेशियों का कहना था कि वे सऊदी अरब जाने के क्रम में प्रतापगढ़ के किसी मनोज पटेल से मिलने के लिए गेस्ट हाउस में रुके थे. वे जून में ही भारत आ गए थे और अवैध रूप से ही इधर-उधर घूम रहे थे. प्रतापगढ़ पुलिस मनोज पटेल की भी तलाश कर रही है. ■

DR R.K GUPTA
DR P.K JOSHI
DR A.S CHANDEL

feedback@chauthiduniya.com

VASTU DOORS
सुरक्षा का वादा
www.vastudoors.com
* मजबूत
* दीमकरोधी
* सीलनरोधी
* जंकरोधी
by वास्तु विहार®

FINAL TOUCH
by वास्तु विहार®
अब, घर सजाने की बारी...
Phone : 7280023037, 9534095340

छात्र नेता कन्हैया कुमार की तारीफ़ कर बुरे फंसे भोला बाबू

कन्हैया बहाना भाजपा टिकट निशाना

सुरेश चौहान

बेगूसराय में भाजपा का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. लोकसभा चुनाव के बाद से ही किसी न किसी मुद्दे के कारण यहां भाजपा के मंच पर विरोध के स्वर सुनाई पड़ते रहे हैं. ताजा विवाद पैदा हुआ है, कन्हैया कुमार के लिए सांसद डॉ भोला सिंह की दरियादिली को लेकर. कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाजपा का अंतरद्वन्द्व खुलकर मंच पर दिखाई दिया. भाजपा के वरिष्ठ नेता सांसद डॉ भोला सिंह एवं पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बिहार विधान परिषद में सचेतक, विधान पार्षद रजनीश कुमार ने एक-दूसरे पर जमकर जुबानी प्रहार किया. दिनकर भवन में उपस्थित महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने डॉ भोला सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी की. भोला सिंह वापस जाओ के भी नारे लगे. इसके बाद डॉ भोला सिंह को भाषण पूरा किए बिना ही मंच छोड़ना पड़ा. जिले की राजनीति में डॉ भोला सिंह की इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी. दरअसल, भाजपा नेता भोला सिंह ने कन्हैया कुमार की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी और उन्हें देशभक्त बताया था. सांसद भोला सिंह ने कहा था कि भगत सिंह को भी उस समय की अंग्रेज सरकार देशद्रोही माना करती थी जैसे कि आज की सरकार कन्हैया कुमार को मानती है. जिस प्रकार आज भगत सिंह को कोई भी देशद्रोही नहीं मानता, उसी तरह मैं भी कन्हैया को दोषी नहीं मानता हूं. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि सरकार को कन्हैया कुमार गुनहगार लगते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ सबूत पेश करे.

जिले में एक तरह से भाकपा का राजनीतिक अवसान हो चुका है. पार्टी को पुन: स्थापित करने के लिए भाकपा जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो कन्हैया बेगूसराय में भाजपा के लिए चुनौती बनेंगे. लेकिन भाजपा सांसद भोला सिंह ने ही कन्हैया की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए. उन्होंने भगत सिंह से उनकी तुलना कर दी और कहा कि कन्हैया देशद्रोही नहीं है. संयोग से इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर तीन नवम्बर को ही (कैलाशपति मिश्र की पुण्य तिथि के दिन) अखबार में प्रकाशित हुई. भोला सिंह द्वारा कन्हैया को देशभक्त बताए जाने से भाजपाइयों में आक्रोश था. भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर दिनकर भवन में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें जिले के 150 पुराने भाजपा कार्यकर्त्ताओं को सम्मानित किया जाना था. समारोह में डॉ भोला सिंह एवं रजनीश कुमार सहित सभी स्थानीय नेता आमंत्रित थे. डॉ भोला सिंह एवं रजनीश कुमार दोनों मंच पर विराजमान भी थे. श्रद्धांजलि सम्बोधन के लिए जब रजनीश कुमार की बारी आई, तो उन्होंने तीखे स्वर में डॉ भोला सिंह को इंगित करते हुए कहा कि ये कन्हैया कुमार को देशद्रोही नहीं मानते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं, जबकि भाजपा उसे देशद्रोही मानती है. उसे देशद्रोही नहीं कहना पार्टी का अपमान है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार के इतना कहते ही कार्यकर्ता सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. इसके बाद सांसद भोला सिंह मंच से उठकर जाने लगे. तब जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने स्थिति को सामान्य बनाया और मान-मनौवल के बाद सांसद ने पुन: स्थान ग्रहण किया. रजनीश कुमार ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि मेरी बातों से यदि किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. अब बारी थी भोला सिंह की. सांसद ने अपने सम्बोधन में फिर से वही दोहराया कि कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है, वो भी देशभक्त है. भोला सिंह के इतना कहते ही दिनकर भवन की गैलरी से काफी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्त्ता उबल पड़े और भोला सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डायस के सामने आ गए. लाचार भोला सिंह को अपना सम्बोधन बीच में ही छोड़ना पड़ा. इसके बाद जिलाध्यक्ष ने घोषणा की कि कन्हैया कुमार को देशद्रोही नहीं कहना भोला सिंह की व्यक्तिगत राय है. भाजपा कन्हैया कुमार को देशद्रोही मानती है. राष्ट्रीय सचिव रजनीश कुमार फिर से उबल पड़े. उन्होंने भोला सिंह द्वारा कन्हैया की तुलना भगत सिंह से किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी करनी है, तो बाहर जाकर करिए, क्योंकि इस प्रकार की बातें करना भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी नेता का कद पार्टी में कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन इस प्रकार के बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रजनीश कुमार ने यहा तक कह दिया कि इस प्रकार के बयान न सिर्फ जन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी मानसिकता को भी दर्शाते हैं. कई नेताओं ने भोला सिंह के इस बयान का कड़ा विरोध किया और वे सभा का बहिष्कार करते हुए वहां से निकल गए. इन सबके बाद पार्टी के वरीय नेताओं ने सांसद भोला सिंह को वहां से सुरक्षित निकाला.

सांसद डॉ भोला सिंह के विरोध में नारेबाज़ी व हंगामा करते भाजपा कार्यकर्ता

भोला सिंह और रजनीश कुमार का सियासी टकराव

सिमरिया धाम का कुंभ आयोजन और भोला सिंह द्वारा छात्र नेता कन्हैया कुमार की तुलना अमर शहीद भगत सिंह से करना इस वाक्युद्ध का तात्कालिक कारण बना. लेकिन सियासी हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कुंभ और कन्हैया तो बहाना है, अगामी लोकसभा चुनाव निशाना है. कहा जा रहा है कि भोला सिंह के बयान को लेकर शुरू हुए विवाद के मूल में 2019 का चुनाव है, जिसमें भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर खिंचातानी हो रही है. ऐसे तो बेगूसराय में भाजपा तीन खेमों में विभाजित है. एक खेमे का नेतृत्व विधान पार्षद रजनीश कुमार कर रहे हैं. वहीं दूसरा खेमा सांसद डॉ भोला सिंह के हाथ में है. दोनों खेमों से अलग तीसरा खेमा कार्यकर्ताओं का है. डॉ भोला सिंह एवं रजनीश कुमार के बीच चल रहे संघर्ष को जानने के लिए थोड़ा पीछे झांकना होगा.

बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड में एक पार्टी कार्यकर्त्ता की हत्या हो गई थी. डॉ भोला सिंह ने आरोप लगाया कि इसमें रजनीश कुमार की संलिप्तता है. फिर इसके बाद सिमरिया धाम में चल रहा कुंभ मेला मुद्दा बना. रजनीश कुमार कुंभ आयोजन समिति के महासचिव हैं. भोला सिंह ने कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि देश में चार ही कुंभ स्थल हैं, जिसमें सिमरिया कुंभ का कहीं नाम नहीं है. इस कुंभ को फ्लॉप बताते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ आयोजन के नाम पर राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है और मेले में अवैध वसूली हो रही है. ऐसा भी नहीं है कि भोला सिंह और रजनीश कुमार की सियासी टकराहट हाल के दिनों में सामने आई है. इससे पहले भी ये दोनों नेता आमने-सामने आते रहे हैं. गत लोकसभा चुनाव के समय से ही डॉ भोला सिंह और रजनीश कुमार के बीच मनमुटाव जारी है. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में रजनीश कुमार को भाजपा पार्टी प्रत्याशी बना सकती है. रजनीश कुमार अंदरखाने चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं. इस तरह से वे भोला सिंह के लिए बड़ी सियासी चुनौती पेश कर रहे हैं. भोला सिंह किसी भी स्थिति में यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं कि उनका सीटिंग एमपी का टिकट काटकर किसी और को दिया जाय. इसके लिए वे पूरी तरह से रजनीश कुमार को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में लगे हैं. कुंभ आयोजन की कुव्यवस्था उजागर करना इन्हीं कोशिशों की कड़ी है. लेकिन भोला सिंह की इन कोशिशों पर कन्हैया की तारीफ हावी हो गई और वे अब खुद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

सांगठनिक मर्यादा के नजरिए से देखें, तो कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर भाजपा के नेताओं की सार्वजनिक जुबानी जंग को जायज नहीं कहा जा सकता. कैलाशपति मिश्र बिहार में जनसंघ एवं भाजपा के संस्थापकों में से एक रहे हैं. पार्टी संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया. ऐसे महान नेता की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों को संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए था. लेकिन हुआ इसके विपरीत. अब तक पर्दे के पीछे चल रही भाजपाइयों की गुटबाजी इस घटना से उजागर हो गई. अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गुटबाजी से भाजपा को कितना नफा-नुकसान होता है. भाजपा इस मुगालते में है कि गत लोकसभा चुनाव में उसके प्रत्याशी की जीत हुई थी, तो इसबार भी इस सीट पर उसका ही कब्जा होगा. जबकि हकीकत इससे विपरीत है. पिछली बार राजद-कांग्रेस और जदयू-भाकपा गठबंधन के कारण चुनावी टिकट से वंचितों ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाकर मतदान किया था. इस बार तो भाजपाइयों की आंतरिक गुटबाजी ही बेगूसराय में पार्टी की जीत को पलिता लगा सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम
मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....
AL™
अलीगढ़ लॉक्स
प्रा.लि.
पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
❖ अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान ❖ नक्कालों से सावधान
❖ कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...
PERFECT Exterior Emulsion
JOHNSON Exterior Emulsion
JOHNSON PAINTS INDUSTRIES

आधी आबादी की आवाज़

महिलाओं का हक़ है 33 फ़ीसदी आरक्षण

नूतन-सुरभि-खुशबू

भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति हो रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार को खत्म करने एवं इनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 12 सितबंर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था. तब से लेकर आज तक महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने का यह मुद्दा चर्चा में रहा है. महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को लेकर काफी विवाद भी हुआ. कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिससे यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है. सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाया है कि वे सदन में महिला आरक्षण का समर्थन करेंगी. उनका मानना है कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. सियासत में तो इसे लेकर चर्चा होती ही रही है,'चौथी दुनिया' ने इस मुद्दे पर आधी आबादी की राय जानने की कोशिश की है. हमने अलग-अलग क्षेत्र की कुछ महिलाओं से बात की और यह जानने की कोशिश की कि उन्हें महिला आरक्षण से क्या उम्मीदें हैं.

वरिष्ठ अधिकारी **राखी चक्रवर्ती** कहती हैं कि महिला आरक्षण महिलाओं के विकास और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन शायद ही कोई सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है. महिलाओं को सरकार केवल वोट का जरिया समझती है. अगर ऐसा नहीं होता, तो आज महिलाएं हर क्षेत्र की भांति राजनीति में भी बड़ी तादाद में होतीं. मेरा मानना है कि सभी दलों को इस मामले में अपना दिल बड़ा करना चाहिए और सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पास कराने का प्रयास करना चाहिए.

सरकारी स्कूल में शिक्षिका **अनिता सिंह** का कहना है कि सरकार को शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पास करा देना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा. 33 फीसदी आरक्षण से महिलाओं के हौसले बुलंद होगें और वे मजबूती के साथ सियासत में कदम रखेंगी. मेरी इच्छा है कि हजारों-लाखों महिलाओं का यह सपना जल्द से जल्द पूरा हो.

एक निजी कंपनी में मैनेजर **सुरभि विशाल** कहती हैं कि हमारे यहां महिलाओं को हर क्षेत्र में दबाया जाता है और उन्हें आजादी के साथ काम नहीं करने दिया जाता. अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होता है, तो इससे राजनीति में तो महिलाएं सशक्त होंगी ही, अन्य क्षेत्रों में भी उनकी स्थिति में सुधार होगा. राजनीति के जरिए व्यवस्था का अंग बनने वाली महिलाएं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की परेशानियों को बखूबी समझ सकती हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकती हैं.

आकाश संस्थान में बैंकिंग एस्पिरेशन के पद पर कार्यरत **सवेरा सिंह** का कहना है कि बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुधार कर पाना मुश्किल है. वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व है. वहां महिलाओं के लिए आगे आना काफी मुश्किल है. महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाने और इसके कानून बन जाने के बाद राजनीतिक दलों की यह मजबूरी हो जाएगी कि वे अपने दल में महिलाओं को तवज्जो दें. इसलिए हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द-से-जल्द पास हो, ताकि लोकतंत्र में महिलाओं की सियासी भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

पीएसी में ब्लॉक हेल्थ मैनेजर **अर्चना कुमारी** का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से लेकर सेना तक में महिलाएं अपनी काबिलियत का परिचय दे रही हैं. लेकिन राजनीति में उनकी भगीदारी अब भी अधूरी है. अब तक जो महिलाएं राजनीति में पहचान बनाने में सफल हुई हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी पुरुष के सहारे आगे बढ़ी हैं. अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होता है, तो इसके जरिए आम महिलाएं भी राजनीति में अपना मुकाम बना सकती हैं.

डॉ. मधुमिता कहती हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, तो फिर राजनीति में भी उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए. महिला आरक्षण वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है. आज जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में खुलकर सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर उन्हें राजनीति में समान अवसर मिले, तो वे अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकती हैं. राजनीति में आकर सरकार और व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद वे महिलाओं के अधिकारों के हनन पर भी रोक लगाने का काम करेंगी. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि वो अपनी आधी आबादी को लोकतांत्रिक शासन पद्धति का हिस्सा बनाए.■

feedback@chauthiduniya.com

गुटबाज़ी की भेंट चढ़ा राजद का सांगठनिक चुनाव

सुनील सौरभ

बिहार की राजनीति में एकाएक सता से बेदखल हो विपक्ष में आए राष्ट्रीय जनता दल में भी अब पद के लिए हंगामा शुरू हो गया है. पहले प्राय: पार्टी के विभिन्न पदों पर लोगों को मनोनयन करने की परंपरा रही है. लेकिन अब राजद में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया (दिखावे के लिए ही सही) के सहारे संगठन का चुनाव कराया जा रहा है. फिलहाल मगध के पांच जिलों में राजद प्रखंड से लेकर जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव कराने में लगा है. लेकिन बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मगध में राजद का यह सांगठनिक चुनाव गुटबाजी की भेंट चढ़ गया.

चुनाव को लेकर कई स्थानों पर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनने के लिए राजद कार्यकर्ता हंगामा करते देखे गए. संगठन चुनाव को लेकर नेता-कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट पर उतारू हो गए. अपने-अपने नेताओं के समर्थन में खूब नारेबाजी भी हुई. मगध की राजनीति के केंद्र बिन्दु गया जिले के कुल 24 प्रखंडों और एक नगर निगम क्षेत्र को मिलाकर कुल 25 प्रखंड अध्यक्ष और प्रत्येक प्रखंड से 2-2 डेलीगेट्स का चुनाव होना था. इसे लेकर 2 नवंबर 2017 को बोधगया के बिरला धर्मशाला में बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में राजद चुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सूबेदार दास और सहायक निर्वाची पदाधिकारी भाई अरुण कुमार निर्धारित समय से दो घंटे देरी से पहंचे और जिला राजद अध्यक्ष के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कराई. इसके बाद दो गुटों में बंटे राजद कार्यकर्ता अपने-अपने नेता के समर्थन में हंगामा और नारेबाजी करने लगे. स्थिति मारपीट तक पहुंच गई. माहौल बिगड़ता देख निर्वाची पदाधिकारी ने चुनाव को स्थगित कर दिया. पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद यासिर और निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहम्मद निजाम इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार थे. दोनो में से किसी ने भी आम सहमति से जिला अध्यक्ष पद का निर्वाचन नहीं होने दिया. प्रखंड अध्यक्ष, डेलीगेट्स तथा कार्यकर्ता सभी दो गुटों में बंटकर पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हंगामा करते रहे. अंत में गया जिला राजद अध्यक्ष पद पर मनोनयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंपने की बात पर दोनों गुट सहमत हो गए. पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता डॉ विनोद कुमार यादवेन्दु ने कहा है कि जिला अध्यक्ष पद के लिए दो दावेदारों के आ जाने और सर्वसम्मति की स्थिति नहीं बनने के कारण जिला अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के बाद गया जिला राजद अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी.

जिला राष्ट्रीय जनता दल, गया

राजद के स्थापना काल से ही मगध के पांच जिलों में अध्यक्ष के मनोनयन में माय समीकरण का ख्याल रखा गया है. हालांकि गया में समय-समय पर माय समीकरण से हटकर भी जिला अध्यक्ष होते रहे हैं. जहानाबाद जिले में राजद के स्थापना काल से ही मुजफ्फर हुसैन राही जिला अध्यक्ष हैं. नवादा जिले में महेन्द्र यादव लगातार तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. अरवल में रंजन यादव राजद जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, वहीं औरंगाबाद में कौलेश्वर यादव राजद के स्थापना काल से ही अध्यक्ष पद पर काबिज हैं. मगध राजद का एक मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है. यहां की 26 विधानसभा सीटों में से 11 राजद के कब्जे में हैं. सिर्फ गया के ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 राजद के पास है. यही कारण है कि मगध में किसी जिले का राजद अध्यक्ष होना प्रतिष्ठा का विषय माना जा जाता है. इसी को लेकर गया में राजद जिला अध्यक्ष पद के लिए दो दावेदारों में ठनी हुई है. गौर करने वाली बात यह भी है कि अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और दोनों की ही अपने समुदाय में अच्छी पकड़ है. वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद निजाम की पत्नी शगुफ्ता परवीन अभी वार्ड पार्षद हैं. वे गया नगर निगम की मेयर भी रही हैं. मगध की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजद विधायक और पूर्व मंत्री डॉ सुरेन्द्र प्रसाद यादव मोहम्मद निजाम के करीबी भी माने जाते हैं. वहीं पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद यासिर भी डॉ सुरेन्द्र प्रसाद यादव के समर्थक हैं. यही कारण है कि जब दोनों दावेदारों में अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए विवाद हुआ, तो सुरेन्द्र प्रसाद यादव निष्पक्ष भूमिका में आ गए. तब निर्वाची पदाधिकारी सुबेदार दास ने दोनों गुटों की सहमति लेकर गया जिला राजद अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पाले में डाल दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध राजद का एक मजबूत राजनीति गढ़ माना जाता है. यहां की 26 विधानसभा सीटों में से 11 राजद के कब्जे में हैं. सिर्फ गया के ही 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 राजद के पास है. यही कारण है कि मगध में किसी जिले का राजद अध्यक्ष होना प्रतिष्ठा का विषय माना जा जाता है. इसी को लेकर गया में राजद जिला अध्यक्ष पद के लिए दो दावेदारों में ठनी हुई है.

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
- बचत
- मजबूती
- शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770
CRM TMT Fe-500

पैदल चाल और सही डायट
स्वस्थ जीवन की कुंजी
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
जहानाबाद ऑर्थोपेडिक्स एण्ड फ्रेक्चर सेन्टर, हॉस्पिटल मोड़

डॉ. दिनेश कुमार
एमबीबीएस,एमएस ऑर्थो (सर्जन)

जहानाबाद से डॉ. दिनेश कुमार जिनका हॉस्पिटल मोड़ के पास क्लिनीक है ने अपने इन्टरव्यू के दौरान बताया कि आजकल लोग आराम पसंद हो गये हैं आराम पसंद जॉब करना चाहते तो हैं ही साथ ही घर में भी ज्यादातर सोफा, बेड पर बैठकर अपना जीवन का ज्यादा समय व्यतीत करते हैं यही कारण है कि आजकल के लोगों में नसों की हड्डीयों की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा ज्यादा समय कम्प्यूटर पर काम करने से भी पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। या किसी भी व्यक्ति को जो सही पॉश्चर में नहीं बैठता है उसे यह समस्या आ सकती है। डॉ. दिनेश ने बताया कि बच्चों ये समस्या आने की वजह कैल्शीयम की कमी होना, खेल-खेल में चोट लगना, कहीं कोई नस का दब जाना इत्यादि है परंतु बड़े लोगों में इसका कारण बैलेंस डायट नहीं लेना सही वर्किंग स्टाइल में काम नहीं करना माना गया है। डॉ. दिनेश ने पैदल चलने, मेहनत वाला काम करने तथा खान पान में दही, पनीर, हरी शब्जी, दाल, इत्यादि का सेवन करें जिससे शरीर में कैल्शियम व वीटामीन डी की कमी पूरी हो सके। लेने योग्य आहार- आहार से विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा ले पाना असंभव है। सूर्य के प्रकाश से सीधा सम्पर्क ही आपके शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है। वसायुक्त मछली, जिगर का मॉस, अंडे की जर्दी, शक्ति मिश्रित दूध, डेरी उत्पाद और सन्तरे का रस। शक्ति मिश्रित अनाज और मक्खन। शक्ति मिश्रित सोया उत्पाद (टोफू और सोया दूध) पनीर, मशरुम, ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

सम्मान के बहाने अंतर्विरोधों पर नज़र

अनंत विजय

उम्र के नब्बे पड़ाव पार कर चुकी लेखिका कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का एलान किया गया. ज्ञानपीठ सम्मान देने वाली जूरी के अध्यक्ष नामवर सिंह हैं. यह उनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष है. उनके पुरस्कार के एलान के बाद साहित्यिक हलके में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर दो बार इस पुरस्कार के लिए मना करने के बाद कृष्णा जी ने इसको स्वीकार कैसे और क्यों कर लिया. साहित्य जगत में हो रही चर्चा के मुताबिक, एक बार कृष्णा जी को किसी अन्य भारतीय भाषा के लेखक के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था. दूसरी बार जब हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तब भी कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की चर्चा चली थी, लेकिन उस बार भी उन्होंने मना कर दिया था. साहित्य जगत की इस चर्चा में कितनी सत्यता है, ये तो ज्ञानपीठ की जूरी के सदस्य या फिर कृष्णा जी ही बता सकती हैं, लेकिन इस बार के उनके स्वीकार के पीछे ज्ञानपीठ के निदेशक और ज्ञानपीठ पुरस्कार के संयोजक लीलाधर मंडलोई की भूमिका या निर्विवाद छवि हो सकती है.

> कृष्णा सोबती जी हिंदी की बेहद समादृत लेखिका हैं, लेकिन वो काफी विवादित भी रही हैं. हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर उनके विवादित बयान को अब भी याद किया जाता है. कृष्णा जी ने एक बार कहा था कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पुरस्कार आदि तय किए जाते हैं. कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन उनकी चर्चा इस वक्त उचित नहीं है. यह इसी पृष्ठभूमि का नतीजा है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर कृष्णा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. कोई उनके उम्र को लेकर तंज कस रहा है, तो कोई उनके स्वीकार को लेकर हैरान है. दरअसल हिंदी में बड़े पुरस्कारों के साथ यह समस्या है कि वो ज्यादातर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड की तरह हो गए हैं. ज्ञानपीठ की बात को छोड़ भी दें, तो ज्यादातर पुरस्कार अब लेखक की उम्र को देखकर दिए जाते हैं. यहां तक कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में लेखन के साथ-साथ उम्र को देखा जाने लगा है.

कृष्णा सोबती जी हिंदी की बेहद समादृत लेखिका हैं, लेकिन वो काफी विवादित भी रही हैं. हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर उनके विवादित बयान को अब भी याद किया जाता है. कृष्णा जी ने एक बार कहा था कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पुरस्कार आदि तय किए जाते हैं. कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन उनकी चर्चा इस वक्त उचित नहीं है. यह इसी पृष्ठभूमि का नतीजा है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर कृष्णा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. कोई उनके उम्र को लेकर तंज कस रहा है, तो कोई उनके स्वीकार को लेकर हैरान है. दरअसल हिंदी में बड़े पुरस्कारों के साथ यह समस्या है कि वो ज्यादातर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड की तरह हो गए हैं. ज्ञानपीठ की बात को छोड़ भी दें, तो ज्यादातर पुरस्कार अब लेखक की उम्र को देखकर दिए जाते हैं. यहां तक कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में लेखन के साथ-साथ उम्र को देखा जाने लगा है. कोलकाता की लेखिका अलका सरावगी को साहित्य अकादमी देने के बाद इस पुरस्कार में कोई ऐसा नाम नहीं आया जो कि सिर्फ कृति को ध्यान में रख कर दिया गया हो. ज्यादातर पुरस्कार भूल गलतियों को सुधाने के लिए दिए गए. यही हाल दिल्ली की हिंदी अकादमी के पुरस्कारों की भी है. वहां भी उम्र को एक मानक माना जाने लगा है. जबकि पुरस्कार देने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बेहतरीन कृति आई हो, तो उसको पुरस्कृत किया जाए. भगवानदास मोरवाल का उपन्यास काला पहाड़ ऐसी ही एक कृति है, लेकिन साहित्य अकादमी उस वक्त उनको पुरस्कृत करने का साहस नहीं दिखा पाई.

यह हिंदी साहित्य के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि नब्बे साल की उम्र के आसपास या उससे पार के कई लेखक अब भी रचनात्मक रूप से सक्रिय हैं और अभी भी अपनी रचनात्मक मौजूदगी और सक्रियता से पूरे परिदृश्य में सार्थक हस्तक्षेप कर रहे हैं. नामवर सिंह तो अब भी गोष्ठियों की शान हैं. रामदरश मिश्र लगातार अपने लेखन से समकालीन साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप कर रहे हैं. अभी हाल ही में कृष्णा जी के संस्मरणों की पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी हिंदी जगत में खूब चर्चा हुई. कृष्णा जी ना केवल रचनात्मक रूप से सक्रिय हैं, बल्कि राजनीतिक-साहित्यिक मोर्चे पर भी बेहद सक्रिय हैं. उनकी ये सक्रियता आश्वस्तिकारक भी है. पिछले दिनों जब पूरे देश में असहिष्णुता के खिलाफ कुछ लेखकों ने आंदोलन और पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया था, तो उसके बाद दिल्ली में देशभर के लेखकों का एक जमावड़ा हुआ था. कृष्णा सोबती जी उस जमावड़े में पहुंची थीं और उन्होंने अपनी बात रखी थी. उस वक्त देश में कथित तौर पर बढ़ रहे असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार वापसी अभियान को कृष्णा सोबती की भागीदारी से बल मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है. उनकी भागीदारी का जनमानस पर कितना असर हुआ इस पर मतभिन्नता हो सकती है. लेखक के तौर पर उनको अपनी बात कहने का हक है और साहित्य से इतर राजनीति पर भी अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है. कृष्णा सोबती के इस अधिकार का उनके वैचारिक विरोधियों ने भी सम्मान किया. कथित असहिष्णुता के खिलाफ उनके इस कदम को लेकर खासी चर्चा हुई थी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी. लेकिन उसी के आसपास उन्होंने खुद पर लिखी एक किताब के विमोचन को टलवाने के लिए नई लेखिका पर सिर्फ इसलिए दबाव बनाया था, क्योंकि उनकी विचारधारा से अलग विचार रखने वाले लोग भी उस मंच पर थे. यह एक किस्म की अस्पृश्यता थी. इसपर भी विस्तार से चर्चा हुई थी और हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी इसपर लेख प्रकाशित हुए थे.

इसके पहले भी कृष्णा जी और अमृता प्रीतम के बीच केस मुकदमा चले थे. कृष्णा सोबती ने अमृता प्रीतम पर उनकी कृति हरदत्त का जिंदगीनामा को लेकर केस किया था. वो केस करीब 25 साल तक चला था और फैसला अमृता प्रीतम के पक्ष में आया था. दरअसल अमृता प्रीतम की किताब हरदत्त का जिंदगीनामा जब छपा तो कृष्णा जी को लगा कि ये शीर्षक उनके चर्चित उपन्यास जिंदगीनामा से उड़ाया गया है और वो कोर्ट चली गईं. साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कृष्णा सोबती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी गईं अमृता प्रीतम के बीच इस साहित्यिक विवाद की उस वक्त पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी. जब केस का फैसला अमृता जी के पक्ष में आया तबतक अमृता प्रीतम की मौत हो गई थी. केस के फैसले के बाद कृष्णा सोबती ने बौद्धिक संपदा का तर्क देते हुए कहा था कि हार जीत से ज्यादा जरूरी उनके लिए अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए संघर्ष करना था. उस वक्त भी कई लेखकों ने कृष्णा सोबती को याद दिलाया था कि जिंदगीनामा का पहली बार प्रयोग उन्होंने नहीं किया था. कृष्णा सोबती के उपन्यास के पहले फारसी में लिखी दर्जनों किताबें इस शीर्षक के साथ मौजूद हैं. मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने तो उस वक्त भी कहा था कि श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य ने उनकी जीवनी भी जिंदगीनामा के नाम से लिखी थी और ये किताब कृष्णा सोबती के उपन्यास के काफी पहले प्रकाशित हो चुकी थी. जिंदगीनामा को लेकर कैसी बौद्धिक संपदा का गुमान और उसको लेकर कैसा विवाद और केस मुकदमा. लेकिन विवाद तो हुआ ही था.

इसी तरह से जब रवीन्द्र कालिया ने एक संस्मरण लिखा था, तब भी कृष्णा जी ने काफी आपत्ति जताई थी और एक तरह से विवाद खड़ा किया था. बेहतर रचानाकार और विवादप्रियता के अलावा कृष्णा जी में ह्यूमर भी था. मुझे याद पड़ता है कि दिल्ली में लेखक से मिलिए कार्यक्रम में एक बार कृष्णा जी थीं. उस कार्यक्रम में भारत भारद्वाज ने उनसे एक सवाल पूछा था कि कृष्णा जी की नायिकाएं इतनी बोल्ड और बिंदास दिखती हैं, वो आजाद ख्याल भी हैं और अपने कपड़ों आदि में आधुनिक भी, तो कृष्णा जी खुद इतना लंबा चोगानुमा ड्रेस क्यों पहनती हैं. कृष्णा जी ने इस प्रश्न को मजाकिया लहजे में टालते हुए उत्तर दिया था कि भारत जी आप देखना क्या चाहते हैं और पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया था. ये उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है.

हम वापस लौटते हैं, ज्ञानपिठ पुरस्कार पर. दरअसल ज्ञानपीठ की चयन प्रक्रिया बेहद जटिल है. इसकी शुरुआत होती है, करीब चार हजार लेखकों और संस्थाओं से प्रस्ताव मंगवाने से. उन प्रस्तावों को फिर भाषावार छांटा जाता है. फिर तेइस भाषाओं की सलाहकार समिति के पास इन प्रस्तावों को भेजा जाता है, जहां से उनसे दस नाम मांगे जाते हैं. उन नामों को फिर जूरी के सदस्यों के सामने रखा जाता है और वो अपनी सम्मति देते हैं. उन सम्मतियों के आधार पर जिस नाम पर सहमति बनती है या जिनको सबसे अधिक जूरी के सदस्य चाहते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है. टाई होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास वीटो पॉवर होता है. इसके अलावा जूरी के सदस्यों को आधार सूची से अलग नाम प्रस्तावित करने का भी अधिकार होता है. ऐसे में किसी तरह की सेटिंग की गुंजाइश बहुत कम रहती है. इस बार भी कृष्णा जी के नाम के साथ अमिताभ घोष का नाम भी था. उनके नाम पर भी जूरी में व्यापक चर्चा हुई लेकिन जूरी के 5 सदस्यों ने कृष्णा जी के नाम पर सहमति दी और तीन ने अमिताभ घोष के नाम पर. जाहिर है चयन कृष्णा जी का ही होना था. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

ऐसे करें व्यवसायीकरण में अनियमितता की पड़ताल

चौथी दुनिया ब्यूरो

व्यवसायिक गतिविधियों में होने वाली अनियमितताएं आए दिन खबरों में जगह पाती हैं. आम लोगों के फायदे की बात कहकर सरकारी व्यवस्था और सरकारी सम्पदा का बेजा इस्तेमाल किया जाता है. इससे जनता के हित को तो झटका लगता ही है, बाजार भी प्रभावित होता है. व्यवसायीकरण के मामले में फर्जीवाड़े की हद ये है कि कई बार सरकारी कानूनों और नियमों की अनदेखी कर के किसी को भी जगह-जमीन या संसाधन अलॉट कर दिए जाते हैं. आरटीआई के माध्यम से ऐसे मामलों की तह तक पहुंचा जा सकता है. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप व्यवसायीकरण के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का पता लगा सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया..... क्षेत्र में व्यवसायीकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी भवनों की सूची प्रदान करें, जिनका उपयोग कानून का उल्लंघन करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.
2. ऐसे प्रत्येक मामले में किस तरह के कानूनों का और किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है? इसका विवरण दें. आपके विभाग को इन उल्लंघनों के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली?
3. इन उल्लंघनों की जानकारी मिलने के बाद इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इसका पूरा विवरण दें.
4. कृपया उन नियमों, कानूनों और सरकारी आदेशों की जानकारी दें, जिनका आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उल्लंघन हुआ है.
5. आवासीय संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में निर्धारित सजा अथवा नियम के मुताबिक की जाने वाली कार्रवाई का विवरण दें.
6. ऐसे प्रत्येक मामले में आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रत्येक घटना का अलग-अलग पूरा विवरण दें. यदि किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?
7. मैं ऐसे प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों व फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे दिन, समय तथा स्थान के बारे में सूचित करें जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं.
8. उन अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क का विवरण बताएं, जो इन व्यवसायीकरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं.
9. क्या ये अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13(घ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के उल्लंघन के दोषी हैं?
10. इन अधिकारियों के खिलाफ अब आगे कब और क्या कार्रवाई की जाएगी?
11. उपरोक्त क्षेत्र से दिनांक..... से..... के दौरान आपके विभाग को व्यवसायीकरण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं..... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

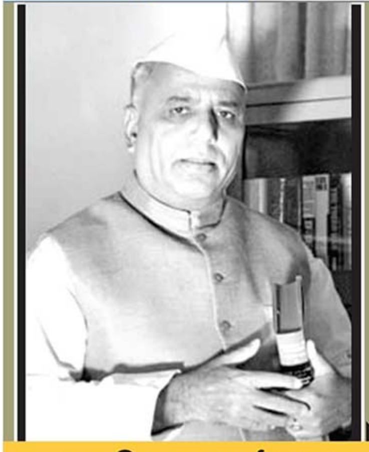

पुण्यतिथि विशेष

महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और विपक्ष के पहले नेता यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण

जन्मदिन– 12 मार्च 1913
पुण्यतिथि– 25 नवम्बर 1984

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ, लेकिन हमारे लोकतंत्र को पहला विपक्षी नेता मिला 1977 में और वो थे यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण. वाईबी चव्हाण महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और भारत के पांचवे उप प्रधानमंत्री थे. वे एक मजबूत नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे. जनहित के लिए सदैव आगे रहने की प्रतिबद्धता ने उन्हें आम लोगों के नेता के रूप में स्थापित किया. उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में समाजवादी लोकतंत्र की पुरजोर वकालत की. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा स्थापित की गईं सहकारी समितियां कृषि कल्याण के क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित हुईं.

वाईबी चव्हाण का जन्म 12 मार्च 1913 को महाराष्ट्र के सतारा जिले (वर्तमान सांगली) के देवराष्ट्रे नामक गांव के एक मराठा किसान परिवार में हुआ था. बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया. मां ने उनके चाचा के सहयोग से उनका पालन–पोषण किया. आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का सबक वाईबी चव्हाण को विरासत में मिला. बचपन से ही वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभावित थे. प्रतिकूल पारिवारिक स्थिति के बावजूद यशवंतराव अपनी शिक्षा पूर्ण करने में सफल रहे. उन्होंने 1938 में बंबई विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में बीए की पढ़ाई पूरी की. इस अवधि के दौरान वे कई सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहे. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी रही. 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उनपर जुर्माना लगाया गया. 26 जनवरी 1932 को यशवंतराव ने सतारा में भारतीय ध्वज फहराया, जिसके कारण उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई. यशवंतराव 1940 में सतारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने. 1941 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की. अगले साल ही यानि 1942 में सतारा जिले के फल्टन में वेनूताइ से उनका विवाह हो गया. इसी साल हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक मुंबई अधिवेशन में उन्होंने बतौर प्रतिनिधि भाग लिया. इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया गया था. इसमें भाग लेने के कारण यशवंतराव को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वे 1944 में जेल से रिहा हुए.

यशवंतराव 1946 में दक्षिण सतारा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए. उसी वर्ष उन्हें बम्बई राज्य के गृह मंत्री के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. 1953 में वे नागपुर समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसमें महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों के समान विकास का आश्वासन दिया गया था. 1957 में यशवंतराव कराड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधाई पार्टी के नेता के रूप में निर्वाचित हुए और द्विभाषी बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री बने. 1957 से 1960 तक उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के रूप में चुना गया. संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था. 1 मई 1960 को यशवंतराव महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने. संपूर्ण महाराष्ट्र का औद्योगिक व कृषि विकास उनका सपना था. उन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से इस सपने को पूरा करने की दिशा में काम किया. मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत निकायों तथा कृषि भूमि सीमांकन अधिनियम के संबंध में कानून पारित किए गए. यशवंतराव चव्हाण केन्द्र की सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे. गृह, रक्षा, वित्त तथा विदेश मामलों का मंत्रालय संभालने के बाद वे भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने. 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया, तब पंडित नेहरू ने यशवंतराव को महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाया और उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया. युद्ध के बाद की नाजुक स्थिति का दृढ़ता से सामना करते हुए उन्होंने सशस्त्र बलों के सशक्तिकरण हेतु कई निर्णय लिए और पंडित नेहरू के साथ मिलकर चीन के साथ युद्ध विराम पर वार्ता की. सितम्बर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी यशवंतराव रक्षा मंत्री थे.

अगले आम चुनाव में यशवंतराव चव्हाण नासिक निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने गए. 14 नवम्बर 1966 को उन्हें देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया. इसके बाद 26 जून 1970 को वे भारत के वित्त मंत्री और 11 अक्टूबर 1974 को विदेश मंत्री बनाए गए. आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया. 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनने पर यशवंतराव विपक्ष के नेता बने. यशवंतराव भारतीय ससंद के इतिहास में पहले विपक्ष के नेता थे, क्योंकि उससे पहले किसी भी दल को उतनी सीटें नहीं मिल सकी थीं कि उसे विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके.

1978 के अंत में बैंगलोर के वार्षिक सत्र में कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई. कांग्रेस (इंदिरा) तथा कांग्रेस (उर्स). देवराज उर्स, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, एके एंटनी और शरद पवार जैसे नेताओं के साथ यशवंतराव कांग्रेस उर्स में शामिल हुए. इंदिरा गांधी से अलग होने का निर्णय लेने के बाद यशवंतराव के राजनीतिक करियर को एक बड़ा झटका लगा. जल्द ही कांग्रेस (उर्स) विघटित हो गई और देवराज उर्स स्वयं जनता पार्टी में शामिल हो गए. इसके बाद कांग्रेस (उर्स) का नाम बदलकर भारतीय कांग्रेस (समाजवादी) रख दिया गया. प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रीमंडल में यशवंतराव भारत के गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री बने. 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस (आई) ने संसद में बहुमत प्राप्त किया और इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की. इस चुनाव में यशवंतराव एक सांसद के रूप में महाराष्ट्र से निर्वाचित होने वाले एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे, जो कांग्रेस (समाजवादी) के टिकट पर जीत कर आए थे. 1981 में यशवंतराव चौहान कांग्रेस (आई) में वापस आए और 1982 में उन्हें भारत के आठवें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

यशवंतराव चव्हाण साहित्य में भी दिलचस्पी लेते थे. उन्होंने मराठी साहित्य मंडल की स्थापना की और मराठी साहित्य सम्मेलन का समर्थन किया. वे कई कवियों, संपादकों और लेखकों के साथ काफी करीब थे. उन्होंने तीन खंडों में अपनी आत्मकथा लिखने की योजना बनाई थी, जिनके नाम भी तय हो गए थे. पहले खंड में उनके बचपन से शुरुआती दिनों का जिक्र था, चूंकि उनका घर कृष्णा नदी के किनारे था इसलिए उन्होंने पहले खंड को कृष्णा कथ नाम दिया था. दूसरे खंड का नाम सागर तीर था, क्योंकि यह उनके महाराष्ट्र में बिताए गए समय पर आधारित था. अंतिम दिनों में वे दिल्ली में रहे थे और आत्मकथा का तीसरा खंड उनकी इन्हीं दिनों की जिंदगी के बारे में था, इसलिए उसे यमुना कथ नाम दिया जाने वाला था. लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी आत्मकथा का केवल प्रथम खंड ही पूरा हो पाया. 25 नवम्बर 1984 को 71 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से यशवंतराव चव्हाण का दिल्ली में निधन हो गया. उनके सम्मान स्वरूप 1985 में मुंबई में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान स्थापित किया गया. वहीं 1989 में उनके नाम पर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. ■

दूसरा पहलू

मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं...

जितने अजीब भैय्या हैं, उतने ही विचित्र उनके सवाल होते हैं. इस बार छूटते ही उन्होंने यह सवाल दाग दिया कि हमारे नेता चुनाव के मौसम में ही एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में क्यों जाते हैं? अजीब सवाल है भाई! अब इस मौसम में नहीं जाएंगे, तो कब जाएंगे? दरअसल ये पार्टियां उनके लिए ऐसी ट्रेनें होती हैं, जो हर घंटे, हर दिन या हर हफ्ते तो आती नहीं हैं. एक बार आ के निकल गई, तो पूरे पांच साल लग जाते हैं उन्हें वापस आने में. ऊपर से ऐसे–ऐसे तुर्रम खां इन पर सवारी करने के लिए बेचैन रहते हैं कि किसका नंबर आएगा और किस का नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती. हमारे नेता अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद की उधेड़बुन से बाहर निकलने के लिए इस मौसम में कबीर के अनुयाई बन जाते हैं और इस दोहे का अक्षरश: पालन करते हैं कि 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अब...' कबीर के अनुसरण के उनके अंदाज़ भी निराले हैं. कई ऐसे हैं, जिनके पास एक ट्रेन का टिकट है, लेकिन उसके बावजूद वे किसी दूसरी ट्रेन में बैठने के जुगाड़ में लगे रहते हैं. कई ऐसे हैं, जो आख़िर–आख़िर तक यह ज़ाहिर नहीं होने देते कि वे किस गाड़ी में सवार होंगे. कई ऐसे हैं, जो एक गाड़ी में बैठकर रास्ते में ही उतर जाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई बेहतर एक्सप्रेस गाड़ी मिल जाए. कई तो ऐसे भी होते हैं, जो पांच साल पहले जिस एक्सप्रेस गाड़ी की सवारी कर चुके होते हैं उसका टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में लोकल ट्रेन पकड़ने को ही लालायित रहते हैं. लोकल ट्रेन पकड़ने के बाद वे इस ताक में रहते हैं कि 2–3 बड़ी गाड़ियों में भिड़ंत हो जाए, ताकि उनकी लोकल ट्रेन सबसे पहले मंज़िल तक पहुंच जाए.

यह तो हुई उनके गाड़ी बदलने की बात. अगर बात सिर्फ़ यहीं तक रहती, तो कोई बात नहीं थी. बात इसलिए और आगे जाती है, क्योंकि गाड़ी बदलने के साथ–साथ उनके रंग भी बदल जाते हैं. मसलन काला रंग लाल हो जाता है, लाल हरा बन जाता है और पीला नीला हो जाता है. रंगों का रंग उनके सिर इस तरह चढ़ता है कि एक खास रंग के अलावा कोई भी रंग दिखाई नहीं देता. हम इसे कलर ब्लाइंडनेस कैसे कह सकते हैं, यह तो एक बीमारी है ना? लेकिन अब रंगों की बात निकल ही आई है, तो लगे हाथ एक और वाक़या आपकी नज़र करता चलूं. किस्सा यूं है कि इस खेल में दो पार्टियां ऐसी हैं, जिनकी नज़दीकी उतनी ही है, जितनी पृथ्वी के दो ध्रुवों में है. एक ने अगर पूरब को पूरब कह दिया, तो दूसरा मर जाएगा, लेकिन उसे पश्चिम साबित करके दम लेगा. उनमें से एक पार्टी ने अपने दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए यह हिटलरी फरमान जारी किया कि चूंकि पीला रंग हमारे विरोधियों का है, इसलिए पार्टी दफ्तर के आसपास पीला रंग दिखाई नहीं देना चाहिए. बस फिर क्या था, उसके बाद पीले रंग को टकसाल बाहर किया गया और पूरे देश में पार्टी समर्थकों ने पीले रंग के ख़िलाफ़ अभियान शुरू कर दिया. उनका यह अभियान अब तक जारी हैं, लेकिन यह देखना अभी बाक़ी है कि देश में पीले रंग का क्या हश्र होता है.

लेकिन भैय्या को रंगों से क्या? वे तो इतने भोले हैं कि जब देश में दल–बदल विरोधी क़ानून लागू हुआ, तो उन्हें लगा था कि इससे हमारे नेता मौसमी परिंदों की तरह अपना ठिकाना नहीं बदल पाएंगे, उनकी उड़ान पर शिकंजा कस जाएगा और उनकी उड़ने की शक्ति इतनी क्षीण हो जाएगी कि वे एक डाल से दूसरी डाल पर आज़ादी के साथ नहीं जा सकेंगे. लेकिन ये परिंदे अब इतने भी नादान नहीं थे कि अपने बनाए हुए जाल (क़ानून) में खुद ही उलझ जाएं और कोई सिरफिरा यह आवाज़ कसे कि लो आप अपने दाम (जाल) में सय्याद (शिकारी) आ गया.

राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ या दूसरे शब्दों में कहें, तो राजनीति का ज्ञान बघारने वाले यह मानते हैं कि राजनीति की खिचड़ी इसलिए पकती है, क्योंकि सब कुछ सबके लिए बराबर नहीं है, यानि हर किसी की हर वस्तु में समान हिस्सेदारी नहीं हो सकती. वे यह भी देखते हैं कि कौन, कब, कैसे और क्या प्राप्त करता है. राजनीति की खिचड़ी बनाने वाले एक वरिष्ठ बावर्ची ने यहां तक कह डाला है कि यह एक कला है, लोगों को ठगने की. अर्थात जो जितना बड़ा ठग होगा, उसकी खिचड़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी. इन सभी राजनीतिज्ञों के कथन और क्रियाकलाप में जो समानता है, वह है अवसर को सुअवसर बनाने का. इस हुनर को नेताओं ने विद्वानों से सीखा या विद्वानों ने नेताओं से, यह शोध का विषय है. लेकिन यहां यह कहने की कदापि ज़रूरत नहीं है कि अवसर को सुअवसर में बदलने की सीख जनता को किससे लेनी चाहिए, क्योंकि जनता समझदार है.

ओफ्फोह! बात कहां से शरू हुई थी और कहां पहुंच गई? हम बात कर रहे थे दल–बदल विरोधी क़ानून की और बात राजनीतिक खिचड़ी तक पहुंच गई (ज़िक्र जब छिड़ गया कयामत का/बात पहुंची तेरी जवानी तक). अब क्या करें भैय्या हैं ही अजीब, सब कुछ उल्टा–पुल्टा. इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आती कि जब चुनाव का मौसम आता है, तो उसमें ऐसा होना कोई अप्राकृतिक बात नहीं है. इस मौसम में हर शख्स यह कहते–कहते कि मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं, ताल ठोक कर अखाड़े में दो–दो हाथ करने के लिए उतर जाता है. फिर गणित की अलग–अलग विद्याओं का इस्तेमाल करके एक–दूसरे को पटखनी देने की होड़ सी लग जाती है. कोई ज्यामिति का सूत्र आजमाता है, तो कोई अंकगणित का. कहने का मतलब यह कि जितने मुंह, उतनी बातें. मुझे तो भैय्या की वजह से मैदान में कूदना पड़ा, वरना मैं तो, तौबा–तौबा... ■

–शफीक आलम

feedback@chauthiduniya.com

तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा
चोट दिल पे वो खाई
मज़ा आ गया...

दुनियाभर में रश्क-ए-क़मर की धूम

रश्क-ए-क़मर... पर दुनिया का रक्स

प्रवीण कुमार

feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड में अब लगता है अच्छे गानों का अकाल पड़ गया है. अब पहले जैसे सदाबहार गाने नहीं बनते, जिन्हें लोग लम्बे समय तक याद रख सकें. आजकल बॉलीवुड में नया ट्रेंड चल रहा है, पुराने गानों को रिमिक्स करके शोर-शराबे के साथ नए वर्जन में तैयार करने का. ये गाने कुछ ही दिन लोगों की जुबान पर रहते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से एक ऐसा गीत वायरल हुआ, जो है तो काफी पुराना, लेकिन आज भी लोग इस पर रक्स (नाच रहे है) कर रहे हैं. आपको याद होगा कि इस साल मार्च के महीने में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चलती कार में एक लड़की *रश्क–ए–क़मर* गाने पर डांस कर रही है. इस वीडियो को तो पहले गुरमेहर कौर से जोड़ा गया, जिसके इस बयान के बाद विवाद हो गया था कि मेरे पापा को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है. हालांकि बाद में ये वीडियो इस मुद्दे से इतर *रश्क–ए– क़मर* गीत को लेकर प्रसिद्ध हो गया.

रश्क–ए– क़मर आज भी करोड़ों लोगों की जुबां पर कायम है. यह गीत इस साल पहली बार किसी फिल्म का हिस्सा बना है. मिलन लूथरिया ने अपनी फिल्म *बादशाहो* में अजय देवगन और इलियाना डीक्रूज पर रोमांटिक अंदाज में इस गाने को फिल्माया, जिसके बाद यह करोड़ो लोगों के दिलों में उतर गया है. वैसे तो आज यह गीत करोड़ों लोगों की ज़ुबां पर है, लेकिन शायद ही बहुत लोगों को *रश्क–ए– क़मर* का मतलब पता होगा. दरअसल, रश्क का मतलब होता है ईर्ष्या और चांद को अरबी में क़मर कहते हैं. इस पूरे वाक्या यानि रश्क–ए– क़मर का मतलब होता है, जिससे चांद भी ईर्ष्या करने लगे ऐसी ख़ूबसूरती.

आपको बता दें कि रश्क–ए– क़मर, पाकिस्तानी शायर फ़ना बुलंदशहरी की रचना है. इसे पाकिस्तानी सूफ़ी गायक नूसरत फ़तेह अली खान ने पहली बार साल 1988 में संगीतबद्ध किया और अपनी आवाज़ दी. उस समय यह गाना दुनियाभर में काफी प्रसिद्ध हुआ था. उसके बाद इसे कई लोगों ने गाया. इस गाने की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान के साथ–साथ हिंदुस्तान में भी इसे ख़ूब प्यार मिला. हाल में वायरल होने के बाद भी कई गायकों ने इसे अपने अंदाज में गाया है. आइए जानते हैं दुनियाभर के उन गायकों के बारे में जिनके द्वारा अलग–अलग अंदाज में गाया गया *रश्क–ए– क़मर* गाना यू–ट्यूब और सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है.

रबी पीरज़ादा
(Rabi Peerzada)

रबी पीरज़ादा दिखने में जितनी सुंदर हैं, उतनी ही ख़ूबसूरत उनकी आवाज़ भी है. वे फिल्म अभिनेत्री और पॉप सिंगर हैं. अपनी गायिकी के जरिए वो लाखों लोगों को अपना दिवाना बना चुकी हैं. उनका जन्म 3 फरवरी 1991 को ब्लोचिस्तान (पाकिस्तान) के क्वेटा में हुआ था. वे पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी मेजर हुमायूं पीरज़ादा की बेटी है. *रश्क– ए–क़मर* को उन्होंने पॉप स्टाइल में बहुत ख़ूबसूरती से गाया है. ■

https://www.youtube.com/watch?v=srzI9kAkzN8

नेहा कक्कड़
(Neha Kakkar)

गायिकी की दुनिया में नेहा कक्कड़ आज एक जाना–पहचाना नाम है. वे सोनू कक्कड़ की छोटी बहन हैं. नेहा बॉलीवुड इंड्रस्टी में सक्रिय हैं. उन्होंने प्यारी रिया के साथ मिलकर ज़ी चैनल पर सारेगामापा लिटिल चैंप्स में जब *रश्क– ए– क़मर* गाया तो सभी लोग देखते रह गए. आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहा कक्कड़ द्वारा टीवी शो में गाया गया *रश्क– ए– क़मर* फिल्म बादशाहों के बाद यू–ट्यूब पर सबसे ज्यादा (5 करोड़ से ज्यादा) बार देखा जाने वाला वीडियो है. इसके अलावा नेहा ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई गाने गाए हैं. नेहा के हिट गानों में *काला चश्मा, चलती है क्या 9 से 12, बद्री की दुल्हनिया, आ तो सही, माही वे, कर गई चुल्ल* आदि शामिल हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=SqOq9wjS9kc

रोजलीन साहू
(Rojalin Sahu)

रोजलीन साहू गायिकी की दुनिया का एक ऐसा नाम है, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा. वे भुवनेश्वर की रहने वाली हैं. रोजलीन द्वारा गाए गए *रश्क–ए– क़मर का वीडियो* यू–ट्यूब पर खूब वायरल हुआ. इस गाने को गाते वक्त रोजलीन और उनकी अवाज़ इतनी ख़ूबसूरत लग रही है कि लोग इसे देखना और सुनना खूब पसंद कर रहें हैं. आपको बता दें कि रोजलीन सोनी और ज़ी चैनल पर इंडियन आइडल और सा रे गा मा पा जैसे टीवी शो में भाग ले चुकी हैं. अब भी वे गीत–संगीत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और शो में हिस्सा लेती हैं. अपनी गायिकी के कारण वे अपने फैन्स के बीच लोकप्रिय हैं. सोशल मीडिया पर रोजलीन के अच्छे–ख़ासे फॉलोवर्स हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=sj4onfXC-6Y

फ़ादिया शबोरोज़
(Fadia Shaboroz)

मूल रूप से इस्लामाबाद की रहने वाली फ़ादिया शबोरोज़ दिखने में जितनी ख़ूबसूरत हैं, उनकी गायिकी का अंदाज भी उतना ही अच्छा है. उन्होंने भी रश्क –ए– क़मर गीत गाया है. उनके द्वारा गाए गए इस गीत को खूब सराहा जा रहा है. यू–ट्यूब पर उनके इस गीत को करोड़ों लोगों ने देखा है. ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ादिया उर्दू, पंजाबी, पॉप, क्लासिकल, गज़ल और सूफ़ी गायिका भी है. वे अभिनय और मॉडलिंग भी करती हैं. इतना ही नहीं फ़ादिया शबोरोज़ लेखिका भी हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=IkO8dj3e3jA

बाबा सहगल
(Baba Sehgal)

बाबा सहगल ने पॉप और पंजाबी गानों के जरिए 1990 में गीत–संगीत की दुनिया में कदम रखा. वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. बाबा सहगल सिंगर होने के साथ अभिनेता भी हैं. उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई गाने अलग–अलग तरीके से गाए हैं. शायद यही कारण है कि उन्होंने *रश्क–ए–क़मर* को भी दूसरों से अलग हटकर गाने के बारे में साचा. उन्होंने घर बैठकर ही एक तबले के जरिए यह गाना गाकर यू–ट्यूब पर अपलोड किया. सहगल के इस वीडियो को भी ख़ूब पसंद किया जा रहा है.■

https://www.youtube.com/watch?v=fMqz-osRHdE

तुलसी कुमार
(Tulsi Kumar)

तुलसी कुमार का पूरा नाम तुलसी कुमार दुआ है. वे प्रसिद्ध गायक स्व. गुलशन कुमार दुआ की बेटी हैं. तुलसी भी अपने पिता की तरह बॉलीवुड में गायिका हैं, साथ ही वे अभिनेत्री भी हैं. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म *बादशाहों* के लिए मशहूर गीत *रश्क –ए– क़मर* गाया है. उनके गाए इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है. चूंकि पहले से ही तुलसी की अच्छी फैन फॉलोइंग है, इसलिए भी इस हिट गाने के जरिए उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी.■

https://www.youtube.com/watch?v=2zGrzpLSkVw

नसीबो लाल
(Naseebo Lal)

नसीबो लाल का जन्म 1970 में पाकिस्तान में हुआ था. वे पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर हैं. नसीबो लाल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर आर्टिस्ट कोक स्टूडियो पाकिस्तान (सीजन 9)से की थी. उन्होंने पंजाबी, उर्दू और मारवाड़ी भाषाओं में कई गाने गाए हैं. उन्होंने भी रश्क –ए– क़मर गाना गाया है. एक एलबम में जुनैद असगर के साथ मिलकर नसीबो लाल द्वारा गाए गए इस गीत को लोगों ने खूब पसंद किया. ■

https://www.youtube.com/watch?v=kzthOOv9pNQ

सोनू कक्कड़
(Sonu Kakar)

20 अक्टूबर 1986 को उत्तराखंड के ऋषिकेश जन्मी सोनू कक्कड़ पेशे से गायिका हैं. साल 2014 में सोनू कक्कड़ का एक एलबम आया था, अरबन मुंडा (Urban Munda). इसमें उन्होंने *रश्क– ए– क़मर* को एक अलग अंदाज में गाया था. उनके द्वारा गाए गए इस गीत को करोड़ों लोगों ने पसंद किया. वे बॉलीवुड में कई फिल्मों के लिए गाने गा चुकी हैं. इसके अलावा कई एलबम वीडियों में भी उन्होंने गीत गाए हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=3kRQW6cvJF0

सारा रज़ा खान
(Sara Raza Khan)

सारा रज़ा खान पाकिस्तानी गायिका हैं. क्लासिकल म्यूज़िक और ग़ज़ल गायिकी में उन्हें महारत हासिल है. सारा रज़ा ने *रश्क– ए– क़मर* को एक ग़ज़ल के रूप में गाया है. उनके द्वारा गाए गए इस गीत को खूब वाहवाही मिली है. उन्होंने अपनी गायिकी की शुरुआत भारतीय टीवी शो *सा रे गा मा पा चैलेंज–2009* से की थी. इस शो में वे एक उभरती हुई गायिका के रूप में सामने आई थीं. सारा रज़ा पाक टीवी की रियलटी शो ब्राइड स्टार की विजेता रह चकी हैं. वे अक्सर रियल्टी शो में भाग लेती रहती हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=jHujt1cDCnw

जुनैद असग़र
(Junaid Asghar)

जुनैद असग़र पाकिस्तान के सियालकोट (पंजाब) के रहने वाले हैं. उन्होंने रश्क–ए–क़मर को अपने एक एलबम के जरिए गाकर दुनियाभर में वाहवाही बटोरी है. यू–ट्यूब पर उनके इस एलबम को 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. जुनैद सॉफ्ट ट्यून्स प्रोडेक्शन में म्यूज़िक प्रोड्यूसर और गीतकार हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=enFNXTXbvKs

पवन सिंह
(Pawan Singh)

पवन सिंह भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं. उन्होंने बड़ी तेजी से भोजपुरी इंड्रस्टी में अपनी पहचान बनाई है. गायक और अभिनेता दोनों रूप में वे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं. *रश्क– ए– क़मर गीत को* पवन सिंह ने भोजपुरी स्टाइल में रिमिक्स करके गाया है. उनके द्वारा गाए गए इस गीत को लाखों लागों ने पसंद किया है. उनका भोजपुरी गीत *लॉलीपोप लागे लू...* इंटरनेशनल लेवल पर हिट है.■

https://www.youtube.com/watch?v=9Dh4HRSqpbY

वृधी सैनी
(Vridhi Saini)

वृधी सैनी एक उभरती हुई गायिका हैं. हाल ही में उन्होंने एनटीवी पर वॉइस किड्स इंडिया शो में भाग लिया था. इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे लाखों लोगों के बीच फेमस हुईं. वृधी ने अपने एक एलबम में *रश्क– ए– क़मर* को पॉप म्यूज़िक स्टाइल में गाया है. उनका यह वीडियो लाखों लागों ने पसंद किया है.■

https://www.youtube.com/watch?v=fRTuob5VOSY

हसीब मुबाशिर
(Haseeb Mubashir)

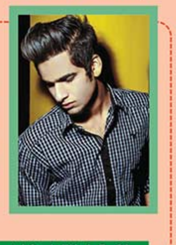

हसीब मुबाशिर ने रश्क –ए–क़मर को स्लो वर्जन में बड़े ही दर्द भरे अंदाज में गाया है. हसीब के इस वीडियो को भी लोगों ने ख़ूब पसंद किया है. हसीब मूल रूप से लाहौर के रहने वाले है. वे हिप–हॉप/पॉप में माहिर हैं. साथ ही वे एक बैंड के मेंबर भी हैं.■

https://www.youtube.com/watch?v=b-EUo1xBoC8